बालाघाट
शनिवार 11 जुलाई 2026
आषाढ कृष्ण 11 विक्रम सम्वत 2083
वर्ष 16, अंक 287
पृष्ठ 12
मूल्य ₹ 7.00

पद्मेश मीडिया समूह का प्रकाशन

बालाघाट एक्सप्रेस

हिन्दी दैनिक

/padmeshmedia /padmeshmedia
epaper.balaghatexpress.in
E-mail: balaghatexpress@gmail.com

सेंसेक्स	–	78,285.07
निफ्टी	–	24,430.35
सोना	–	1,55,044
चांदी	–	2,45,000
डॉलर	–	95.38

खास खबर

अभिनेता राजपाल यादव फिर जाएंगे जेल

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें चेक बाउंस मामले में बढ़ गई हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को इस केस में उनकी सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट ने अभिनेता के आचरण को संदिग्ध बताते हुए अधिकारियों को उन्हें दोबारा जेल भेजने का आदेश दिया। यह पूरा मामला साल 2010 का है, जब राजपाल यादव ने अपनी एक फिल्म के लिए 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। बकाया रकम वापस न करने और चेक बाउंस होने के बाद यह विवाद लंबे समय से अदालत में चल रहा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राजपाल यादव के आचरण पर गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने उनके रवैये को संदिग्ध माना और राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बार-बार आश्वासन देने के बाद भी अभिनेता ने बकाया रकम नहीं चुकाई। इसके बाद हाई कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया कि राजपाल यादव को वापस जेल भेजा जाए। इस फैसले के बाद अभिनेता की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं।

डीटीसी बसों में पिंक टिकट बंद

नई दिल्ली। दिल्ली में 1 अगस्त से दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (डीटीसी) बसों में पिंक टिकट बंद होगी। 1 अगस्त से डीटीसी बसों में पिंक सहेली एनसीएमसी कार्ड के जरिए ही महिलाएं मुफ्त सफर कर पाएंगी। दिल्ली सरकार के मुताबिक अभी तक दिल्ली में 15 लाख पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1 अगस्त के बाद भी अलग-अलग सेंटर पर इनको बनाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। दिल्ली सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 1 अगस्त से डीटीसी की बसों में सफर करने वाली महिलाओं को फ्री बस सफर स्कीम का फायदा उठाते रहने के लिए जरूरी तौर पर पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड रखना और टैप करना होगा। डीटीसी के एक स क ं ल र के मुताबिक, एलिजिबल महिला पैसेंजर को 31 जुलाई तक पेपर पिंक टिकट मिलते रहेंगे।

सुपर टायफून बावी से देश में धीमा पड़ेगा मानसून

नई दिल्ली/भोपाल/जयपुर। देश ने पूरे मानसून को कवर कर लिया है, लेकिन आज सामने आई तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। मौसम विभाग की सैटेलाइट इमेज में मध्य भारत में मानसून ज्यादा एक्टिव है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर तक बादल हैं। दूसरी ओर, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी हिस्सों में बादल कम हैं। यहां आने वाले दिनों में बारिश की कम संभावनाएं दिख रही हैं। देश के मानसून के लिए एक और बुरी खबर है। फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में सुपर टायफून बावी बना है। यह ताइवान और चीन की ओर बढ़ रहा है। इसका असर 3 से 4 हजार किमी दूर बंगाल की खाड़ी तक पड़ रहा है।

कुछ ना कहना

दतिया विधानसभा उपचुनाव

दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद हंगामा

जिला अध्यक्ष समेत पार्षदों का इस्तीफा; ग्वालियर-झांसी हाईवे जाम

दतिया। दतिया विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा ने शुक्रवार को आशुतोष तिवारी को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। इस घोषणा के होते ही शाम को दतिया में हंगामेदार स्थिति पैदा हो गई। हाईवे स्थित भाजपा जिला कार्यालय पर पूर्व गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा समर्थक काफी संख्या में जमा हो गए। उन्होंने हाईवे पर बैठकर धरना दिया। जमकर प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए।

सबसे ज्यादा नाराजगी उन भाजपा नेताओं में देखने को मिली, जिन्हें डॉ मिश्रा को टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन भाजपा आलाकमान ने उन्हें दरकिनार कर मप्र हाउसिंग बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी घोषित कर दिया, जिसके बाद शुक्रवार शाम को दतिया में भाजपा का घमासान सड़कों पर आ गया।

समर्थकों का भारी हंगामा

टिकट के प्रबल दावेदार पूर्व गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों के विरोध के स्वर तेज हो गए। डॉ मिश्रा को पार्टी का टिकट न दिए जाने से नाराज उनके समर्थकों ने जिला कार्यालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी और प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के खिलाफ नारेबाजी कर उन पर तमाम आरोप तक जड़ डाले।

नाराज कार्यकर्ता इतने पर भी नहीं माने और वह दतिया का बाजार बंद करने निकल पड़े, जिसके बाद टाउनहॉल, बड़ा बाजार व किला चौक पर दुकानें बंद हो गई।

दतिया जिलाध्यक्ष ने दिया इस्तीफा

भाजपा से जुड़े डॉ नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों में उनकी टिकट कटने के बाद बहुत गुस्सा है। जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाह ने पद से इस्तीफा दे दिया है। डॉ मिश्रा समर्थक अब आलाकमान से टिकट बदलने की मांग को लेकर दिल्ली कूच करने की तैयारी में हैं। भाजपा की सूची जारी होते ही उसमें अपने नेता का टिकट कटने से नाराज कार्यकर्ताओं का कहना था कि वह आर या पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है।

आशुतोष को मिला टिकट

भोपाल । मध्यप्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर भाजपा ने आशुतोष तिवारी को टिकट देकर एक बार फिर सभी को चौका दिया है। अभी तक भाजपा की और से पूर्व मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा का प्रबल दावेदार माना जा रहा था यहां तक कि उन्होंने नामांकन फार्म भी खरीद लिया था कई राजनीति पंडित आगामी 13 जुलाई को उनके द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने की बात भी कर रहे थे । लेकिन शुक्रवार शाम को पार्टी आलाकमान ने आशुतोष तिवारी के नाम का घोषणा कर सभी को चौका दिया है।

कौन है आशुतोष तिवारी

संघ की पृष्ठ भूमि से संबंध रखने वाले आशुतोष तिवारी काफी सरल स्वाभाव के व्यक्ति है वह पूर्व में सागर संभाग के संभागीय संगठन मंत्री रह चुके है। बाद में संभागीय संगठन मंत्री का पद समाप्त होने पर उन्हें मध्यप्रदेश गृह निर्माण और अधोसरंचना मंडल का अध्यक्ष(केबिनेट मंत्री दर्जा) बनाया गया था। वर्तमानमें आशुतोष तिवारी प्रदेश भाजपा संगठन में सभी मोर्चा के प्रभारी का दायित्व निभा रहे है। आशुतोष तिवारी ने 2023 में सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का टिकट मांगा था, लेकिन यह टिकट प्रदीप अग्रवाल को दिया गया।

नरोत्तम की मेहनत पर फिरा पानी

उपचुनाव की घोषणा होने के बाद पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने चुनावी मैदान संभाल लिया था। आमसभा के जरिए वे लोगों से जुड़ रहे हैं। अब तक वे दो सभा कर चुके थे। इनमें गलतियों पर माफी भी मांगी थी।

स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, सबसे कम उम्र में 300 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनीं

नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना ने महिला क्रिकेट में एक नया इतिहास रच दिया है। लंदन के प्रतिष्ठित लॉर्ड्स मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के साथ उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का 300वां मुकाबला खेला। इसी उपलब्धि के साथ वह सबसे कम उम्र में 300 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। 29 वर्षीय स्मृति मंधाना ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि ऐसे मैदान पर हासिल की, जिसे क्रिकेट का सबसे प्रतिष्ठित मैदान माना जाता है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 300वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के लिए इससे बेहतर मंच नहीं हो सकता था। उन्होंने इस उपलब्धि को अपने परिवार, साथियों, प्रशिक्षकों और प्रशंसकों के समर्थन का परिणाम बताया। स्मृति मंधाना भारतीय महिला क्रिकेट की सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में गिनी जाती हैं। उन्होंने अपने करियर में टेस्ट, एकदिवसीय और टी-20 तीनों प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन करते हुए कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। 300 अंतरराष्ट्रीय मैचों का आंकड़ा छूने वाली वह भारत की चुनिंदा महिला क्रिकेटरों में भी शामिल हो गई हैं। इस ऐतिहासिक टेस्ट मैच में भी स्मृति ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और अपने अनुभव का परिचय देते हुए टीम की पारी को मजबूती दी।

किसी व्यक्ति को गुंडा घोषित करने के लिए उसका आदतन अपराधी होना जरुरी

-हाईकोर्ट ने कहा- दो मुकदमों के आधार पर किसी को गुंडा घोषित नहीं कर सकते

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक अहम फैसले में कहा कि केवल दो आपराधिक मुकदमों में नाम आने के आधार पर किसी व्यक्ति को यूपी गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत गुंडा घोषित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने साफ किया कि किसी व्यक्ति को गुंडा घोषित करने के लिए उसका आदतन अपराधी होना जरुरी है। एक या दो मामलों में संलिप्तता मात्र से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वह व्यक्ति समाज के लिए स्थायी खतरा है। यह फैसला न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने राहुल उर्फ राहुल सरोज की याचिका पर दिया। कोर्ट ने इस आधार पर अमेठी के अपर जिलाधिकारी द्वारा याची को 25 फरवरी को गुंडा घोषित करने के आदेश और अयोध्या मंडल के आयुक्त द्वारा 6 मई को पारित अपीलीय आदेश को निरस्त कर दिया। याचिकाकर्ता को 2021 और 2025 में दर्ज दो अलग-अलग आपराधिक मामलों के आधार पर गुंडा घोषित किया गया था। राज्य सरकार ने दो बीट सूचना रिपोर्ट और एक निषेधात्मक रिपोर्ट का भी सहारा लिया था। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि इन परिस्थितियों से यह सिद्ध नहीं होता कि याचिकाकर्ता आदतन अपराधी है या उसकी गतिविधियों से लोक व्यवस्था को वास्तविक खतरा है। पीठ ने कहा कि आदतन शब्द का अर्थ बार-बार, लगातार और समान प्रकृति के अपराध करना है।

करूर भगदड़ पीड़ितों को सरकारी नौकरी, लेकिन हाईकोर्ट का बड़ा कानूनी पेंच

चेन्नई। मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को पिछले साल करूर भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों को सरकारी नौकरी देने की मंजूरी दे दी है। हालांकि, यह मंजूरी एक बड़े कानूनी पेंच के साथ आई है, ये नियुक्तियां अस्थायी होंगी और न्यायिक समीक्षा के नतीजे पर निर्भर करेंगी।

मुदुरै बेंच के जस्टिस सीवी कार्तिकेयन और आर शक्तिवेल की बेंच ने कहा कि सरकार के नीतिगत फैसले में कोर्ट का दखल देना बहुत संकीर्ण सोच होगी। इस बात को ध्यान में रखकर कोर्ट ने राज्य सरकार को मृतकों के परिवारों को नियुक्ति पत्र सौंपने के लिए निर्धारित सार्वजनिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी। हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि ये नौकरियां अस्थायी आधार पर होंगी और पूरी तरह से न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगी। कोर्ट का इरादा इस मामले की सुनवाई महीने के आखिर तक, यानी नौकरी पाने वालों को पहली सैलरी मिलने से पहले, पूरी करने का है। यह फैसला मदुरै के वकील थीरन थिरुमुरुगन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिन्होंने पिछले साल सितंबर में हुई करूर भगदड़ में मारे गए 41 लोगों के परिवारों को सरकारी नौकरी देने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि ऐसी त्रासदियों में पीड़ितों के परिवारों को स्थायी सरकारी नौकरी देने के लिए कोई एक जैसी नीति नहीं है। उनका मानना था कि एक मामले में नौकरी देने से संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत समानता और समान अवसर के संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन हो सकता है, क्योंकि हर योग्य नागरिक को सरकारी नौकरी के लिए मुकाबला करने का संवैधानिक अधिकार है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसी नियुक्तियों के लिए स्पष्ट नीति का अभाव सरकार के फैसले को मनमाना और असंवैधानिक बनाता है, खासकर जब सर्वोच्च न्यायालय में त्रासदी से संबंधित मामले लंबित हों।

दो सौ साल पुरानी जोधपुरी मोजड़ी को मिला जीआई टैग

नई दिल्ली । राजस्थान की प्रसिद्ध पारंपरिक जोधपुरी मोजड़ी को भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग मिल गया है। करीब दो सौ वर्ष पुरानी इस हस्तनिर्मित पारंपरिक पादुका को जीआई टैग मिलने से न केवल इसकी विशिष्ट पहचान को कानूनी संरक्षण मिला है, बल्कि स्थानीय कारीगरों और हस्तशिल्प उद्योग को भी बड़ा प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में जोधपुरी मोजड़ी की मांग बढ़ेगी।

जोधपुरी मोजड़ी अपनी बारीक कारीगरी, आकर्षक कढ़ाई, चमड़े की उत्कृष्ट गुणवत्ता और पारंपरिक राजस्थानी डिजाइन के लिए देश-विदेश में प्रसिद्ध है। इसे पूरी तरह हाथ से तैयार किया जाता है और प्रत्येक जोड़ी को बनाने में कई दिन लग जाते हैं। वर्षों से यह राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और शिल्प परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। जीआई टैग मिलने के बाद अब इसकी नकल या गलत नाम से बिक्री पर कानूनी रोक लगाने में भी मदद मिलेगी।

हस्तशिल्प विशेषज्ञों का कहना है कि यह उपलब्धि स्थानीय कारीगरों के लिए आर्थिक रूप से भी लाभकारी साबित होगी। इससे उनकी पारंपरिक कला को नई पहचान मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही युवा पीढ़ी का रुझान भी इस पारंपरिक शिल्प की ओर बढ़ने की संभावना है। गौरतलब है कि जीआई टैग किसी उत्पाद की उस विशेष पहचान को मान्यता देता है, जो उसकी भौगोलिक उत्पत्ति और पारंपरिक निर्माण शैली से जुड़ी होती है।

ई-20 पेट्रोल पर छिड़ी नई बहस- गडकरी ने माना- माइलेज में आती है कमी

नई दिल्ली । देशभर में लागू ई-20 पेट्रोल को लेकर नई बहस तेज हो गई है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के हालिया बयानों के बाद आम लोगों के बीच ई20 के प्रभावों पर चर्चा बढ़ गई है। हालांकि मोदी सरकार का स्पष्ट कहना है कि ई20 से इंजन को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन माइलेज में मामूली कमी आना स्वाभाविक है।

ई-20 पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल का मिश्रण होता है, इस देशभर में लागू किया गया है। मोदी सरकार का तर्क है कि इससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटेगी, किसानों की आय बढ़ेगी और प्रदूषण कम होगा।

चार जुलाई को पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ई-20 को पूरी तरह सफल बताकर कहा था कि करोड़ों दोपहिया और लाखों कारें इसका उपयोग कर रही हैं, और इसके कारण किसी प्रकार की तकनीकी समस्या सामने नहीं आई है। उन्होंने बताया कि सरकार अब ई-25 मिश्रण पर परीक्षण कर रही है। वहीं, शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री गडकरी ने स्वीकार किया कि ई20 पेट्रोल के उपयोग से माइलेज पर कुछ असर पड़ सकता है, क्योंकि इथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से कम होती है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अंतर सामान्य परिस्थितियों में बहुत अधिक नहीं होता और इंजन खराब होने का दावा तथ्यों पर आधारित नहीं है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने इसतरह के किसी भी प्रमाण को सामने लाने की चुनौती दी, जिससे यह साबित हो सके कि वाहन केवल ई20 के कारण खराब हुआ हो।

विशेषज्ञों के अनुसार, इथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में ऊर्जा कम होने के कारण माइलेज में करीब 3 से 3.5 प्रतिशत तक कमी आना संभव है। दूसरी ओर, पुरानी ई10 मानक वाली गाड़ियों में रबर सील, फ्यूल पाइप और अन्य पुर्जों पर लंबे समय में प्रभाव पड़ने की आशंका को लेकर तकनीकी चर्चाएं जारी हैं।

6 दिन में चार्जशीट, 40 दिन में फैसला...

मासूम आरव के कातिल को मौत की सजा

फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में डेढ़ साल के मासूम आरव की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला जज ने आरोपी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई है। इस सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस ने महज 6 दिन में चार्जशीट दाखिल की, जबकि अदालत ने घटना के सिर्फ 40 दिन के भीतर फैसला सुना दिया।

यह घटना इसी साल 30 मई को फिरोजाबाद के शिकोहाबाद स्थित यादव कॉलोनी में हुई थी। आरोप है कि बदायूं निवासी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक ने डेढ़ साल के मासूम आरव को सड़क पर पटक-पटक कर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया था और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इस जघन्य वारदात ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था। इस मामले की सुनवाई तेजी से पूरी की गई। गुरुवार को जिला जज ने अंतिम सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया था। इसके बाद शुक्रवार दोपहर करीब ढाई बजे जिला एवं सत्र न्यायालय, फिरोजाबाद में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरोपी को पेश किया गया। अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को सजा-ए-मौत सुनाई। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई भी बेहद तेज रही। शासकीय अधिवक्ता राजीव प्रियदर्शी के अनुसार, पुलिस ने घटना के केवल 6 दिन के भीतर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसी वजह से मुकदमे की सुनवाई भी तेजी से आगे बढ़ी। कम समय में जांच पूरी कर अदालत के सामने मजबूत साक्ष्य पेश किए गए।

गर्भावस्था के चलते रुकी महिला आईपीएस की ट्रेनिंग

सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से किया इनकार

नई दिल्ली। गर्भावस्था की वजह से ट्रेनिंग से बाहर हुई मध्य प्रदेश कैडर की आईपीएस अधिकारी उर्वशी सेंगर को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने चल रही ट्रेनिंग में उन्हें शामिल कराने का आदेश देने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने केंद्र के इस बयान को रिकॉर्ड पर लिया कि इससे उनकी वरिष्ठता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा ट्रेनिंग का नौ हफ्ते का कार्यक्रम चल रहा है और इसमें से तीन हफ्ते पूरे हो चुके हैं। ऐसे में अब अधिकारी पूरी ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगी। इसी वजह से अदालत ने फिलहाल उन्हें ट्रेनिंग में शामिल करने का आदेश नहीं दिया। साथ ही ट्रिब्यूनल से कहा कि वह इस मामले की मूल याचिका पर मेरिट के आधार पर सुनवाई करे।

सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र से यह भी पूछा कि अगर कोई महिला अधिकारी मेडिकल तौर पर फिट है और ट्रेनिंग के लिए तैयार है, तो उसे मातृत्व लाभ के नाम पर उसके अधिकारों से क्यों रोका जाए। कोर्ट ने इस सवाल पर केंद्र का पक्ष भी सुना, लेकिन अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। यह मामला मध्य प्रदेश कैडर की 2023 बैच की आईपीएस अधिकारी उर्वशी सेंगर से जुड़ा है। ट्रेनिंग के दौरान वह गर्भवती हो गई थीं। बच्चे के जन्म के बाद मेडिकल फिटनेस हासिल करने पर उन्होंने जून में शुरू हुए फेज-टू प्रशिक्षण में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। लेकिन अकादमी ने 1993 के गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन का हवाला देते हुए उनकी मांग स्वीकार नहीं की।1993 के गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन के मुताबिक, अगर कोई महिला आईपीएस प्रोबेशनर ट्रेनिंग के दौरान गर्भवती हो जाती है, तो उसकी ट्रेनिंग रोक दी जाती है। उसे प्रसव के एक साल बाद दोबारा प्रशिक्षण में शामिल होने की अनुमति मिलती है। उर्वशी सेंगर ने इसी नियम को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह नीति महिलाओं को राहत देने के लिए बनाई गई थी, न कि उन्हें अयोग्य ठहराने के लिए।

सुप्रीम कोर्ट में वकील ने सीजेआई को अपशब्द कहे

कागज हवा में उछालते हुए कहा...दे देना उस सीजेआई को...।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को एक याचिकाकर्ता वकील ने सुनवाई के दौरान अभद्र व्यवहार किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई चल रही थी। याचिका वकील ने ही लगाई थी। सुनवाई की शुरुआत से ही वकील ने बेहद आक्रामक रुख अपना रखा था। कुछ ही देर में उसने कोर्ट में गाली देना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, केस से जुड़े कागज हवा में उछालते हुए कहा... दे देना उस *** सीजेआई को....।

याचिकाकर्ता वकील के इस व्यवहार से कोर्ट रूम में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। लेकिन तुरंत ही सिक्योरिटी ने उसे कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया। मामले की सुनवाई जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच कर रही थी। हालांकि कोर्ट ने वकील के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई न करने का फैसला किया, लेकिन उसकी याचिका खारिज कर दी।

हंगामे के बाद जज बोले- हमें उसके साथ सिंपैथी है

सुनवाई शुरू होते ही याचिकाकर्ता ने कहा, न्यायिक अधिकारी महोदय, मैं आपको आदेश देता हूं कि आप लखनऊ के एसीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दें। इस पर जस्टिस केवी विश्वनाथन ने हैरानी जताते हुए पूछा, आप मुझे आदेश दे रहे हैं? इसके जवाब में याचिकाकर्ता ने कहा, मेरी तरफ से बस इतना ही। सब कुछ रिकॉर्ड पर है। इसके बाद उसने केस की फाइल हवा में फेंक दी और गाली-गलौज करने लगा। इसके तुरंत बाद सुरक्षा कर्मी सक्रिय हुए और उसे कोर्टरूम से बाहर ले गए। हंगामे के बाद जस्टिस केवी विश्वनाथन ने कहा- वह बहुत परेशान है, यह सब हताशा है। हमें उसके लिए केवल सहानुभूति है।

कोर्ट ने नहीं लिया एक्शन

हंगामे के बावजूद, बेंच ने याचिकाकर्ता के खिलाफ अदालत की अवमानना या कोई दूसरी कार्रवाई न करने का फैसला किया। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा, हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। जहां तक मामले के गुण-दोष की बात है, हमने रिकॉर्ड देख लिए हैं और हमें विवादित आदेश में दखल देने का कोई ठोस आधार नहीं मिला।

जान जोखिम में डालकर जर्जर स्कूल भवन में पढ़ाई कर रहे बच्चे

अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे वनांचल गांवो के स्कूल, कभी भी हो सकते हैं धराशाही, ग्रामीणों ने जताया आक्रोश, नया स्कूल भवन बनाने की करी मांग, सुनवाई ना होने पर ,जनप्रतिनिधियों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी

सिटी रिपोर्टर।
पद्मेश न्यूज। बालाघाट।

एक ओर शासन प्रशासन द्वारा प्रतिवर्ष, स्कूलों के उन्नयन के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने की दावा किया जाता है।तो वहीं दूसरी ओर सरकार, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को तमाम तरह की सुविधा देने, प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर स्कूल भवन का निर्माण करने और एक अच्छे माहौल में शिक्षा देकर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के दावे करती है लेकिन सरकार के इन दावों की हकीकत कुछ और ही है। और आज भी जिले के कई सरकारी स्कूल है जो अपनी बदनसीबी पर आंसू बहते नजर आ रहे हैं। इसे जिले के सरकारी स्कूलों की उपेक्षा कहे या फिर कुछ और, की लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी सरकारी स्कूलों की हालत में सुधार नही आ रहा है और वहां पढ़ने वाले बच्चों को अपनी जान जोखीम में डालकर पढ़ाई करना पड़ रहा है। जहां वर्षो से खंडहर हुए स्कूल भवनों में कक्षाएं लगाने के चलते बरसात में स्कूल की छत से पानी टपकता है। तो वही जर्जर हो चुकी स्कूल की इमारत के कभी भी धराशाई होने का डर बना रहता है।बावजूद इसके भी वहां जर्जर भवन में स्कूलों का संचालन किया जा रहा है जहां सबसे ज्यादा अव्यवस्थाएं जिले के पिछड़े क्षेत्रों में देखने को अक्सर मिलती रहती है।खंडहर स्कूलों का ताजा मामला जिले के जनपद शिक्षा केन्द्र बिरसा के ग्राम पीपरटोला का है।जहां शासन प्रशासन की उदासीनता के चलते सरकारी स्कूल जर्जर हो चुका हैं और इस जर्जर हो चुके स्कूल भवन में कक्षाएं संचालित की जा रही है ।जहा अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चे और शिक्षक पठन-पाठन का कार्य करने के लिए मजबूर है। जिस पर अपनी नाराजगी जताते हुए शिक्षकों और स्थानीय ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों ने स्कूल भवन का पुन: निर्माण कराया जाने की मांग की है।वही मांग पूरी ना होने पर उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है।

दशको पुराना बताया जा रहा जर्जर स्कूल

बताया जा रहा है कि बिरसा तहसील अंतर्गत वनांचल गांव पिपरटोला में स्थित शासकीय प्राथमिक शाला कई दशक पुराना है।जो जर्जर हालत में पहुंच गया हैं। ऐसे में यहां रोज जान जोखिम में डालकर बच्चों की पाठशाला लगाई जा रही है।स्कूल के लिए

नया भवन बनवाने पंचायत के सरपंचों द्वारा प्रस्ताव पारित कर सर्व शिक्षा अभियान के अधिकारियों को कई बार पत्र लिखा गया है, लेकिन इतने सालों में जिम्मेदारों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। साथ ही पालक शिक्षक संघ ने भी इस प्रयास को आगे बढ़ाया। बावजूद इसके कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। नतीजन रोज जर्जर भवन में कक्षा लगी रहने से शिक्षक व बच्चे दोनों दहशत में रहते हैं।

ना हो रही मरम्मत ना स्कूल भवन का हो रहा पुन: निर्माण

जनपद शिक्षा केन्द्र बिरसा के ग्राम पीपर टोला स्थित प्राथमिक शाला भवन इतना जर्जर हो चुका है कि यह किसी भी समय धाराशायी हो सकता है।बताया गया कि सरकार द्वारा गांव-गांव में शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल खोलने का दावा किया जा रहा है, लेकिन पुराने भवनों को न तो नए बनवाए जा रहे है और ना ही पुराने की मरम्मत करवा रहे है। हालांकि इसकी शिकायत शिक्षकों व सरपंच, पालक शिक्षक संघ के जरिए सर्व शिक्षा अभियान के अधिकारी से लेकर कलेक्टर, विधायक, सांसद सहित अन्य जनप्रतिनिधियों से की गई। इसके बाद भी पुराने जर्जर स्कूलों को लेकर कोई सामने नहीं आ रहा है। यही कारण है कि जर्जर स्कूलों में बच्चों की कक्षाएं शिक्षकों को लगानी पड़ती है।

बच्चो की पढाई हो रही प्रभावित

शिक्षा की गुणवत्ता और बेहतर शैक्षणिक सुविधाओं के दावों के बीच जनपद शिक्षा केन्द्र बिरसा के ग्राम पीपर टोला का प्राथमिक शाला भवन,बदहाल शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर पेश कर रहा है। यहां हालात ऐसे हैं कि पहली कक्षा से लेकर पांचवीं कक्षा के बच्चे स्कूल के बरामदे और घर में बैठकर पढ़ने को मजबूर है।जिससे बच्चों की पढ़ाई पर सीधा असर पड़ रहा है। जर्जर भवन को लेकर ग्रामीण अभिभावकों में आक्रोश पनप रहा है, उन्होंने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि चुनाव के समय नेता बड़े बड़े वादे करते हैं,लेकिन समस्या पर ध्यान नहीं देते हैं।

सभी अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है नही हो रही सुनवाई-हेमंत साहू

जनपद पंचायत बिरसा उपाध्यक्ष हेमंत साहू ने बताया कि शाला भवन लंबे समय से जर्जर है इसकी जानकारी बीआरसी,डीईओ सहित अन्य को कई बार पत्राचार के माध्यम से दी गई है।लेकिन इस दिशा में कोई कार्यवाही नही हो रही है।स्कूल भवन कभी भी गिर सकता है।हमारी मांग है कि नया स्कूल भवन बनाना चाहिए ,जब तक नया भवन ना बन जाए तब तक बच्चो को बैठाने की वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। स्कूल में करीब 31 बच्चे हैं वहां बैठकर बच्चों को पढाना खतरे से खाली नहीं है इसीलिए पुन: स्मरण पत्र लिखा जाएगा। उन्होंने बताया कि कई बार पत्राचार किया जा चुका है बावजूद इसके भी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

स्कूल भवन जर्जर है,इसलिए बच्चो को बाहर बैठाकर पढ़ाते है- नरेश

शिक्षक नरेश कुमार नागेश्वर ने बताया कि प्राथमिक शाला का भवन लंबे समय से जर्जर है, बारिश के कारण भवन की स्थिति और खराब हो गई है, सुरक्षा को देखते हुए बच्चों को वहां बैठाना संभव नहीं रहा। जिसके कारण अस्थायी रूप से कुछ बच्चों को बरामदे और कुछ को घर में बैठाकर पढ़ाया जा रहा है।

तो उग्र आंदोलन कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा-गौवतरिया मेरावी

दुरभाष पर की गई चर्चा के दौरान सरपंच श्रीमती गौवतरिया मेरावी ने बताया कि विद्यालय भवन की जर्जर स्थिति की जानकारी कई बार संबंधित अधिकारियों को दी गई, लेकिन अब तक नए भवन के निर्माण की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हुई। उनका कहना है कि यदि जल्द नया भवन नहीं बना तो ग्रामीणों के साथ वे आंदोलन धरना-प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।

सांसद श्रीमती भारती पारधी 11 जुलाई को सिवनी दौरे पर रहेंगी

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। बालाघाट-सिवनी लोकसभा क्षेत्र की सांसद श्रीमती भारती पारधी 11 जुलाई 2026 (शनिवार) को सिवनी जिले के दौरे पर रहेंगी। जारी दौरा कार्यक्रम के अनुसार वे प्रात: 9 बजे बालाघाट से सिवनी के लिए प्रस्थान करेंगी। दौरे के दौरान सांसद श्रीमती पारधी प्रात: 11 बजे भाजपा जिला कार्यालय, सिवनी में आयोजित जिला बैठक में शामिल होंगी। इसके पश्चात दोपहर 1 बजे भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित भाजपा कोर कमेटी की बैठक में भाग लेंगी और संगठनात्मक गतिविधियों एवं आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा करेंगी। निर्धारित कार्यक्रमों के समापन के बाद सांसद श्रीमती भारती पारधी शाम 5 बजे सिवनी से बालाघाट के लिए रवाना होंगी।

मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस का प्रांतिय सम्मेलन १२ जुलाई को

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस का प्रांतिय सम्मेलन १२ जुलाई को बालाघाट में आयोजित किया जा रहा है। जिसमें प्रदेश भर के सभी जिलों के पदाधिकारियों एवं प्रांतिय पदाधिकारियों के आगमन के साथ संगठन के संस्थापक पूर्व सांसद रामेश्वर निखरा का आगमन भी होगा। बालाघाट जिलाध्यक्ष राकेश वर्मा ने बताया कि कई वर्षों बाद बालाघाट में प्रांतिय सम्मेलन का आयोजन होना बालाघाट के शिक्षक साथियों के लिए गौरव की बात है। जिसमें जिले के विधायक गण भी शामिल होंगे। इस अवसर प्रांतिय पदाधिकारियों एवं विधायकों के समक्ष शिक्षकों की समस्याओं में विशेष रूप से ई अटेंडेंस, शिक्षकों को प्रमोशन, पुरानी पेशन, टी ई टी परीक्षा से निजात एवं अन्य बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। श्री वर्मा द्वारा जिले के संगठन के सभी पदाधिकारियों एवं शिक्षक साथियों से अपील की गई है कि होटल शीतल पैलेस बालाघाट में संपन्न होने जा रहे इस सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करें।

In The Court Of Pranesh Kumar Pran,Principal District and Session Judge,Balaghat

Presiding Officer:-प्राणेश कुमार प्राण

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 8 हिन्दु अप्राप्तव्यता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956
प्रकरण क्रमांक (MJC GW/00021/2026)

1. आदिका बनोटे पिता स्व दुर्गेश बनोटे उम्र 09 वर्ष ना.बा. वली मां सोनू बनोटे पति स्व दुर्गेश बनोटे
2. सोनू बनोटे पति स्व दुर्गेश बनोटे उम्र 40 वर्ष दोनों निवासी वार्ड नंबर 32 नर्मदा नगर बालाघाट म.प्र.................**आवेदकगण**

विरूद्ध

1 आम जनता..............................**अनावेदक**

Process Id-608/2026
पेशी तारीख-25/08/2026

(1) **आम जनता पता- आम जनता**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका सोनू बनोटे प्रतिपाल्य अधिनियम 1868 के अंतर्गत स्वयं को पुत्री आदिका बनोटे उम्र 09 वर्ष का संरक्षक एवं प्रतिपाल्य घोषित करने का आवेदन इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।

यह कि आवेदिका ने आदिका बनोटे को अपने और अपने पति स्व0 दुर्गेश बनोटे की संतान होना बताया है। आवेदिका ने उक्त आवेदन में अभिवचनित किया है कि उसे उसकी संरक्षक घोषित किया जावे, जिससे कि वह अपनी बेटी के हिस्से की भूमि मौजा बडगांव, प0ह0नं0 16, रा0नि0मं0 व तहसील किरनापुर जिला बालाघाट में स्थित खसरा नंबर 35/1/3 रकबा 0.133 हेक्टे कृषि मद की भूमि को विक्रय कर सके।

अत: यदि किसी व्यक्ति को आवेदक के अभिभावक / संरक्षक होने संबंधी प्रमाण पत्र जारी किये जाने में कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 25-08-2026 को न्यायालय में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहें। सूचना उपरांत यदि अनुपस्थित रहे तो प्रकरण की सुनवाई एक पक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा।

न्यायाधीश
जिला बालाघाट(म.प्र.)

ऑपरेशन हमदर्द बना बेसहारों का सहारा, जीआरपी ने संभाली मानवता की जिम्मेदारी

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। रेलवे स्टेशन बालाघाट पर बेसहारा, बेघर, वृद्ध एवं असहाय लोगों की मदद के उद्देश्य से ऑपरेशन हमदर्द अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान रेलवे स्टेशन परिसर और आसपास ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है जो बेघर, बेसहारा या भीख मांगकर जीवनयापन कर रहे हैं। जीआरपी द्वारा ऐसे लोगों को

सुरक्षित आश्रय स्थल, रैन बसेरा अथवा वृद्धाश्रम तक पहुंचाया जा रहा है। जिन लोगों का परिवार मौजूद है, उन्हें उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाने की भी व्यवस्था की जा रही है।जिसकी एक झलक शुक्रवार को रेलवे स्टेशन में देखने को मिली।बताया गया कि यह विशेष अभियान पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश तथा रेल पुलिस अधीक्षक जबलपुर सुंदर सिंह कनेश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भावना मरावी एवं उप पुलिस अधीक्षक अंकिता सुलया के मार्गदर्शन में 1 से 31 जुलाई तक संचालित किया जाएगा।

जरूरतमंदो को सम्मानजनक जीवन और सामाजिक सुरक्षा देना अभियान का उद्देश्य

रेल पुलिस का कहना है कि कई मामलों में पारिवारिक विवाद या उपेक्षा के कारण वृद्धजन और अन्य लोग घर छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे मामलों में पुलिस केवल उन्हें परिवार तक पहुंचाने का कार्य ही नहीं कर रही, बल्कि परिवार के सदस्यों को समझाइश देकर उन्हें अपने परिजनों की जिम्मेदारी निभाने के लिए भी प्रेरित कर रही है। अभियान का उद्देश्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि जरूरतमंद लोगों को सम्मानजनक जीवन और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना भी है।

जरूरतमंदों की जीआरपी को दे जानकारी- गढ़पाल

जीआरपी चौकी बालाघाट के प्रधान आरक्षक राकेश गड़पाल ने बताया कि पूरे जुलाई माह तक चलने वाले इस अभियान में आम नागरिकों की सहभागिता भी बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि यदि रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म या आसपास कोई वृद्ध, बीमार, मानसिक रूप से अस्वस्थ, बेसहारा महिला या पुरुष दिखाई दे तो इसकी सूचना तत्काल जीआरपी बालाघाट को दें, ताकि संबंधित व्यक्ति को समय पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके।उन्होंने कहा कि पुलिस और समाज के संयुक्त प्रयास से ही ऐसे जरूरतमंद लोगों को सुरक्षित आश्रय, उपचार और परिवार का सहयोग मिल सकता है। ऑपरेशन हमदर्द इसी मानवीय सोच को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो जरूरतमंद लोगों के जीवन में नई उम्मीद जगा रही है।

गौ-रक्षा और मंदिर संरक्षण के संकल्प के साथ बालाघाट से खाटू श्याम तक साइकिल यात्रा

14 कोठीगढ़ में भजन-आरती, 15 को रवाना होगी यात्रा, रास्ते में लगेंगे 1100 पौधे

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। सनातन धर्म और पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ बालाघाट जिले से राजस्थान स्थित खाटू श्याम बाबा मंदिर तक साइकिल पद यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा का मुख्य उद्देश्य मंदिरों का संरक्षण, गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाना और पर्यावरण को बचाना है।हीरापुर विष्णुधाम में विश्व की सबसे ऊंची 205 फीट हनुमान प्रतिमा निर्माण की संकल्प यात्रा के बाद यह जिले की दूसरी बड़ी धार्मिक पहल है।

14 कोठीगढ़ में होगा शुभारंभ

यात्रा की शुरुआत से एक दिन पहले 14 जुलाई को मां अन्नपूर्णा देवी कोठीगढ़ धाम में विशेष पूजा-अर्चना होगी। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ पौधरोपण किया जाएगा। शाम को मंदिर परिसर में संध्या भजन और महाआरती का आयोजन किया जाएगा। 15 जुलाई की सुबह मंदिर से विधिवत साइकिल यात्रा रवाना होगी।

यह रहेगा यात्रा का मार्ग

वारासिवनी निवासी मुरली चौबे के नेतृत्व में निकलने वाली इस यात्रा में धनलाल बिसेन मोहगांव, रुपचंद महादेव टेकाड़ी रामटेक कान्हादेवी, लकेश कुसराम, गजानंद ग्वालवंशी धारणा बरघाट, संदीप मेश्राम महदोली सहित जिले भर के भक्त शामिल होंगे।यात्रा बालाघाट

जिला मुख्यालय से होते हुए वारासिवनी, रामपायली, मोहगांव और कटंगी पहुंचेगी। इसके बाद सिवनी के रास्ते यह दल राजस्थान की ओर प्रस्थान करेगा। आयोजकों के अनुसार यात्रा को खाटू श्याम पहुंचने में 15 से 20 दिन का समय लगेगा।

रास्ते में लगेंगे 1100 पौधे

यात्रा की एक खास बात यह है कि जहां-जहां यह दल रात्रि विश्राम करेगा, वहां पर्यावरण संरक्षण के तहत पौधरोपण किया जाएगा। पूरे मार्ग में 1100 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है।आयोजकों ने बताया कि गुरु पूर्णिमा के दिन खाटू श्याम मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की जाएगी। इस दौरान गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने, गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने, जिले के प्रत्येक प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार कराने और ग्राम पंचायत व नगर पालिका स्तर पर हर मंदिर में एक सेवादार की नियुक्ति करने की मनोकामना की जाएगी।

कार्यालय ग्राम पंचायत सरंडी जनपद पंचायत वारासिवनी जिला बालाघाट म.प्र

क्रमांक १७/२०२६ दिनांक ०९/०७/२०२६

निविदा

एतद् द्वारा आमजन को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत सरंडी जनपद पंचायत वारासिवनी अंतर्गत वित्तीय वर्ष २०२६-२७ हेतु शासकीय अनुदान १४,१५ वें वित्त आयोग, ५वें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, डीएमएफ , स्वकराधान मद, पंचायत निधी कर व अन्य स्वच्छ भारत अभियान, विधायक निधी, सांसद निधी, परफार्मेंस ग्रांट फंड, पूर्व संचित शेष निधियों एवं पंचायत क्षेत्र में संचालित अन्य समस्त शासकीय अनुदान की योजनाओं तथा केन्द्र सरकार की वीबी जी राम जी योजनांतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु आवश्यक निर्माण सामग्री सीमेंट, लोहा,गिट्टी, मुरम, मिट्टी, तार, खीला,सीमेंट पोल, चैनलिंक फेंसिंग, एलईडी बल्ब ,वायरिंग, पैंट, ब्रश,विरला व्हाईट सहित अन्य समस्त निर्माण सामग्री क्रय एवं मिक्सर मशीन, वाइब्रेटर, ट्रेक्टर ट्राली ,जेसीबी व अन्य मशीनरी किराये पर लिये जाने हेतु दिनांक ११/०७/२०२६ से १८/०७/२०२६ तक मुहरबंद निविदाएँ कार्यालयीन समय में आमंत्रित की जाती है।

टीप-निविदा स्वीकृती के संबंध में अंतिम निर्णय ग्राम पंचायत सरंडी का होगा

विनीत-श्रीमती पूजा गौतम सरपंच ,चाणक्य चौबे
सचिव ग्राम पंचायत सरंडी जनपद पंचायत वारासिवनी

कलेक्टर ने ली राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक-लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के दिए निर्देश

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। कलेक्टर मृणाल मीना ने शुक्रवार 10 जुलाई को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री जी.एस. धुर्वे, संयुक्त कलेक्टर एम.आर. कोल, डिप्टी कलेक्टर प्रदीप कौरव, एसडीएम गोपाल सोनी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं जिले के सभी एसडीएम व तहसीलदार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुडे रहें। बैठक में कलेक्टर श्री मीना ने फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति की तहसीलवार समीक्षा की। समीक्षा के दौरान लांजी तहसील की प्रगति सबसे कम पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की तथा एसडीएम लांजी एवं तहसीलदार को इसमें शीघ्र प्रगति लाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने सभी एसडीएम व तहसीलदारों को निर्देशित किया फार्मर रजिस्ट्री के कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए। फार्मर रजिस्ट्री के कार्य को मिशन मोड में करना सुनिश्चित करें तथा शीघ्र ही फार्मर रजिस्ट्री के कार्य को संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिये गए। इसके साथ ही उन्होंने सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्रों के गांवों में मुनादी कराकर किसानों को कीटनाशकों के सुरक्षित एवं सावधानीपूर्वक उपयोग के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिये। बैठक में नजूल प्रकरणों एवं स्थायी पट्टों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही राजस्व वसूली अभियान में तेजी लाने, नियमित वसूली करने तथा वसूली के पश्चात उसकी ऑनलाइन प्रविष्टि (एंट्री) समय पर दर्ज करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने 500 दिनों से अधिक समय से लंबित 18 सीएम हेल्पलाइन शिकायतों तथा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में उनका निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री मीना ने लोक सेवा गारण्टी व सीएम हेल्पलाईन के लंबित प्रकरणों के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग शिकायतों एवं राजस्व प्रकरणों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करें, ताकि आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये कि सीएम हेल्पलाइन व अन्य राजस्व विभागों के प्रकरणों को लंबित न रखे इसका त्वरित व संतुष्टिपूर्वक निराकरण करना सुनिश्चित करें।

बारबेड वायर (कांटेदार तार)
एवं चेन लिंक जाली
उचित दाम पर उपलब्ध
लघु उद्योग निगम भोपाल से संबद्ध

निर्माता
तिरूपति इंजीनियरिंग वर्क्स
मयूर टॉकिज के सामने हनुमान चौक, बालाघाट
फोन:- 07632-243531
मो:- 8989976858, 9425139998

बालाघाट
शनिवार 11 जुलाई 2026

बालाघाट सिटी न्यूज़

3
पद्मेश न्यूज
बालाघाट एक्सप्रेस

/padmeshmedia /padmeshmedia epaper.balaghatexpress.in E-mail: balaghatexpress@gmail.com

न्यूज गैलरी

वन स्टॉप सेंटर की पहल से बिखरता परिवार बचा

काउंसलिंग और कानूनी परामर्श से रिश्तों में लौटा विश्वास

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। जिला वन स्टॉप सेंटर, बालाघाट की संवेदनशील पहल से एक बिखरते परिवार को नया जीवन मिला। पारिवारिक विवाद, मानसिक तनाव और वैवाहिक संबंधों में आई खटास के बीच सेंटर द्वारा दी गई कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श और काउंसलिंग के सकारात्मक परिणाम सामने आए, जिसके बाद दंपती ने आपसी मतभेद दूर कर साथ रहने का निर्णय लिया। वन स्टॉप सेंटर प्रशासक सुश्री रचना चौधरी ने बताया कि विवाह के कई वर्षों बाद दंपती के बीच संबंधों में तनाव बढ़ गया था। पारिवारिक विवादों के कारण महिला मानसिक रूप से बेहद परेशान हो गई और सहायता की तलाश में जिला वन स्टॉप सेंटर पहुंची। सेंटर में उसे अस्थायी आश्रय, भोजन, चिकित्सा सुविधा तथा मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराया गया। जांच के दौरान महिला तनाव और चिंता (एंग्जायटी) से पीड़ित पाई गई, जिसके बाद उसका उपचार भी शुरू कराया गया। वन स्टॉप सेंटर की टीम ने पति को बुलाकर दोनों पक्षों की काउंसलिंग कराई। इस दौरान उन्हें घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराया गया तथा कई चरणों में एकल एवं संयुक्त परामर्श सत्र आयोजित किए गए। परामर्श के दौरान पति को अपने व्यवहार का परिवार और बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में समझाया गया तथा आवश्यक मानसिक स्वास्थ्य उपचार लेने की भी सलाह दी गई। लगातार काउंसलिंग के बाद पति ने अपने व्यवहार में सुधार लाने, पत्नी के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करने और परिवार को प्राथमिकता देने का लिखित आश्वासन दिया। वहीं पत्नी ने भी आपसी विश्वास को एक और अवसर देने का निर्णय लिया। वर्तमान में दंपती अपनी दोनों बेटियों के साथ पुनः एकजुट होकर खुशहाल पारिवारिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परिवार में सकारात्मक माहौल लौटने के साथ बच्चों के चेहरे पर भी मुस्कान वापस आई है। वन स्टॉप सेंटर, बालाघाट ने बताया कि समय पर कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श और संवेदनशील हस्तक्षेप से न केवल पीड़ित महिलाओं को सहयोग मिलता है, बल्कि कई मामलों में टूटते परिवारों को भी संभालने में सफलता मिलती है।

पांच साल बाद भी सीएम राइज स्कूलों में नहीं मिली परिवहन सुविधा, रोजाना अतिरिक्त खर्च उठाने को मजबूर हजारों अभिभावक

स्कूलों के विलय के समय बस सुविधा का किया गया था वादा, आज भी 5 से 10 किलोमीटर दूर से निजी साधनों से पहुंच रहे छात्र, प्राचार्य बोले- मामला शासन स्तर का, स्कूल प्रबंधन के हाथ में नहीं

सिटी रिपोर्टर।
पद्मेश न्यूज। बालाघाट।

प्रदेश सरकार ने सरकारी विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक, तकनीकी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्य से लगभग पांच वर्ष पूर्व सीएम राइज स्कूल योजना की शुरुआत की थी। इस योजना को सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी शैक्षणिक योजनाओं में शामिल किया गया था। योजना के तहत जिले सहित पूरे प्रदेश में अनेक छोटे-छोटे विद्यालयों का विलय कर बड़े स्तर पर सीएम राइज स्कूल स्थापित किए गए। इन विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, आधुनिक प्रयोगशालाएं, बेहतर खेल सुविधाएं, प्रशिक्षित शिक्षक, डिजिटल शिक्षा और अन्य आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराने के साथ-साथ विद्यार्थियों को उनके घरों से विद्यालय तक लाने और वापस छोड़ने के लिए बस एवं अन्य परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने का भी वादा किया गया था। लेकिन योजना शुरू होने के लगभग पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी जिले के किसी भी सीएम राइज स्कूल में विद्यार्थियों के लिए परिवहन सुविधा शुरू नहीं हो सकी है। इसका खामियाजा हजारों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को रोजाना आर्थिक और मानसिक रूप से भुगतना पड़ रहा है।

जिले में संचालित सीएम राइज स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अभिभावकों का कहना है कि जब सरकार ने विभिन्न विद्यालयों का विलय कर सीएम राइज स्कूल बनाए थे, तब यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि दूर-दराज के गांवों से आने वाले विद्यार्थियों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए बसों और अन्य परिवहन साधनों की व्यवस्था शासन द्वारा की जाएगी। इसी भरोसे के साथ कई अभिभावकों ने अपने बच्चों का प्रवेश सीएम राइज स्कूलों में कराया, लेकिन पांच वर्षों में भी यह घोषणा केवल कागजों तक सीमित रह गई है। अभिभावकों का कहना है कि पहले उनके बच्चे गांव या आसपास के सरकारी विद्यालयों में पढ़ते थे, जहां पैदल या साइकिल से आसानी से स्कूल पहुंच जाते थे और उन्हें किसी अतिरिक्त खर्च का सामना नहीं करना पड़ता था। लेकिन विद्यालयों के विलय के बाद अब विद्यार्थियों को प्रतिदिन 5 से 10 किलोमीटर, कहीं-कहीं इससे भी अधिक दूरी तय कर सीएम राइज स्कूल पहुंचना पड़ रहा है। ऐसे में उन्हें ऑटो, निजी वाहन, बस या अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ता है, जिससे हर महीने सैकड़ों से लेकर हजारों रुपये तक अतिरिक्त खर्च हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के पालकों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच बच्चों की पढ़ाई का खर्च पहले ही बढ़ चुका है। ऐसे में परिवहन का अतिरिक्त खर्च उनके लिए बड़ी समस्या बन गया है। कई परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उनके लिए प्रतिदिन बच्चों के आने-जाने की व्यवस्था करना आसान नहीं है। कुछ अभिभावकों ने बताया कि आर्थिक परेशानी के कारण कई बार बच्चे नियमित रूप से स्कूल भी नहीं पहुंच पाते। पालकों का कहना है कि यदि सरकार ने शुरुआत में ही परिवहन सुविधा देने की घोषणा नहीं की होती तो शायद वे अपने बच्चों को दूसरे विद्यालयों में ही पढ़ाना बेहतर समझते। उनका कहना है कि सरकार ने आधुनिक शिक्षा के साथ सुरक्षित और निःशुल्क परिवहन की बात कही थी, लेकिन आज तक न तो बसें दिखाई दीं और न ही इस दिशा में कोई ठोस प्रयास नजर आया। जानकारी के अनुसार इस समस्या को लेकर पूर्व में भी कई बार अभिभावकों ने जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर सीएम राइज स्कूलों में परिवहन सुविधा शुरू करने की मांग की थी। कई बार इस मुद्दे को स्थानीय स्तर पर उठाया गया, लेकिन अब तक कोई समाधान सामने नहीं आया। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ एक बार फिर यह समस्या गंभीर रूप से सामने आ गई है और पालकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। स्थिति केवल एक विद्यालय तक सीमित नहीं है। जिले के विभिन्न विकासखंडों में संचालित सभी सीएम राइज स्कूलों में लगभग यही हालात बताए जा रहे हैं। कहीं भी शासन द्वारा नियमित बस सेवा उपलब्ध नहीं कराई गई है। ऐसे में दूरस्थ गांवों से आने वाले विद्यार्थियों को निजी साधनों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। कई विद्यार्थियों को सुबह जल्दी घर से निकलना पड़ता है और शाम को देर से घर पहुंचना पड़ता है, जिससे उनकी पढ़ाई और दैनिक दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है।

परिवहन सुविधा का प्रावधान रखा गया था-युवराज राहंगडाले

इस पूरे मामले में शहर के सीएम राइज स्कूल के प्राचार्य युवराज राहंगडाले से चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि सीएम राइज योजना में परिवहन सुविधा का प्रावधान अवश्य रखा गया था, लेकिन यह पूरी प्रक्रिया शासन स्तर पर संचालित होती है। विद्यालय प्रबंधन का कार्य केवल शैक्षणिक व्यवस्था, शिक्षकों और विद्यार्थियों से जुड़े संचालन तक सीमित है। उन्होंने बताया कि उनकी जानकारी के अनुसार परिवहन सुविधा से संबंधित प्रक्रिया अभी उच्च स्तर पर लंबित हो सकती है। संभव है कि बस संचालन के लिए टेंडर प्रक्रिया या अन्य प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी नहीं हो पाई हों। उन्होंने स्पष्ट किया कि विद्यालय स्तर पर इस विषय में कोई निर्णय लेना संभव नहीं है और यह पूरी तरह शासन के अधिकार क्षेत्र का विषय है।

पावरहाउस गली अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अतिरिक्त भूमि की मांग खारिज, एक माह में वैकल्पिक आवास पर होगा निर्णय

13 जुलाई को तहसीलदार के समक्ष पेश होंगे प्रभावित परिवार, पीएम आवास में शिफ्ट नहीं होने पर प्रशासन को कार्रवाई की छूट

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। शहर की पावरहाउस गली से अतिक्रमण हटाने के मामले में शुक्रवार को जबलपुर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए अतिक्रमणकारियों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि पर अस्थायी मकान बनाकर रह रहे लोगों को अतिरिक्त भूमि आवंटित करने की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती। साथ ही तहसीलदार को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी प्रभावितों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए एक माह के भीतर वैकल्पिक आवास में स्थानांतरण के संबंध में निर्णय लें। पावरहाउस गली क्षेत्र में करीब 50 से 60 परिवार वर्षों से अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू किए जाने के बाद प्रभावित परिवारों ने जबलपुर हाईकोर्ट की शरण ली थी। याचिका में उन्होंने प्रशासन से अलग से भूमि आवंटित करने और बेदखली पर रोक लगाने की मांग की थी। मामले की सुनवाई के दौरान प्रशासन ने न्यायालय को बताया कि प्रभावित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित मकानों में स्थानांतरित होने का विकल्प दिया गया था, लेकिन कई लोगों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ताओं की मांग विधिसम्मत नहीं है और मामले को लंबे समय तक लंबित रखना भी उचित नहीं होगा। न्यायालय ने निर्देश दिया कि सभी याचिकाकर्ता 13 जुलाई को संबंधित तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। तहसीलदार प्रत्येक प्रकरण की सुनवाई करते हुए एक माह के भीतर वैकल्पिक आवास के संबंध में अंतिम निर्णय पारित करेंगे। न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि प्रभावित परिवार प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों में स्थानांतरित होने से इनकार करते हैं, तो तहसीलदार विधि अनुसार उनके विरुद्ध आगे की बेदखली और अन्य आवश्यक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे। यानी अब प्रभावित परिवारों के सामने शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए वैकल्पिक आवास को स्वीकार करने या फिर प्रशासनिक कार्रवाई का सामना करने के अलावा कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रहेगा। गौरतलब है कि कुछ माह पूर्व इस मामले को लेकर प्रभावित परिवारों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर बड़ा प्रदर्शन किया था। उस समय बारिश के मौसम और मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने तत्काल बेदखली की कार्रवाई स्थगित कर कुछ समय की मोहलत दी थी। प्रशासन का कहना था कि उद्देश्य किसी को बेघर करना नहीं, बल्कि अतिक्रमण हटाकर वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराना है। सूत्रों के अनुसार, न्यायालय के निर्णय और प्रशासन की कार्रवाई के बाद कुछ परिवार पहले ही पावरहाउस गली से अपने मकान खाली कर चुके हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उपलब्ध कराए गए मकानों में शिफ्ट हो गए हैं। हालांकि, कई परिवार ऐसे भी हैं जो अभी भी वहीं रह रहे हैं। उनका कहना है कि उनके सामने आजीविका, बच्चों की पढ़ाई और अन्य सामाजिक कारणों जैसी व्यावहारिक कठिनाइयां हैं, इसलिए वे अब तक स्थानांतरित नहीं हो पाए हैं। अब हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद प्रशासन की आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। यदि प्रभावित परिवार वैकल्पिक आवास स्वीकार करते हैं तो लंबे समय से चला आ रहा यह विवाद समाप्त हो सकता है, वहीं प्रस्ताव ठुकराने की स्थिति में प्रशासन कानूनी प्रक्रिया के तहत बेदखली की कार्रवाई आगे बढ़ा सकता है। ऐसे में 13 जुलाई को तहसीलदार के समक्ष होने वाली सुनवाई और उसके बाद लिया जाने वाला निर्णय इस पूरे प्रकरण में निर्णायक साबित होगा।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मनाया काला दिवस, मांगो को पूरी करने को लेकर की जमकर नारेबाजी

25 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की लगाई गुहार, सौपा ज्ञापन, विधानसभा का घेराव कर, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। वर्षों से लंबित विभिन्न सूत्रीय मांगे पूरी न होने से आंगनबाड़ियों में कार्यरत कार्यकर्ताएं व सहायिकाए प्रदेश सरकार से खासा नाराज है,जो अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आए दिनों, आवेदन निवेदन और ज्ञापन सौंप रही है, बावजूद इसके भी उनकी अब तक मांग पूरी नहीं हो पायी है। इस बात पर नाराजगी जताते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिका एकता यूनियन द्वारा शुक्रवार 10 जुलाई को काला दिवस मनाया गया। साथ ही उन्होंने नगर के बस स्टैंड स्थित धर्मशाला में एक बैठक का आयोजन कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायताओं को कार्यक्षेत्र में आने वाली विभिन्न परेशानियों से अवगत कराया।तो वही अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी भी की,इसके उपरांत धर्मशाला से एक रैली निकाली गई यह रैली नगर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए सीधे कलेक्टर कार्यालय पहुंची। जहां यूनियन द्वारा वर्षों से लंबित अपनी 25 सूत्रीय मांगों को पूरा कराई जाने को लेकर जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौपा है।अखिल भारतीय आंगनबाड़ी वर्कस एण्ड हेल्पर्स फैडरेशन के राष्ट्रीय आव्हान पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिक यूनियन म.प्र सीटू बालाघाट द्वारा केंद्र व राज्य सरकार के नाम सौंपे गए इस ज्ञापन में उन्होंने जल्द से जल्द उक्त सभी मांगों को पूरा किए जाने की गुहार लगाते हुए, मांग पूरी न होने पर विधानसभा का घेराव कर, 12 अगस्त को उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है।

इन मांगो को पूरा करने की लगाई गुहार

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को नियमित किए जाने, समय पर मानदेय देने, उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत, आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में से की गई कटौती को एरियर के साथ तत्काल भुगतान करने, चार श्रम संहिताओं और नियमों को निरस्त करने,आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के ट्रेड यूनियन अधिकारों को मान्यता देने,आंगनबाड़ी कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर, कार्यकर्ता को न्यूनतम वेतन 41000रु,और सहायिका को 32000 रु तथा 12000 रु पेंशन, सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने, टेक होम राशन का वितरण प्रणाली में सुधार लाने,आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय पोषण ट्रैकर एवं संपर्क एप से न जोड़ा जाने, सरकारी स्कूलों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के प्रवेश के सरकारी आदेश पर रोक लगाने,आंगनबाड़ी केन्द्रों में ही नर्सरी, के.जी.-1, के.जी.-2, की शिक्षा दिये जाने की व्यवस्था करने, ग्रेच्युटी का लाभ सेवा निवृत हुए सभी आंगनबाड़ी कर्मियों को देने, 21अप्रैल 2026 को दिये उच्च न्यायालय के आदेश को तत्काल लागू करते हुये ग्रेच्युटी का भुगतान करने, आंगनबाड़ी कर्मियों की सेवा काल में मृत्यु होने पर 5 लाख रूपये की राशि मृत्यु उपरान्त परिवार को सहायता राशि के रूप में देने। रिटायरमेंट में मिलने वाली राशि का भुगतान तत्काल शुरू करने,आंगनबाड़ी भवन किराया बढ़ी हुई नई दरों के हिसाब से भुगतान करने, उपस्थित बच्चों की वास्तविक संख्या को पोषण ट्रेकर में दर्ज करने की अनुमति देने, राशन वितरण प्रणाली के तहत परिवहन भाड़ा देने, ग्रीष्मकालीन शीतकालीन अवकाश के समय भी बच्चों को भोजन प्रदान करने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को ग्रीष्मकालीन अवकाश देने, ट्रेनिंग या मीटिंग के लिए आने जाने के एवज में टीए डीए भत्ता दिए जाने, उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं से अन्य विभागों का कार्य न लेने, उन्हें पदोन्नति का लाभ देने,सेवा निवृत्ति की आयु 62 से बढ़कर 65 वर्ष किए जाने, और आंगनबाड़ी केंद्र के लिए अवकाश कैलेंडर जारी करने सहित वर्षों से लंबित अन्य मांगों को पूरा किए जाने की गुहार लगाई है।

विधानसभा का घेराव कर, 12 अगस्त को करेंगे उग्र आंदोलन-अंजली बिसेन

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यूनियन की जिलाध्यक्ष श्रीमती अंजली बिसेन ने चर्चा के दौरान बताया कि न्यायालय के आदेश के बावजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 2019 से 6 प्रतिशत एरियर राशि का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। इसके अलावा मानदेय का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है, अतिरिक्त कार्य भी कराया जा रहा है जिससे प्रदेश व जिले के समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता , सहायिकाओं में नाराजगी व्याप्त है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 38 हजार रूपए व सहायिकाओं को 25 हजार रूपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाओं ने शासन-प्रशासन को चेतावनी दी कि शीघ्र मांगें पूरी नहीं की जाती है तो विधानसभा घेराव व 12 अगस्त को उग्र आंदोलन किया जाएगा।

सरकार ताजुद्दीन औलिया के 104 वे उर्स पर रोजाना हो रहे विभिन्न कार्यक्रम

जामेआ नूरिया में मिलाद शरीफ तो अंजुमन शादी हाल में हुआ लंगर ए आम

पद्मेश न्यूज़। बालाघाट। शहंशाह ए नागपुर, सरकार बाबा ताजुद्दीन औलिया का उर्स मुबारक केवल देश ही नही बल्कि दुनिया के तमाम मुल्कों में उनके अकीदतमंदों द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जो हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है।जिसके तहत रोजाना ही विभिन्न कार्यक्रमो के आयोजन किए जा रहे है जिसकी धूम बालाघाट जिले में भी देखी जा रही है। इसी कड़ी में सरकार ताजुद्दीन औलिया की 26 वी मुबारक पर जिला मुख्यालय सहित अन्य तहसील व ग्रामीण अंचलों में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। जहां सरकार बाबा ताजुद्दीन औलिया के 104 वे उर्स मुबारक पर हर साल की तरह इस साल भी नगर के वार्ड नं 10 रजा नगर स्थित जामेआ नूरिया मदरसे में शुक्रवार शाम मिलाद शरीफ का आयोजन किया जिसमे नात ख्वानी, दरूद ख्वानी, तकरीर व तबरुकात वितरण किया गया।तो वही बैहर रोड़ स्थित अंजुमन शादी हाल में अकीदतमंदों की जानिब से लंगर के आम का आयोजन किया गया।आयोजित इस लंगर ए आम के कार्यक्रम में ना सिर्फ मुस्लिम समाज बल्कि सर्व धर्म व समाज के लोगो ने बढ़चढ़ हिस्सा लिया।

पोंडी पुल से रमपुरी मार्ग पर मरम्मत के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति

पहली ही तेज बारिश में बह जायेगी मरम्मत के लिये डाली गई मिट्टी

स्थाई समाधान के बजाय की गई है सिर्फ औपचारिकता, पक्का मरम्मत एवं रिटर्निंगवॉल का निर्माण की उठी मांग

रिपोर्टर।
पद्मेश न्यूज। लालबर्रा।

नगर मुख्यालय से 6 किमी. दूर हाईवे मार्ग स्थित ग्राम पोंडी-सिहोरा पुल से रमपुरी को जोड़ने वाला मुख्य पहुंच मार्ग इस समय बड़े हादसे को न्योता दे रहा है। पिछले वर्ष नाले में आई बाढ़ के कारण सड़क के किनारे की मिट्टी का भारी कटाव हो गया था। यह कटाव अब सीधे मुख्य सड़क तक पहुंच चुका है, जिससे स्थिति अत्यंत गंभीर और संवेदनशील हो गई है। वही किसी भी समय बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई थी। साथ ही आवागमन करने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस गंभीर जनसमस्या को प्रमुखता से बालाघाट एक्सप्रेस अखबार में समाचार प्रकाशित कर प्रशासन का ध्यानाकर्षण करवाया गया था। वहीं खबर प्रकाशन के बाद प्रशासनिक अमले में हलचल तो हुई, लेकिन संबंधित विभाग द्वारा समस्या का स्थाई समाधान निकालने के बजाय केवल खानापूर्ति और औपचारिकताएं पूरी की गई है। जेसीबी मशीन से जिस स्थान से सड़क का कटाव हो गया था उस स्थान पर नाले की मिट्टी से क%चा मरम्मत कार्य करवाया गया है और यह कार्य गुणवत्ताहीन किया गया है। गत दिवस हुई तेज बारिश के कारण मिट्टी पुन: नाले में बहने लगी है और बरसात के दिनों में बारिश होने एवं नाले में बाढ आने पर पुन: स्थिति जस की तस हो जायेगी। वहीं सड़क का कटाव भी हो सकता है जिससे इस मार्ग से आवागमन भी बाधित हो सकता है। जिससे इस मार्ग से आवागमन करने वाले आधा दर्जन से अधिक ग्रामों के ग्रामीणजन एवं स्कूली ब%चों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि सड़क विभाग को मिट्टी कटाव को रोकने के लिए रिटर्निंगवॉल का निर्माण करवाना था। लेकिन मरम्मत के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति करते हुए सिर्फ औपचारिकता निभाई गई है जिससे ग्रामीणजनों एवं राहगीरों में आक्रोश व्याप्त है।

नाले में बाढ़ आने पर, सड़क ढहने से आवागमन हो सकता है बंद

आपकों बता दे कि विगत वर्ष पूर्व हुई तेज बारिश और नाले में बाढ़ की वजह से पोंडी-सिहोरा एवं रमपुरी पहुंच मार्ग किनारे नाले की मिट्टी का कटाव सड़क तक पहुंच चुका है। यह समस्या विगत वर्षो से बनी हुई है और इस समस्या से अनेक बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा संबंधित विभाग को अवगत करवाया गया किन्तु विभाग के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है परंतु स्थाई समाधान नही किया जा रहा है। वर्तमान में भी विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा क्षतिग्रस्त स्थान पर पक्का निर्माण करवाने के बजाय, नाले के अंदर से ही गीली मिट्टी खोदकर सड़क के किनारे डाली गई है।जबकि वर्तमान में मानसून (बारिश का मौसम) पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। ऐसे में नाले का जलस्तर बढ़ने और पानी का तेज बहाव आने पर यह ढीली मिट्टी एक झटके में बह जायेगी। विभाग द्वारा की जा रही यह मरम्मत सिर्फ कागजी खानापूर्ति नजर आ रही है, जिससे सरकारी धन का भी दुरूपयोग हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह से मिट्टी डालकर मरम्मत कार्य अनेक बार किया गया है परंतु कुछ दिनों के बाद स्थिति जस की तस हो जाती है और वर्तमान में स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है, मिट्टी का कटाव सड़क तक पहुंच चुका है। ऐसी स्थिति में जब तक यहां मजबूत रिटर्निंगवॉल का निर्माण नहीं किया जाता, तब तक मिट्टी डालना सिर्फ समय और रूपये की बर्बादी है। पहली ही तेज बारिश में यह पूरी मिट्टी बह जायेगी और मुख्य सड़क भी ढह जायेगी।

रिटर्निंगवॉल ही एकमात स्थाई समाधान

भौगोलिक स्थिति को देखा जाये तो इस नाले में बाढ़ आने पर पानी का बहाव बेहद तेज और मटमैला होता है। बिना किसी ठोस सुरक्षा दीवार (रिटर्निंग वॉल) के, पानी का तेज बहाव मिट्टी को आसानी से अपने साथ बहा ले जाता है। यही कारण है कि धीरे-धीरे कटाव बढ़ते-बढ़ते अब पक्की सड़क के अस्तित्व पर खतरा बन गया है। अगर समय रहते यहां पक्की रिटर्निंगवॉल नहीं बनाई गई, तो पोंडी-सिहोरा पुल से रमपुरी मार्ग का संपर्क पूरी तरह टूट सकता है, जिससे हजारों की आबादी प्रभावित होगी। सड़क की इस बदहाली और विभाग की लचर कार्यप्रणाली से स्थानीय निवासियों एवं राहगीरों में भारी आक्रोश है। सुरक्षा की दृष्टि से और किसी भी संभावित बड़ी दुर्घटना को टालने के लिए ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और संबंधित सड़क विभाग से तत्काल प्रभाव से यहां मजबूत रिटर्निंगवॉल (सुरक्षा दीवार) का निर्माण करवाने की पुरजोर मांग की है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पर कब तक सुध लेता है या किसी बड़े हादसे का इंतजार करता है। वहीं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विभाग के महाप्रबंधक माया परते से दूरभाष पर पोंडी-सिहोरा पुल से रमपुरी पहुंच मार्ग के नाले किनारे से जो मिट्टी का कटाव होने से सड़क क्षतिग्रस्त हुई है उसका पक्का मरम्मत एवं मिट्टी कटाव के लिए रिटर्निंगवॉल का निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा करने का प्रयास किया गया किन्तु संपर्क नही हो पाया।

मिट्टी कटाव को रोकने के लिए रिटर्निंगवॉल का निर्माण करवाये

प्रशासन - श्याम

चर्चा में रमपुरी सरपंच श्याम मानेश्वर ने बताया कि पिछले वर्ष पूर्व हुई तेज बारिश एवं नाले में बाढ़ आने से सड़क किनारे की मिट्टी का कटाव मुख्य सड़क के समीप तक हो चुका है। जिसके कारण आवागमन में परेशानी हो रही थी। उक्त समस्या से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विभाग को अवगत करवाकर पक्का मरम्मत कार्य करवाने की मांग की गई थी। लेकिन उनके द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के तहत क%चा मरम्मत कार्य करवाया गया है। तेज बारिश होने पर पुन: मिट्टी कटाव हो जायेगी जिससे बरसात के दिनों में परेशानी होगी। श्री मानेश्वर ने बताया कि प्रशासन को मिट्टी कटाव को रोकने के लिए रिटर्निंगवाल का निर्माण करवाना चाहिए, सड़क विभाग के अधिकारियों ने आश्वास्त किया है कि शासन से राशि स्वीकृत होने के बाद रिटर्निंगवाल का निर्माण करवायेंगें।

खेत में धान रोपाई को लेकर विवाद, दो महिलाओं ने युवती से की मारपीट, मामला कायम

पद्मेश न्यूज। लालबर्रा। थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मानपुर में खेत में धान की रोपाई करने और जमीन पर कब्जे की बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इस हद तक बढ़ गया कि दो महिलाओं ने मिलकर एक युवती के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट कर दी। पीड़िता की शिकायत पर लालबर्रा पुलिस ने दोनों महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम मानपुर निवासी 26 वर्षीय पीड़िता मनीषा पंचेश्वर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उसके पिता के निधन के बाद उनकी पैतृक कृषि भूमि पर उनके परिवार द्वारा धान का रोपा लगाया गया था। 10 जुलाई को दोपहर 2 बजे जब मनीषा अपने खेत पर गई, तो उसने देखा कि गांव की ही सुनीता पंचेश्वर और मुन्नी पंचेश्वर उस जमीन को अपना बताकर वहां जबरन धान की रोपाई कर रही थीं। जब मनीषा और उसकी बहन ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और रोपाई करने से मना किया, तो दोनों महिलाएं भड़क गईं और उन्हे गंदी गाली-गलौज करते करने लगे। जिन्हे गाली देने से मना करने पर सुनीता और मुन्नी ने मनीषा के साथ मारपीट कर दिये। जिससे मनीषा के गाल और दाहिने हाथ की कलाई में चोटे आई है। पुलिस ने पीड़िता मनीषा पंचेश्वर की शिकायत पर सुनीता पंचेश्वर, मुन्नी पंचेश्वर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 115 (2), 3 (5) के तहत मामला पंजीबध्द कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

रामजीटोला के किसानों ने विद्युत विभाग को सौंपा ज्ञापन

एक माह से ट्रांसफार्मर जलने से कृषि कार्य प्रभावित, नया ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की

पद्मेश न्यूज। लालबर्रा। नगर मुख्यालय की ग्राम पंचायत पांढरवानी के अंतर्गत आने वाले ग्राम रामजीटोला के किसान इन दिनों बिजली की भारी समस्या से जूझ रहे हैं। ग्राम के पटवर्री स्थित कृषि क्षेत्र का मुख्य विद्युत ट्रांसफार्मर पिछले एक महीने से जला पड़ा है, जिसके कारण खेतों में विद्युत सप्लाई पूरी तरह ठप है। इससे परेशान किसानों ने शुक्रवार को विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द नया ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो वे कठोर कदम उठाने बाध्य होगें। आपकों बता दे कि रामजीटोला के पटवर्री स्थित ट्रांसफार्मर से किसानों के खेतों में बिजली गई है। लेकिन एक माह पूर्व ट्रांसफार्मर जल चुका है जिसे अब तक नही सुधारा गया है। वहीं गत दिवस से बारिश भी नही हो पा रही है ऐसी स्थिति में किसानों की खरीफ सीजन की फसल धान की रोपाई सहित अन्य कार्य प्रभावित हो रहे हैं। यानि की बिजली के अभाव में पानी की मोटरें नही चला पा रहे है जिससे कृषि कार्य ठप हो चुका है। वहीं किसानों का कहना है कि अगर समय रहते पानी नहीं मिला, तो उनकी मेहनत और लागत दोनों को काफी नुकसान होगा। जबकि किसानों के द्वारा कई बार विद्युत विभाग को भी इस समस्या से अवगत करवा चुके हैं। लेकिन जिम्मेदारों के द्वारा कोई ध्यान नही दिया जा रहा है जिससे किसानों में रोष व्याप्त है। किसानों ने विद्युत विभाग से पटवर्री रामजीटोला का जो ट्रांसफार्मर खराब हुआ है उसे बदलकर उसके स्थान पर नया ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की है।

शिकायत के बाद भी समस्या का नही हो रहा निराकरण - नंदकुमार

नंदकुमार पंचेश्वर ने बताया कि खेतों में जिस ट्रांसफार्मर से कनेक्शन गया हुआ है वह जल चुका है जिसके कारण बिजली की समस्या बनी हुई है। इस समस्या के संबंध में संबंधित विभाग के कर्मचारी व अधिकारी को अवगत करवाया गया था परंतु समस्या का समाधान नहीं किया गया है इसलिए ज्ञापन सौंपकर जल्द नया ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की गई है। जिस पर अधिकारियों ने आश्वास्त किया है कि सोमवार तक बिजली की समस्या का समाधान कर दिया जायेगा। मांगे पूरी नही होने पर कठोर कदम उठाने बाध्य होगें।

ट्रांसफार्मर खराब हुए एक माह हो गया है - दीपक

जनपद सदस्य दीपक कावरे ने बताया कि किसानों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक माह पूर्व से पटवर्री मैदान में लगा ट्रांसफार्मर जल चुका है। जिसे अब तक नही सुधारा गया है जिससे कृषि कार्य प्रभावित हो रहे है एवं शिकायत के बाद भी समस्या का निराकरण नही होने पर शुक्रवार को किसानों के साथ विद्युत कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर खराब ट्रांसफार्मर को बदलकर नया ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की है। श्री कावरे ने बताया कि ट्रांसफार्मर जहां लगने के आया था वहां नहीं लगाया गया है, दुसरी जगह लगाया गया है, बिजली सप्लाई बंद होने से धान का रोपाई सहित अन्य कृषि कार्य ठप हो चुका है, हमारी मांग है कि बिजली की समस्या को जल्द दुर किये जाये।

इनका कहना है-

रामजीटोला के पटवर्री का ट्रांसफार्मर जलने से बिजली सप्लाई बंद है। सोमवार तक खराब ट्रांसफार्मर को बदलकर उसके स्थान पर नया ट्रांसफार्मर लगा दिया जायेगा, जिससे बिजली की समस्या दुर हो जायेगी।

सरफराज कुरैशी
कनिष्ठ यंत्री
विद्युत विभाग लालबर्रा।

आमाटोला ददिया में हैंडपंप खराब, बूंद-बूंद पानी को तरस रहे ग्रामीण

आंगनबाड़ी के नौनिहाल बच्चें और कार्यकर्ता के साथ ही ग्रामीणजन पानी के लिए हो रहे परेशान, जिम्मेदार मौन

पद्मेश न्यूज। लालबर्रा। नगर मुख्यालय से करीब 4 किमी दूर ग्राम पंचायत ददिया के अंतर्गत आने वाले ग्राम आमाटोला के आंगनवाड़ी केन्द्र के समीप स्थित हैंडपंप खराब हो जाने से उक्त वार्ड में गत दिवस से पेयजल संकट गहराया हुआ है। वार्ड में स्थापित एकमात हैंडपंप पिछले कई दिनों से खराब पड़ा है, जिसके कारण वार्डवासियों को पानी के लिए खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है । हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि ग्रामीणों को अपनी प्यास बुझाने और रोजमर्रा के कामों के लिए दूसरे वार्डों में जाकर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि हैंडपंप खराब होने की समस्या से ग्रामीणजनों ने पीएचई विभाग को अवगत करवा चुके है लेकिन कोई ध्यान नही दिया जा रहा है। वहीं आंगनबाड़ी केन्द्र के नौनिहाल बच्चों एवं कार्यकर्ता को भी पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। ग्रामीणजनों ने पीएचई विभाग से आमाटोला ददिया के आंगनवाड़ी केन्द्र के समीप स्थित हैंडपंप जो खराब हो चुका है उसे जल्द सुधारने की मांग की है ताकि पानी की समस्या से निजात मिल सके।

शिकायत के बाद भी विभाग मौन, जल संकट दूर करने की मांग

ग्रामीणों ने बताया कि आमाटोला ददिया स्थित आंगनवाड़ी के समीप स्थित वार्ड का एकमात हैंडपंप था, जिसके भरोसे पूरे वार्डवासी निर्भर थे। लेकिन वर्तमान में यहां हैंडपंप खराब हो चुका है, जिसके चलते इससे पानी निकलना बंद हो गया है। हैंडपंप के बंद होते ही पूरे वार्ड में पानी के लिए लाही-लाही मच गई है। वहीं नल-जल योजना का भी नियमित रूप से पानी नही मिलता है और बरसात के दिनों में ग्राम में पानी की समस्या बनी हुई है। साथ ही कुएं का पानी भी बारिश होने के कारण मटमैला हो चुका है, ऐसी स्थिति में दुर स्थित हैंडपंप से ग्रामीणों को पानी लाकर उपयोग करना पड़ रहा है। वहीं इस पानी की विकट समस्या का सबसे अधिक बड़ा असर आंगनवाड़ी के नौनिहाल बच्चों पर पड़ रहा है। जिस जगह यह हैंडपंप खराब हुआ है, ठीक उसी के बगल में सरकारी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। यहां छोटे-छोटे बच्चे पढ़ाई और पोषण आहार के लिए आते हैं। हैंडपंप खराब होने से अब मासूम बच्चों के पीने के पानी के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को भी भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। उन्हें भी काम छोड़कर दूर से पानी का इंतजाम करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि हैंडपंप खराब होने की सूचना और इससे उत्पन्न हुई विकट समस्या के संबंध में संबंधित विभाग को अवगत करवा चुके है। लेकिन इसके बावजूद अब तक जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा कोई ध्यान नही दिया जा रहा है। शासन-प्रशासन और संबंधित विभाग के उ च अधिकारियों से मांग है कि पानी की समस्या की गंभीरता को देखते हुए जल्द से जल्द खराब हैंडपंप को सुधारे ताकि वार्डवासियों और आंगनबाड़ी के ब चों को इस भीषण जल संकट से निजात मिल सके।

मदनपुर में सिंचाई व्यवस्था बदहाल प्रशासन मौन

कासपुर से आने वाली माइनर नहर जगह.जगह से हुई क्षतिग्रस्त व्यर्थ में बह रहा पानी

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। वारासिवनी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत मदनपुर के किसान इन दिनों सिंचाई व्यवस्था को लेकर बेहद परेशान और आक्रोशित हैं। गांव में सिंचाई के लिए बनी कच्ची नहर वर्तमान में पूरी तरह जर्जर और बदहाल हो चुकी है। देखरेख के अभाव में इस नहर का अस्तित्व संकट में है जिसके कारण किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। किसानों का आरोप है कि विभाग और संबंधित अधिकारियों को कई बार लिखित व मौखिक रूप से अवगत कराने के बाद भी अब तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

नाली में तब्दील हुई नहर लाइनिंग कार्य करने की मांग

प्राप्त जानकारी के अनुसार कायदी से एक मुख्य नहर आलेझरी के लिए आती है। इसी मुख्य नहर से कासपुर के पास से एक माइनर नहर मदनपुर के लिए निकाला गया है जो कि अंतिम छोर टेल एरिया पर स्थित ग्राम है। वर्तमान में कासपुर से आने वाली इस नहर की पार जगह जगह से टूट चुकी है और इसमें छोटे.बड़े गड्ढे हो गए हैं जिससे कीमती पानी व्यर्थ बह जाता है। नहर के भीतर बड़े पैमाने पर गाद जमा होने और मुरम फिसलने के कारण इसने अब एक संकरी नाली का रूप ले लिया है। स्थिति यह है कि पट मैदान के पास यह नहर महज डेढ़ फीट की नाली बनकर रह गई है। इसके अलावा पूरी नहर में बेतहाशा झाड़ियां और खरपतवार उग आए हैं जिससे पानी का बहाव पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है। मदनपुर में इस नहर पर करीब ५०० एकड़ से अधिक किसानों की कृषि भूमि निर्भर है। लेकिन नहर की दुर्दशा के चलते महज कुछ एकड़ भूमि ही सिंचित हो पाती है। अंतिम छोर के किसानों को पानी के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ती है। अधिकांश किसानों को अपनी फसल पकाने के लिए मजबूरन अन्य नालों, तालाबों या ट्यूबवेल के माध्यम से पंप लगाकर मोटी लागत में सिंचाई करनी पड़ रही है। किसानों में जल संसाधन विभाग की कार्यप्रणाली से आक्रोशित है। विभाग के द्वारा सिंचाई कर पानी की वसूली तो समय पर कड़ाई से की जाती है चाहे खेतों तक पानी पहुंचे या नहीं। जब वे नियमित रूप से पानी का पैसा दे रहे हैं तो उन्हें सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी और सुदृढ़ व्यवस्था भी मिलनी चाहिए। किसानो ने जल संसाधन विभाग और प्रशासन से मांग की है कि इस माइनर नहर की तत्काल साफ सफाई करवायी जायें और टूट चुके किनारों की मरम्मत हो। किसानों ने इस समस्या के स्थायी समाधान के रूप में पूरी नहर का लाइनिंग पक्कीकरण कार्य करवाने की मांग उठाई है। ताकि पानी का रिसाव बंद हो सके और अंतिम छोर पर बैठे हर गरीब किसान के खेत तक पानी आसानी से पहुंच सके।

पानी आना बहुत मुश्किल है यह समस्या वर्षों की बनी हुई है-सुनील झिल्पे

सरपंच प्रतिनिधि सुनील झिल्पे ने बताया कि नहर की दैनिय स्थिति है जीव जंतुओं ने गड्ढे कर दिए हैं कई जगह से रिपेयरिंग भी नहीं हो पाई है। पानी आना बहुत मुश्किल है यह समस्या वर्षों की बनी हुई है शिकायत भी किये थे परंतु अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया है। अभी भी वैसे ही जर्जर स्थिति में नहर है कोई अधिकारी देखने तक नहीं आता है। पानी की व्यवस्था सिंचाई के लिए नहीं हो पाती है इन्हें पक्की नहर बनाना चाहिए ताकि आसानी से हर किसान के खेत में पानी जा सके। हर बार किसान परेशान होता है और यह अधिकारी केवल सिंचाई कर वसूलने के लिए आ जाते हैं समस्या पर इनका कोई ध्यान नहीं है।

नहर जगह जगह से फूट गई है सिंचाई विभाग को इसकी मरम्मत करना चाहिए-रविशंकर पारधी

पंच रविशंकर पारधी ने बताया कि नहर पुरी बर्बाद है मदनपुर में कभी पूरा पानी नहीं आया है। यहां के लोग एसडीओ और अमीन को तक नहीं पहचानते हैं क्योंकि किसी भी किसान की शिकायत पर विभाग के अधिकारी ने संपर्क आज तक नहीं किया है। जबकि किसान को बारिश से रबी की फसल तक पानी की जरूरत होती है। आज तक अंतिम छोर तक पानी नहीं आया है नहर भी जगह जगह से फ ूट गया है। सिंचाई विभाग को इसकी मरम्मत करना चाहिए क्योंकि वह किसानों से पैसे लेते हैं तो सुविधा देनी चाहिए पर ऐसा कुछ होता नहीं। किसान को खुद नहर सुधार कर पानी अपने खेतों तक लाना पड़ता है उसके बाद भी पर्याप्त पानी किसान को नहीं मिलता हैं।

शिकायत किये जाने पर भी समाधान शून्य है-संजय सोनी

संजय सोनी ने बताया कि नहर की स्थिति पिछले १० वर्षों से बहुत ज्यादा खराब है। इस नहर पर करीब५०० एकड़ खेती भूमि का रकबा है जिसमें से महज ६० एकड़ भूमि सिंचित हो पाती है क्योंकि नहर का पानी आ नहीं पता है। बाकी लोग विभिन्न जल स्रोत के माध्यम से पंप लगाकर अपना खेती कार्य करते हैं। नहर की मरम्मत आज तक नहीं हुई है मिट्टी फिसल कर नहर महज डेढ़ फीट की नाली बन गई है यह कासपुर से नहर आती है किसानो की समस्या बहुत बड़ी है पर अधिकारी इसे समझने के लिए गंभीर नहीं है। किसान और जनप्रतिनिधि सभी ने शिकायत किये पर आज तक समाधान शून्य है।

हमारा प्रयास वारासिवनी को महानगरो की तर्ज पर सुसज्जित और सुविधायुक्त बनाने का है-प्रदीप जायसवाल

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। नगर की सभी सीमाओं को सौंदर्यीकृत करने के उद्देश्य से नपा परिषद ने रामपायली चौक पर स्ट्रीट लाईट की सुविधा की शुरूवात कर विकास के नये आयाम स्थापित किये है। इस दौरान पूर्व केबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल, नपा अध्यक्ष श्रीमती सरिता मनोज दांदरे, पूर्व नपा अध्यक्ष श्रीमती स्मिता जायसवाल, किशोर अमुले, प्रदीप शरणागत, रिधन चौहान सहित नपा के अधिकारी राहगीरो ने स्थल पर ही पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल और नपा अध्यक्ष को इस प्रासंगिक कार्य की बधाई प्रेषित की। पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल ने कहा की हमारा प्रयास वारासिवनी को महानगरो की तर्ज पर सुसज्जित और सुविधायुक्त बनाने का है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव व नपा परिषद के सहयोग से हम आज रामपायली मार्ग पर स्ट्रीट लाईट की सुविधा शुरू कर रहे है। अब नागपुर दिशा से आने वाला राहगीर या हमारे मेहमान भी जब इस सीमा को जगमग रूप से देखेंगे तो उनके मानस पटल पर वारासिवनी की एक अच्छी छवि अवश्य उभरेगी। श्री जायसवाल ने कहा की अब हम कंटगी मार्ग पर टोडिंया नाले से गौशाला तक और लालबर्रा मार्ग पर डॉ चौधरी के क्लिनिक से अभिनंदन लान तक स्ट्रीट लाईट की सुविधा नगरवासीयों को प्रदान करने की दिशा में कार्य शुरू कर रहे है। इसी तरह नपा अध्यक्ष श्रीमती सरिता मनोज दांदरे ने कहा की हमारे नेता प्रदीप जायसवाल की सोच से हम विकास के नये आयाम स्थापित कर रहे है। आज स्ट्रीट लाईट की सौगात से पुरे जिले में वारासिवनी के विकास कार्यो की एक अलग पहचान स्थापित होंगी। आगे भी हमारी नपा परिषद के इस तरह के विकास कार्यो को जनता अवश्य देखेगी। इस दौरान संदीप मिश्रा , वेदप्रकाश पटेल ,श्रीमती दीपा रूसिया, मोनू लिमजे, धर्मु जोशी, अमित येरपूडे,प्रबल जायसवाल,सोनू जायसवाल,संतोष आडे, हरीश जैरथ, अनिश मिश्रा, श्रीमती रीना कासल, मंजू भोंडले, तुलसी शर्मा,शीतल अरोरा,सूर्यप्रकाश उके, अंशिका चौहान उपस्थित रहे।

कर्मचारी उपस्थित रहे। रामपायली चौक इस मार्ग पर चंदन नदी के पुल से रिधनलाल चौहान की राईस मिल तक पहले अंधेरा रहने से परेशानी का अनुभव होता रहा है। किंतु आज जैसे ही स्ट्रीट लाईट की रोशनी से यह मार्ग जगमगाया आवागमन करने वाले वाहन चालको और

राजस्थान की मासूम को न्याय दिलाने सड़क पर उतरीं महिलाएं

महिलाओं ने निकाला विशाल शांति मार्च, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। नगर में जय स्तंभ चौक से १० जुलाई को महिलाओं के द्वारा शांति मार्च एवं ज्ञापन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक १३ वर्षीय मासूम बालिका के साथ हुए जघन्य और शर्मनाक अपराध के विरोध में किया गया। जिसमें समस्त महिलाओं ने एकजुट होकर एक विशाल शांति मार्च निकाला और महामहिम राष्ट्रपति के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर पीड़िता के लिए त्वरित न्याय की मांग की।

देश में बेटियों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग

प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार को जय स्तंभ चौक पर बड़ी संख्या में मातृशक्ति एकत्रित हुई। यहाँ से महिलाओं ने शांतिपूर्ण ढंग से मार्च की शुरुआत की। मार्च में शामिल महिलाओं के हाथों में तख्तियां थीं जिन पर दोषियों को फ ांसी दो और अपराधियों पर कठोरतम कार्यवाही करो जैसे गंभीर स्लोगन लिखे हुए थे। यह आक्रोश और संवेदना से भरा प्रदर्शन जय स्तंभ चौक से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से गुजरा। यह शांति मार्च नेहरू चौक से होते हुए आंबेडकर चौक पहुंचा। जहां समाज के विभिन्न वर्गों ने भी इस आंदोलन के प्रति अपनी संवेदनशीलता और समर्थन व्यक्त किया। तत्पश्चात मार्च पुन: वापस जय स्तंभ चौक पर आकर संपन्न हुआ। मार्च के समापन पर अनुविभागीय अधिकारी वारासिवनी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार वंदना कुशराम को सौंपा गया। ज्ञापन में बताया की इस हृदयविदारक घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। देश में बेटियों की सुरक्षा के लिए अब ठोस कदम उठाए जाने अत्यंत आवश्यक हैं। भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार से मांग की गई है कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए तथा महिलाओं और बालिकाओं के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट से न्याय दिलाकर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही।

यह कृत्य घृणित मानसिकता का है हर व्यक्ति में डर होना चाहिए- जयश्री अरोरा

डॉ जयश्री अरोरा ने बताया कि यह जो हादसा हुआ उसके विरोध में महिलाएं अपना आक्रोश व्यक्ति करने के लिए निकली है। यह कृत्य घृणित मानसिकता का है हर व्यक्ति में डर होना चाहिए की घटना का अंजाम क्या होगा। हम लोगों के बीच में स्वस्थ मानसिकता फैलाना चाहते हैं कि किसी भी बच्चों के साथ ऐसा होता है तो समाज को साथ में होना चाहिए। आज हर व्यक्ति को दुख और संवेदना है हम यह जो परिवर्तन देख रहे हैं वह घृणित मानसिकता के कारण है क्योंकि इन्होंने ऐसी बच्ची को टारगेट किया जो अपना विरोध प्रकट नहीं कर सकती है। यह लोग सोच समझकर १० और १२ वर्ष की बच्चियों को टारगेट कर रहे हैं।

ऐसी गंदी सोच वालों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए- स्मिता जायसवाल

पूर्व नपाध्यक्ष श्रीमती स्मिता जायसवाल ने बताया कि हमने यह शांति मार्च राजस्थान में हुई दुर्घटना के विरोध में निकाला है। यह एक शर्मनाक घटना थी हम इसकी घोर निंदा करते हैं। आज हम सभी महिलाएं यहां पर एकत्रित हुई है हम उस पीड़ित परिवार के साथ है। शासन प्रशासन से मांग हैं की जल्द कार्यवाही हो आरोपियों को कठोर सजा मिले। शांति मार्च का उद्देश्य घटना पर शासन प्रशासन से त्वरित कार्यवाही करवाने के साथ हम सभी को जागरूक करना भी है कि जब तक हम अपनी माता बहनों की रक्षा के लिए कदम नहीं उठाएंगे तब तक यह होगा। ऐसी गंदी सोच वालों को सजा मिलनी चाहिए।

प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने विभिन्न मांगो को लेकर विधायक पटेल को सौंपा ज्ञापन

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। वारासिवनी प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को विधायक जनसंपर्क कार्यालय पहुंचकर विधायक विवेक पटेल को ज्ञापन सौंपा। जहाँ ज्ञापन में महंगाई भत्ता,पेंशनरों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा और लंबित एरियर्स,मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच मंहगाई राहत के लिए सहमति लेने वाली धरा ४९,६ को पूरी तरह खत्म किया जाए। ८० वर्ष के बजाए ७९ वर्ष की आयु पूरी करने वाले पेंशनरों को २० प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन मिलना शुरू किया जाए, केंद्र सरकार के समान और समय पर पूरी मंहगाई राहत दिया जाने जैसे विभिन्न मांगे की गयी। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष अशोक मिश्रा, कार्यकारी अध्यक्ष एस एस गंगेले, उपाध्यक्ष के एल लिल्हारे, बसंत मिश्रा, छगनलाल विजयवार, दिनेश नेमा, अशोक शुक्ला, सोहनलाल डोहरे, दशराम पटले, एन पी नेमा, आर एस बैस, मनोहर बोकडे, सुरेश दुबे,शिवलाल चौधरी, बाजीराव डहाके सहित अन्य लोग मौजूद रहे। संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष शिवशंकर गंगेले ने बताया कि मध्यप्रदेश के पेंशनर्स २०१९ से लेकर आज तक लगातार आर्थिक हानि के साथ मानसिक त्रासदी भुगत रहे है। और उनमें से लगभग ४५ प्रतिशत के करीब यह त्रासदी झेलते झेलते दिवंगत हो चुके है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान से लेकर वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव,मंत्रियों और अधिकारियों को हजारों पत्र प्रस्तुत किए किन्तु सरकार ने आज तक कोई ध्यान ही नहीं दिया। ये सरकार पेंशनर्स के विरोधी है। मध्यप्रदेश सरकार का हमारी समस्याओं पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है हमारी मांग है की हम पेंशनरों की मांगो को सरकार पूरे करे। विधायक विवेक पटेल ने कहा कि कई वर्षों से प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मंत्रियों और अधिकारियों के माध्यम से अपनी समस्या मुख्यमंत्री तक पहुंचाई है। मगर भाजपा के नेताओं को इन पेंशनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों की कोई चिंता नहीं है। इनकी मांग पूरी होना चाहिए ये अपना अधिकार मांग रहे है मगर शासन इनके अधिकारों को छीन रही है। विधानसभा सत्र प्रारंभ होने वाला है हम इनकी मांगो को ध्यान आकर्षण के माध्यम से सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे। वहीं इन पेंशनर्स की मांग पूरी की जाए मुख्यमंत्री के नाम पत्र भेजा गया है।

जनपद पंचायत खैरलांजी में सामान्य प्रशासन समिति की बैठक सम्पन्न

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। जनपद पंचायत खैरलांजी के सभा कक्ष में सामान्य प्रशासन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें विकास कार्यों की समीक्षा के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा कर निर्णायक प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में जनपद पंचायत क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति, शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण को लेकर विस्तृत मंथन किया गया। जनप्रतिनिधियों ने जनहित से जुड़े मुद्दों को जोर शोर से उठाते हुए अधिकारियों को समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने और योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक सुनिश्चित रूप से पहुंचाने के निर्देश दिए। जांच और बदलाव के प्रस्तावों पर जोर देकर बैठक में पूर्व में १५वें वित्त आयोग की राशि से जनपद पंचायत कार्यालय में कराए गए निर्माण कार्यों की जिला पंचायत स्तर से जांच कराने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से लिया गया। इसके साथ ही पंचायतों में पदस्थ उपयंत्रियों के सेक्टर परिवर्तन का प्रस्ताव भी पारित किया गया। वहीं निर्मित कॉम्प्लेक्स के आवंटन को लेकर भी अहम निर्णय लेने की सहमति बनी। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी गायत्री कुमार सारथी, जनपद अध्यक्ष खुशबू

बिसेन, उपाध्यक्ष दुर्गाप्रसाद लिल्हारे, सांसद प्रतिनिधि गिरीश बिसेन, निर्माण सभापति डूंन कुमार डोहरे, वन सभापति ललित ठाकुर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं जनपद सदस्य मौजूद रहे।

समान नागरिक संहिता-कानूनी सुधार की नीयत या राजनीतिक बिसात?

भारत की राजनीति में समान नागरिक संहिता एक ऐसा विषय है, जो जब भी सामने आता है, अपने साथ बहसों का एक नया दौर शुरू हो जाता है। उत्तराखंड में इसे लागू किए जाने के बाद, अब देश के सबसे बड़े आर्थिक और राजनीतिक केंद्र महाराष्ट्र ने भी इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में इस कानून का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक सात सदस्यीय समिति का गठन किया है। सरकार की कोशिश है कि आगामी सत्रों में ही इस विधेयक को विधानसभा में पेश कर दिया जाए। लेकिन क्या देश के सबसे अधिक सामाजिक और आर्थिक विविधता वाले राज्यों में से एक में इसे लागू करना इतना सीधा रास्ता है? या फिर इस कदम की टाइमिंग के पीछे चुनावी समीकरणों की कोई गहरी बिसात बिछी है? जब हम सरकार के इस फैसले को बारीकी से देखते हैं, तो इसके दोनों पहलुओं को निष्पक्षता से तौलना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके समर्थक इसे संविधान के अनुच्छेद 44 में दर्ज नीति निदेशक तत्वों के तहत एक राष्ट्र, एक कानून के सपने को सच करने की दिशा में एक साहसिक कदम मानते हैं। उनका तर्क है कि शादी, तलाक, संपत्ति, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे नागरिक मामलों में सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। इससे विशेष रूप से महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलेगा और सदियों पुरानी रूढ़िवादी प्रथाओं से मुक्ति मिलेगी। इस समिति की कमान जस्टिस रंजना देसाई को सौंपना प्रशासनिक रूप से एक सोची-समझी रणनीति दिखती है, क्योंकि उन्होंने ही पहले उत्तराखंड के कानून का मसौदा तैयार किया था। उनके इस तकनीकी अनुभव का लाभ महाराष्ट्र सरकार उठाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अतीत में शाह बानो और सरला मुद्गल जैसे ऐतिहासिक मामलों में देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत पर बल दिया है, जिससे इस विचार को संवैधानिक मजबूती मिलती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी उतना ही गंभीर और वास्तविक है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आलोचकों और कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तराखंड जैसी सीमित आबादी वाले राज्य और महाराष्ट्र की जमीनी हकीकत में जमीन-आसमान का अंतर है। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी आदिवासी आबादी है, जिनकी अपनी विशिष्ट परंपराएं, प्रथाएं और सामाजिक नियम हैं। इसके अलावा यहाँ विशाल अल्पसंख्यक समुदाय और अलग-अलग धर्मों के निजी कानूनों का एक बेहद पेचीदा ताना-बाना है। इतने बड़े और विविधता से भरे राज्य में बिना किसी व्यापक सामाजिक संवाद के, केवल छह महीने के भीतर एकतरफा मसौदा तैयार कर लेना जमीनी सच्चाइयों से आंखें मूंदने जैसा हो सकता है। भारत का संविधान जहां एक तरफ समानता की बात करता है, वहीं अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार भी देता है। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना किसी भी कानूनविद के लिए एक बड़ी परीक्षा होगी। एक और बड़ा सवाल इस समिति की बनावट पर भी उठ रहा है। सात सदस्यों की इस समिति में पूर्व जजों, पूर्व मुख्य सचिव और संवैधानिक विशेषज्ञों को तो जगह मिली है, लेकिन अल्पसंख्यक या आदिवासी समुदायों के जमीनी प्रतिनिधियों की कमी साफ खलती है। जब आप समाज के हर वर्ग के निजी जीवन को प्रभावित करने वाला कोई बड़ा कानून बनाने जा रहे हों, तो उस चर्चा की मेज पर सभी पक्षों की मौजूदगी न होना कानून की स्वीकार्यता पर सवाल खड़े करता है।

अमेरिका का तुर्की से लगाव की आखिर वजह क्या है?

नाटो शिखर सम्मलेन में ट्रंप ने अंकारा में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अमेरिका तुर्की पर 2020 में लगाए गए बैन हटा देगा। नाटो समिट के दौरान बेस्टेपे प्रेसिडेंशियल कंपाउंड में तुर्की के प्रेसिडेंट रेचेप तैयप एर्दोगन के साथ खड़े होकर ट्रंप ने कहा, हम बैन हटाने जा रहे हैं। वहीं, जब सवाल किया गया कि क्या तुर्की अमेरिकी एफ-35 खरीदने वाला है, इस पर ट्रंप ने कोई वादा नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह फैसला हम लोग करने जा रहे हैं। उन्होंने फाइटर जेट को भी अब तक का सबसे अच्छा फाइटर जेट बताया।लेकिन जब ईरान ने एफ-35 विमान को भी मार गिराया तो यह विमान भी उन्नत नहीं है। अमेरिका का तुर्की से लगाव भारत के लिए खतरा है और जिस तरह सम्बन्ध बनते दिख रहें हैं वो ठीक नहीं है ऐ अमेरिका जानबूझ नाटो में उसको आगे रखकर कहीं ना कहीं ऐ दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत कमजोर है जबकी भारत 140 करोड़ो भारतीय का लोकतान्त्रिक देश है अत: हमारे लिए भगवान राम से बढ़कर कोई और नहीं हो सकता क्योंकि अंतत: राम नाम सत्य होता है भगवान राम ने मानवता का संदेश दिया और न्याय पर भरोसा दिलाया है मार काट खून खराबे नहीं शान्ति का मार्ग दिखाया है हाँ यदि भारत पर कोई बुरी नजर से आंख उठाकर देखा तो हमारी सेना उसके आंख को निकाल देगी हालांकि इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ लेकिन ऐसे निर्णायक मोड़ पर जब हमारी सेना तीन तीन देशों के मोर्चे पर लड़ते हुए पूर्ण जीत की ओर थी तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प ने इसको पता नहीं क्यों अपने पाले में लेने की कोशिश में विपक्ष ने ही हमारे वीर सैनिकों से सवाल पूछ कर उन्हें प्रताड़ित किया जो दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन कारगिल का युद्ध हमें सेना के पराकर्म और साहस की याद दिलाता है जिसमें अटलजी के नेतृत्व में युद्ध में जीत हासिल की करगिल युद्ध को ठीक 21 साल हो चुके हैं। वो युद्ध जिसमें हमने अपने 570 सैनिकों को खोया लेकिन पाकिस्तान के लगभग 3000 सैनिकों को मारा हमारी सेना ने ऊँची पहाड़ी और -10 डिग्री तापमान पर भी भूखे प्यासे रहकर अपनी मात्रभूमि की रक्षा की और अटलजी जैसा प्रधानमंत्री जिसने अमेरिका से बिलकुल नहीं डरे और उन्होंने कहा तक जब तक भारत की 1इंच जमीन भी कब्जे से मुक्त नहीं करा लेते तब तक कोई बात नहीं करेंगे । अपने वीर सैनिकों ने शहादत से पहले, 18 हजार फीट ऊंचाई, माइनस 13 डिग्री की कड़कड़ाती ठंड और भयंकर गोलीबारी के बीच सैनिकों ने दुश्मनों से लोहा लिया कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ी गई एक ऐसी लड़ाई थी जो बहुत ऊँचाई वाले इलाके में हुई थी। यह युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक, यानी 2 महीने, 3 हफ़्ते और 2 दिन (कुल 85 दिन) तक लद्दाख के कारगिल ज़िले में चला। यह लड़ाई विवादित कश्मीर क्षेत्र में लाइन ऑफ़ कंट्रोल (स्भष्ट) के पास हुई थी और इसे परमाणु हथियार रखने वाले दो देशों के बीच हुए कुछ गिने-चुने पारंपरिक युद्धों में से एक माना जाता है। कारगिल युद्ध एक अहम सैन्य घटना है, जो बेहद मुश्किल भौगोलिक हालात, रणनीतिक चुनौतियों और दोनों तरफ़ के सैनिकों की असाधारण बहादुरी के लिए जानी जाती है।इसमें इजराइल देश का साथ मिला इज़राइल कारगिल लड़ाई के दौरान एक ज़रूरी और भरोसेमंद पार्टनर साबित हुआ, जिसने भारत को ज़रूरी मोर्टार एम्युनिशन और जाहिर तौर पर उसके फाइटर जेट्स के लिए लेज़र-गाइडेड मिसाइलें भी जल्दी से दीं। जब ज़मीनी सैनिकों को क्लोज एयर सपोर्ट देने की कोशिश की गई, तो इंडियन एयर फ़ोर्स को पाकिस्तानी बंकरों की लिमिटेड नज़र, गलत अनगाइडेड मिसाइलों और स्भष्ट पार न करने के साफ इंस्ट्रक्शन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इन दिक्कतों को एडजस्ट करने और खास तौर पर कारगिल की ऊंचाइयों पर एक्यूरेसी की समस्या को ठीक करने के लिए, एयर चीफ मार्शल टिपनिस ने 30 मई को आईएफ मिराज 2000॥ फाइटर्स को ज़मीनी हमले के ऑपरेशन्स के लिए लेज़र-गाइडेड बम पहुंचाने में कैपेबल चुना। कई खातों के अनुसार, भारत को इज़रायल से अपने मिराज के लिए तुरंत लेजर-गाइडेड मिसाइलें प्रदान की गई थीं। जून 1999 में, अपग्रेड किए गए मिराज 2000॥ से सटीक हमलों ने पाकिस्तान के सैनिकों के ऊँची पहाड़ीयों पर सटीक हमला कर उसे पीछे हटने पर मजबूर किया अत: जबभी आपको मुश्किल वक्त में आपका साथ देता है तो हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है इसलिए भारत कभी तुर्की जैसा गद्दारी नहीं कर सकता जिसने उसे भूकंप में अपनी सबसे पहले राहत दल को भेजा था और डॉ से लेकर आपदा प्रबंधन के सारे टीम को भेजा था और उसी ने भारत को धर्म के नाम लेकर धोखा दिया और ऑपरेशन सिंदूर में केवल ड्रोन ही नहीं भेजे बल्कि अपने युद्धपोत और सैनिको को भी भेजा जो चीन से भी गन्दा काम किया इसलिए आज भारत ने भी इसके व्यापारिक रिश्ते तोड़ लिए और दिखा दिया भारत में दम है उसके ड्रोन जो पाकिस्तान नहीं चला पा रहें थे तो अपने ऑपरेटर को भी भेज दिया जिससे कई भारतीय मासूमों की जान चली गई आखिर ऐ कौन सा धर्म है जो आपको गद्दार बना देता है धर्म तो यह कहता है दोस्ती का फर्ज निभाना जैसे भगवान राम ने बाली को मार कर सुग्रीव को राजपाठ दिलाया तो सुग्रीव अंतत: भगवान राम के भाई लक्ष्मण के क्रोध से भगवान राम का साथ दिया था हमें हमेशा अपने वीर जवान पर गर्व करना चाहिए जैसे भगवान राम, अपने वीर हनुमान पर गर्व करते थे इसलिए कोई चोरी कर क्या लें जाएगा अंत में राम नाम सत्य ही होना है. जब वो दुनिया से जाएगा तो आपको उसका दु:ख भी होगा बेकार ही हम चोरी का रायता चारों ओर मीडिया में फैला दिया,इसलिए मीडिया को इसतरह की खबरों से बचना चाहिए हमारा ईश्वर भगवान राम है जो न्याय के लिए ही पृथ्वी पर अवतार लिए, उस पर भरोसा करना चाहिए आपने चुना है इसलिए अपनी टीम की गलती भी आपको अपने अनुसार अपने घर के अंदर समेट कर रखना है चाणक्य ने कहा है किसी भी व्यक्ति को परखने के लिए सबसे पहले उसके अंदर इस बात को देखें कि क्या वह दूसरों के सुख के लिए अपने सुख को त्यागने के लिए तैयार है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों के लिए खुद का त्याग करता है तो हमें ऐसे व्यक्तियों पर भरोसा करना चाहिए क्यों ऐसे भक्तो को चुनाव करने में चूक हो गई गलती हमारी भी है इसलिए इस चोरी के मुद्दे को भगवान राम पर विश्वास कर छो? दीजिये क्योंकि कौन ऐसा इंसान होगा जो अंतत: इस दुनिया से नहीं जाएगा तब वो क्या लेकर जाएगा इससे विदेशॉ में भारत की छवि खराव हो रही है विपक्ष को बिना बैठाये एक मुद्दा मिल गया है जिसे दूर दूर तक भगवान राम से कुछ लेना देना नहीं है उसे सबसे बड़ा न्यायकारी मानकर उसके हाल पर छोड़ दें शान्ति से वो स्वयं ही अपनी गलती कबूल कर लेगा चोरी ही तो हुई है कोई हत्या तो नहीं हुई अत: इंसान को भगवान राम पर भरोसा करना चाहिए वो सबसे बड़ा न्यायकारी है.इन सब मामलों में वाद विवाद से बचना चाहिए भारत में एक संगठित राष्ट्रीय आन्दोलन का सूत्रपात ब्रिटिश शासन काल में हुआ भारतीय राष्ट्रवाद कुछ सीमा तक उपनिवेशवादी नीतियों तथा उन नीतियों से उत्पन्न भारतीय प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप ही उभरा था पाश्चात्य शिक्षा का विस्तार मध्यवर्ग का उदय रेलवे का विस्तार तथा सामाजिक-धार्मिक आन्दोलनों ने राष्ट्रवाद की भावना के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई व देश को अंग्रेजों से आजाद कराया.भारत एक सांस्कृतिक, धार्मिक और अलग अलग भाषाई वाला विविधता वाला देश है। राष्ट्रवाद ही वह डोर है जो लोगों को उनके विभिन्न सांस्कृतिक-जातीय पृष्ठभूमि से संबंधित होने के बावजूद सभी भारतीय नागरिकों को एकता के सूत्र में एक पिरोता है। यह कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी भारतीयों को एकजुट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अत: सभी भारतीय जाति पाती धर्म का भेदभाव मिटाकर सभी साथ चले मानवता ही ईश्वर की सच्ची आराधना है.भगवान राम पर विश्वास कीजिये क्योंकि उन्होंने ही आपको यह विश्वास दिलाया है कोई अगर अमरता का वरदान ही हासिल क्यों ना कर लें गलत कर्मों की सजा एकदिन जरूर मिलेगी इसलिए अमरता का वरदान पाकर भी गलत कर्मों से रावण भगवान राम के हाथों बच नहीं सका, बस हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए हम भगवान राम के आदर्शो के लिए जियेंगे और उसके लिए हमें शहीद भी होना पड़े तो कोई चिंता की बात नहीं ऐ भारत में मुल काल के दौरान हुए खुनी संघर्ष में कितने ने अपनी शहादत दि कितने सिख गुरूवों ने शहीद होना स्वीकार किया लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा उसके साथ ही लोगों में भी एकता हुई वों भी उनके विश्वास पर शहीद हुए लेकिन अपना धर्म नहीं छो?ा और इसलिए हम जीवन में भगवान राम के आदर्शो को सबसे ऊपर मानते हैं जो देश प्रेम, मानवता का रास्ता दिखाता है.विश्वास एक ऐसी दवा है जिसका असर तुरंत नहीं होता लेकिन जब होता है तो लोग उससे सीखते हैं धैर्य से काम लेते हैं.क्योंकि दो चीजों को गौर से समझें जहाँ तक ईरान की बात है ऐ उसका और अमेरिका का मामला है लेकिन हार्मोज नियंत्रण को लेकर आईआरजीसी ने उन जहाजो पर भी हमला किया है जिसका इस युद्ध से ?ाई लेना देना नहीं है और आईआरजीसी ने खाड़ी के देशों में जो हमले किए उसमें भारतीय की जान गई कहाँ गई मानवता कट्टर नहीं उदारवादी बनना चाहिए अब भविष्य में युद्ध खाड़ी देशों के आपस में खलीफा बनने की होगी जिसमें शिया और सुन्नी में वर्चस्व की लड़ाई होने की सम्भावना है अत: वहाँ असल में तेल की ल?ाई है जो किसी भी देश को आर्थिक बनाता है अत: उनके या किसी के भी देश के अपने धर्मगुरू को अमेरिका को मारना उचित नहीं था लेकिन शायद खाड़ी देशों में ही आपस में लड़ाई है और इसमें अमेरिका को उकासाया गया और अमेरिका ने भविष्य में उसके परिणाम को बिना सोचे समझे ही युद्ध छेड़ दिया जिसका खामियाजा पूरा विश्व भुगतेगा, इसलिए दोनों देशों को शान्ति से काम लेने की आवश्यकता है अमेरिका का तुर्की से लगाव की आखिर वजह क्या है ऐ समझ से बाहर है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रम्प कभी क्या बोलते हैं कभी कुछ करते हैं लेकिन हकीकत उसकी उलटी है क्योंकि जब 5 महीने से इजारायल और अमेरिका आपस में मिलकर ईरान को नहीं हरा पाएं तो आगे क्या करेंगे कुछ पता नहीं क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति और इजराइल का ईरान पर सयुंक्त युद्ध अभियान सफल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब आप किसी भी देश के टॉप लीडर को मारते हैं तो जनता का आक्रोश और भावुक होना स्वभाविक है इसलिए पहले उसके इतिहास को जाने ईरान का भूगोल ऐसा है कि जमीनी युद्ध में हरना बहुत मुश्किल है ईरान और इराक में 10 सालों से युद्ध हुआ जिसमें दस लाख सैनिकों की मौत हुई फिर भी ईराक जो अमेरिका के समर्थन से लड़ रहा था हरा नहीं पाया अब इस युद्धमें इजराइल का अलग और अमेरिका का अलग उद्देश्य है इजराइल का उद्देश्य सत्ता परिवर्तन का है उसे उसके कच्चे तेल से कोई मतलब नहीं है अमेरिका का उद्देश्य कच्चे तेल को खर्ग द्वीप पर कव्जा करना है इसलिए ट्रम्प ने खुद कहा है तेल गैस ठिकाना को छोड़कर बाकि सभी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करो लेकिन ऐ अभी भी समझ से बाहर है।

-कांतिलाल मांडोत

विकसित भारत की राह में जनसंख्या संतुलन का प्रश्न

प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 की थीम है- "युवाओं की उम्मीदों और आकांक्षाओं को साकार करना-आज और भविष्य के लिए।" यह विषय स्पष्ट संकेत देता है कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य केवल उसकी जनसंख्या के आकार से नहीं, बल्कि उस जनसंख्या की गुणवत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और अवसरों से निर्धारित होता है। भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यह स्थिति एक ओर विशाल मानव संसाधन का अवसर प्रस्तुत करती है, तो दूसरी ओर संसाधनों, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और पर्यावरण पर अभूतपूर्व दबाव भी उत्पन्न करती है। इसलिए विश्व जनसंख्या दिवस भारत के लिए केवल औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि गंभीर आत्ममंथन का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक अवसरों पर छोटे परिवार के महत्व पर बल देते हुए कहा है कि जो परिवार स्वेच्छा से परिवार नियोजन अपनाते हैं, वे राष्ट्र-निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उनका यह संदेश बताता है कि जनसंख्या संतुलन किसी एक समुदाय का नहीं, बल्कि पूरे देश के सतत विकास का विषय है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न पदाधिकारियों ने भी समय-समय पर यह कहा है कि जनसंख्या नीति सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए तथा इसका उद्देश्य किसी समुदाय को लक्ष्य बनाना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित, संसाधनों के संतुलित उपयोग और सामाजिक समरसता को सुनिश्चित करना होना चाहिए।

भारत आज वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" का मंत्र तभी पूरी तरह साकार हो सकता है, जब विकास की गति और जनसंख्या वृद्धि के बीच संतुलन स्थापित हो। यदि जनसंख्या अनियंत्रित गति से बढ़ती रहे और संसाधनों का विस्तार उसी अनुपात में न हो, तो विकास की उपलब्धियां भी पर्याप्त सिद्ध नहीं होंगी। रोजगार के अवसर सीमित होंगे, कृषि योग्य भूमि सिकुड़ेगी, जल संकट गहराएगा, महानगरों पर दबाव बढ़ेगा और पर्यावरणीय असंतुलन गंभीर होता जाएगा। हालांकि यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि जनसंख्या संबंधी विमर्श तथ्यों, संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक सद्भाव पर आधारित हो। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार देता है और जनसंख्या नीति का उद्देश्य भी समान रूप से सभी नागरिकों पर लागू होने वाला, न्यायसंगत एवं पारदर्शी ढांचा होना चाहिए। परिवार नियोजन, महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, विवाह की उपयुक्त आयु, आर्थिक सशक्तिकरण तथा जन-जागरूकता ऐसे उपाय हैं, जिनसे बिना किसी भेदभाव के जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा में प्रभावी परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। विश्व के अनेक अनुभव बताते हैं कि जैसे-जैसे शिक्षा, विशेषकर महिला शिक्षा और आर्थिक विकास बढ़ता है, वैसे-वैसे प्रजनन दर स्वाभाविक रूप से घटती है।

भारत के सामने एक अन्य गंभीर चुनौती अवैध घुसपैठ की भी है। सीमावर्ती क्षेत्रों में यदि अवैध रूप से लोगों का प्रवेश होता है और वे बिना वैधानिक प्रक्रिया के देश में बस जाते हैं, तो इससे राष्ट्रीय सुरक्षा, संसाधनों के वितरण तथा जनसांख्यिकीय संतुलन पर प्रभाव पड़ सकता है। यह विषय जनसंख्या नियंत्रण से अलग, कानून व्यवस्था और सीमा सुरक्षा का प्रश्न है। अत: सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना, अवैध प्रवासन पर प्रभावी नियंत्रण रखना तथा नागरिकता संबंधी कानूनों का निष्पक्ष पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। यह मुद्दा किसी धर्म या समुदाय के विरुद्ध नहीं, बल्कि कानून के शासन और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है। भारत को यह भी समझना होगा कि केवल कठोर कानून बना देना पर्याप्त नहीं होगा। चीन ने अपने समय में एक-संतान नीति अपनाई, लेकिन बाद में बदलती परिस्थितियों के कारण उसे वापस लेना पड़ा। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था चीन से भिन्न है। इसलिए भारत के लिए अधिक उपयुक्त मार्ग वह होगा जिसमें कानून के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता, स्वैच्छिक सहभागिता, शिक्षा और सकारात्मक प्रोत्साहन को प्राथमिकता दी जाए। छोटे परिवारों को प्रोत्साहन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और युवाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान देना अधिक प्रभावी सिद्ध हो सकता है।

पिछले एक वर्ष के आंकड़े बताते हैं कि विश्व की जनसंख्या लगभग 8.19 अरब से ब?कर 8.30 अरब हो गई है, अर्थात एक वर्ष में लगभग 6.9 करोड़ लोगों की वृद्धि हुई है, जो लगभग 0.83 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाती है। दूसरी ओर भारत की जनसंख्या 1.45 अरब से बढ़कर लगभग 1.47 अरब हो गई है, यानी एक वर्ष में लगभग 1.25 करोड़ लोग और जुड़ गए। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 0.87-0.89 प्रतिशत के बीच है, जो वैश्विक औसत से थोड़ी अधिक है। भारत विश्व की कुल आबादी का लगभग 17.8 प्रतिशत हिस्सा रखता है। इतनी विशाल जनसंख्या के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, जल, ऊर्जा, कृषि भूमि और पर्यावरण पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। यदि जनसंख्या वृद्धि और विकास के बीच संतुलन स्थापित नहीं किया गया, तो विकसित भारत का लक्ष्य अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। इसलिए केवल आर्थिक विकास पर्याप्त नहीं है, बल्कि जनसंख्या स्थिरीकरण, मानव संसाधन विकास और संसाधनों के संतुलित नियोजन को भी समान प्राथमिकता देनी होगी।

भारत में जनसंख्या का प्रश्न केवल सामाजिक या आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक विमर्श का भी विषय बन गया है। जातिगत जनगणना और विभिन्न जाति-समुदायों की जनसंख्या को लेकर राजनीतिक दल अक्सर अपने-अपने वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति अपनाते दिखाई देते हैं। अनेक विश्लेषकों का मानना है कि यदि जनसंख्या के आंकड़ों का उपयोग केवल राजनीतिक ध्रुवीकरण या चुनावी लाभ के लिए किया जाएगा, तो यह राष्ट्रीय एकता और समावेशी विकास की भावना के विपरीत होगा। इसके विपरीत, चीन ने अपनी परिस्थितियों के अनुरूप लंबे समय तक कठोर जनसंख्या नियंत्रण नीति अपनाकर जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया, यद्यपि बाद में बदलती जनसांख्यिकीय चुनौतियों के कारण उसने उस नीति में संशोधन भी किया। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था अलग है, इसलिए यहां समाधान कठोर दमनात्मक उपायों के बजाय समान रूप से लागू होने वाली जनसंख्या नीति, महिला शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, परिवार नियोजन, जन-जागरूकता और कानून के निष्पक्ष अनुपालन में निहित है। जनसंख्या के प्रश्न को जाति, धर्म या वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठाकर राष्ट्रीय विकास, सामाजिक संतुलन और भविष्य की पीढ़ियों के हित के दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है।

विश्व जनसंख्या दिवस 2026 की थीम भी इसी दिशा में संकेत करती है कि यदि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और अवसर मिलेंगे, तो वे स्वयं जिम्मेदार नागरिक बनकर संतुलित परिवार और सतत विकास की दिशा में योगदान देंगे। भारत की लगभग आधी आबादी युवा है। यह जनसांख्यिकीय लाभांश तभी राष्ट्र की शक्ति बनेगा, जब यह शिक्षित, कुशल, स्वस्थ और आत्मनिर्भर होगा। अन्यथा यही विशाल युवा आबादी बेरोजगारी, असंतोष और सामाजिक चुनौतियों का कारण भी बन सकती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि देश में एक व्यापक, वैज्ञानिक और सर्वसम्मत राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर गंभीर विचार किया जाए। ऐसी नीति में समानता, पारदर्शिता, संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता मिले। इसके साथ ही जनसंख्या संबंधी किसी भी चर्चा में सामाजिक सौहार्द, तथ्यपरक विश्लेषण और जिम्मेदार सार्वजनिक विमर्श बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। किसी भी प्रकार की अतिरंजना या विभाजनकारी दृष्टिकोण समाधान नहीं, बल्कि नई समस्याओं को जन्म दे सकता है।

विश्व जनसंख्या दिवस हमें यह स्मरण कराता है कि विकसित भारत का सपना केवल आर्थिक विकास से पूरा नहीं होगा। इसके लिए जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन, मानव पूंजी में निवेश, महिलाओं का सशक्तिकरण, युवाओं को अवसर, प्रभावी सीमा प्रबंधन और दीर्घकालिक राष्ट्रीय नीति-इन सभी का समन्वित प्रयास आवश्यक है। यदि भारत समय रहते जनसंख्या संतुलन, मानव विकास और संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग की दिशा में ठोस कदम उठाता है, तो वर्ष 2047 तक विकसित, समृद्ध, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत का लक्ष्य अधिक यथार्थ रूप में साकार हो सकेगा। जनसंख्या केवल संख्या नहीं, बल्कि राष्ट्र की शक्ति है, बशर्ते वह शिक्षित, स्वस्थ, अनुशासित, उत्पादक और संतुलित हो। यही विश्व जनसंख्या दिवस का वास्तविक संदेश है।

-ललित गर्ग

रिश्तों की नींव में दरार-जब विश्वास की जगह हिंसा ले लेती है, तब परिवार ही सबसे असुरक्षित हो जाता है

-कांतिलाल मांडोत

हाल ही में आगरा में सामने आए उस हृदयविदारक मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया, जिसमें एक महिला पर अपने पति की हत्या कर शव को बाथरूम के फर्श के नीचे दफनाने का आरोप है। यह घटना केवल एक आपराधिक मामला नहीं है, बल्कि हमारे समाज के बदलते मनोविज्ञान, पारिवारिक मूल्यों के क्षरण और रिश्तों में बढ़ती कटुता का गंभीर संकेत भी है। जिस घर को सुरक्षा, स्नेह और विश्वास का प्रतीक माना जाता है, वही यदि भय और हिंसा का केंद्र बन जाए तो यह पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है।

आज का समय अभूतपूर्व तकनीकी प्रगति, आर्थिक अवसरों और आधुनिक जीवनशैली का दौर है, लेकिन दूसरी ओर मानवीय संवेदनाएं और रिश्तों की गर्माहट लगातार कमजोर होती दिखाई दे रही हैं। पति-पत्नी का संबंध भारतीय संस्कृति में सबसे पवित्र और विश्वासपूर्ण माना गया है। यह रिश्ता केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो परिवारों और अनेक भावनाओं का संगम होता है। जब इसी रिश्ते में अविश्वास, क्रोध, स्वार्थ और हिंसा प्रवेश कर जाते हैं, तब उसका परिणाम केवल एक परिवार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज की आत्मा को भी घायल करता है।

पिछले कुछ महीनों में देश के विभिन्न हिस्सों से पति या पत्नी द्वारा अपने जीवनसाथी की हत्या के कई मामले सामने आए हैं। कहीं अवैध संबंधों के कारण हत्या हुई, कहीं संपत्ति के विवाद ने रिश्ते खत्म कर दिए, तो कहीं लंबे समय से चले आ रहे घरेलू विवाद हिंसक रूप ले बैठे। इन घटनाओं ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया है कि जिन लोगों ने साथ जीने-मरने की कसमें खाईं, वे एक-दूसरे के प्राण लेने तक पहुंच रहे हैं।

यह भी सच है कि ऐसे अपराध समाज के अधिकांश परिवारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। देश में करोड़ों परिवार आज भी प्रेम, विश्वास और परस्पर सम्मान के साथ जीवन जी रहे हैं। लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं बार-बार सामने आती हैं, तो वे समाज के सामने गंभीर प्रश्न अवश्य खड़े करती हैं। क्या हमारी सहनशीलता कम हो रही है? क्या संवाद की जगह आक्रोश ने ले ली है? क्या छोटी-छोटी बातों का समाधान बातचीत से निकालने की बजाय हिंसा को आसान रास्ता समझा जाने लगा है?

आधुनिक जीवन की भागदौड़, आर्थिक दबाव, बढ़ती अपेक्षाएं, मानसिक तनाव और सामाजिक प्रतिस्पर्धा ने पारिवारिक जीवन को प्रभावित किया है। पति-पत्नी दोनों कामकाजी हों या एक ही व्यक्ति परिवार की जिम्मेदारी निभा रहा हो, हर स्थिति में मानसिक दबाव पहले की तुलना में कहीं अधिक है। यदि इन परिस्थितियों में संवाद समाप्त हो जाए, एक-दूसरे को समझने का प्रयास खत्म हो जाए और अहंकार रिश्तों पर हावी हो जाए, तो विवाद गहराते चले जाते हैं। ऐसे विवादों का समाधान कानून, परिवार, परामर्श या आपसी बातचीत से निकल सकता है, लेकिन हिंसा कभी समाधान नहीं हो सकती।

आगरा की घटना में जिस तरह शव को छिपाने का प्रयास किया गया, उसने लोगों को स्तब्ध कर दिया। यह घटना केवल हत्या तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसके बाद किए गए कथित प्रयासों ने भी समाज को विचलित किया। ऐसे मामलों में कानून अपना कार्य करता है और न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से दोषी या निर्दोष का निर्णय होता है। इसलिए किसी भी आरोपी को अंतिम रूप से दोषी मानना न्यायालय के निर्णय के बाद ही उचित होता है। फिर भी ऐसी घटनाएं यह अवश्य बताती हैं कि अपराध की मानसिकता कितनी भयावह हो सकती है।

आज परिवारों में रिश्ते कभी-कभी सूत के धागे जैसे नाजुक प्रतीत होते हैं। छोटी-सी गलतफहमी, आर्थिक विवाद, संदेह या अहंकार वर्षों पुराने संबंधों को तोड़ देता है। पहले परिवार के बड़े-बुजुर्ग विवादों को बैठकर सुलझाते थे। संयुक्त परिवारों में संवाद के अधिक अवसर होते थे। अब एकल परिवारों के बढ़ने, सामाजिक दूरी और व्यस्त जीवनशैली के कारण कई लोग अपनी मानसिक परेशानियां भीतर ही भीतर दबाए रहते हैं। जब भावनाएं लंबे समय तक दबती रहती हैं, तो कभी-कभी उनका विस्फोट अत्यंत दुखद रूप में सामने आता है।

यह भी आवश्यक है कि समाज किसी एक वर्ग या लिंग को दोषी ठहराने की प्रवृत्ति से बचे। अपराध करने वाला व्यक्ति पुरुष भी हो सकता है और महिला भी। कानून की दृष्टि में अपराधी केवल अपराधी होता है। इसलिए किसी एक घटना के आधार पर पूरे समाज, किसी पीढ़ी या किसी लिंग के बारे में व्यापक निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपराध के कारणों को समझें और उन्हें रोकने के उपाय खोजें।

आज मानसिक स्वास्थ्य पर भी गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। तनाव, अवसाद, गुस्सा और संबंधों में बढ़ती दूरी को समय रहते पहचानना और उनका समाधान करना अत्यंत आवश्यक है। यदि पति-पत्नी के बीच मतभेद हैं, तो परिवार, मित्र, विवाह परामर्शदाता या कानूनी प्रक्रिया की सहायता ली जा सकती है। अलग होना पड़े तो वह भी कानून के दायरे में और गरिमा के साथ होना चाहिए। तलाक एक वैधानिक प्रक्रिया है, जबकि हत्या मानवता और कानून—दोनों के विरुद्ध जघन्य अपराध है।

मीडिया और सोशल मीडिया की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। अपराधों की जानकारी समाज तक पहुंचाना आवश्यक है, लेकिन उनके सनसनीखेज चित्रण की बजाय यह भी बताया जाना चाहिए कि ऐसे अपराधों के पीछे कौन-से सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण काम करते हैं तथा उनसे बचाव कैसे किया जा सकता है। समाज को भय और सनसनी नहीं, बल्कि जागरूकता और संवेदनशीलता की आवश्यकता है।

बच्चों और युवाओं को बचपन से ही संवाद, सहनशीलता, नैतिकता और सम्मानजनक व्यवहार की शिक्षा देना समय की मांग है। परिवार केवल आर्थिक व्यवस्था नहीं, बल्कि भावनात्मक सुरक्षा का आधार होता है। यदि घरों में प्रेम, विश्वास और धैर्य का वातावरण बनेगा, तो समाज भी अधिक सुरक्षित और संवेदनशील बनेगा।

हर दिन दर्ज होने वाले हत्या, मारपीट, अपहरण और अन्य गंभीर अपराध निश्चित रूप से चिंता पैदा करते हैं। लेकिन इन घटनाओं के बीच यह याद रखना भी जरूरी है कि समाज में आज भी असंख्य लोग ईमानदारी, प्रेम और पारिवारिक मूल्यों के साथ जीवन जी रहे हैं। हमें उन्हीं सकारात्मक मूल्यों को मजबूत करना होगा, ताकि हिंसा की प्रवृत्ति को रोका जा सके। रिश्ते विश्वास से बनते हैं और विश्वास टूटने पर सबसे बड़ी क्षति केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज की होती है। यदि हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित, संवेदनशील और संस्कारित वातावरण में जीवन जीएं, तो हमें संवाद, धैर्य, परस्पर सम्मान और नैतिक मूल्यों को फिर से अपने पारिवारिक जीवन का आधार बनाना होगा। यही वह मार्ग है जो समाज को हिंसा से दूर और मानवीयता के निकट ले जा सकता है।

इंदौर बाजार भाव

इंदौर। एजेंसी। शुक्रवार को अनाज मंडी में व्यापार की मात्रा कम ही रही। चना 6050-6100 रू. प्रति क्विंटल पर मजबूत रहा। खाद्य तेलों में व्यापार ठंडा-ठंडा ही रहा। तिलहनों में सोयाबीन बाजार 7000 रू. प्रति क्विंटल पर सुर्ख रहे। किराना जिंसों में ग्राहकी ठंडी-ठंडी ही रही। व्यापारिक सूत्रों के अनुसार शुक्रवार को अनाज मंडी में व्यापार की मात्रा कम ही रही। चने में छुटपुट माँग के बीच बाजार 6050-6100 रू. प्रति क्विंटल पर मजबूत बने रहे। खाद्य तेलों में व्यापार ठंडा-ठंडा ही रहा। तिलहनों में सोयाबीन बाजार 7000 रू. प्रति क्विंटल पर सुर्ख देखे गये। उधर, किराना जिंसों में ग्राहकी ठंडी-ठंडी ही रही। भाव इस प्रकार रहे-

किराना- शक्कर 4450-4520, खोपरा गोला 380-420, खोपरा बूरा 3200-6800 (15 कि.ग्रा.), जीरा राजस्थान 280-285, ऊंझा हल्का 290-295, बेस्ट 315-325, हल्दी निजामाबाद 210-230, सांगली 275-280, साबूदाना हल्का 5200-5350, मीडियम 5450-5600, बेस्ट 6000-6100, सच्चा मोती 5700, मोरधन 7200-8200, सौंफ मोटी 275-350, बेस्ट 350-400, सौंफ बारिक 180-300, एक्स्ट्रा बोल्ड 350-400, राई दाल 90-95, सरसो दाल 85-95, कालीमिर्च एटम 750-755, मीनी मटरदाना 770-800, मटरदाना 825-850, खसखस अनक्लीन 1150-1250, क्लीन 1300-1350, दालचीनी 250-260, जायफल 725-750, वाद्यान फूल 405-600, शाहजीरा 350-400, तेजपान 90-100, पत्थर फूल 235-425, जावत्री 1675-1750, केसर 200-250, नाग केसर 925-975, सौंठ 325-500, धोली मूसली 1400-1600, लौंग 700-720, बेस्ट 760-790, हींग (वनदेवी 751) 3450, पाउच 10 ग्राम 3550, सिंघाडा छोटा 100-120, बड़ा 120-130, सिंदूर (25 कि.ग्रा. पैकिंग) 7300, देशी कपूर 850-860, बेस्ट 875-900, पूजा बादाम 115-125, बेस्ट 220-230, पूजा सुपारी 425-450, अरीठा 180-200, हरी इलायची एवरेज 2700-2800, मीडियम 2900-3050, बेस्ट 3150-3250, एक्ट्रा बेस्ट 3300-3500, पानबार 2450, बड़ी इलायची 1800-2100, तरबूज मगज 525-550, काजू (240) 880-925, काजू (210) 950-1000, काजू डब्ल्यू (340) 840-870, काजू एस.डब्ल्यू (300) 800-825, काजू जे.एच. 840-870, टुकड़ी 780-820, बादाम मगज 840-870, सिंगापुरी 850-860, बादाम टांच 700-725, अखरोट 590-850, अखरोट गिरी 1250-1550, जर्दालु 375-500, बेस्ट 550-650, किशमिश कंधारी 450-600, इंडियन 400-450, चारौली 1450-1750, मुनक्का 350-550, अंजीर 850-950, मखाना 850-1200, बेस्ट 1350-1400, खारक एवरेज 75-80, मीडियम 90-130, बेस्ट 140-260, पिस्ता पिशोरी 2900-3100, कंधारी 2500-2700, नमकीन पिस्ता 1000-1150, बेस्ट 1200-1250, गेहूँ आटा 1820, मैदा कट्टा 1850, रवा कट्टा 1880, बेसन 4675 (50 कि.ग्रा.), नारियल (120) 2500, (160) 2900, (200) 3100, (250) 3600,

तेल- सींगदाना 1600-1620, मुम्बई 1620, राजकोट तेलिया 2530, सोया साल्वेंट 1390-1400, सोया रिफाइंड 1455-1460, कपास्या 1500-1510, धूलिया 1510-1520, कड़ी 1520,

रात की धारणा- गुजरात लुज 1600-1610, मुम्बई पाम 1665, मुम्बई सोया 1670,

खली- कपस्या खली (60 कि.ग्रा.) इन्दौर 2600, देवास-उज्जैन 2600, खंडवा-बुरहानपुर 2575, अकोला 3925 (प्रति क्विंटल)

तिलहन- सरसो 7600-7800, रायडा 6800, सोयाबीन 7000, टोली (महुआ बीज) 5000-5100, करंज 4400-4500, अलसी 8500-9000, अरंडी 4500-4700, तिल्ली पुरानी 6500-7000, तिल्ली नई 7200-7500,

दलहन- चना कांटेवाला बेस्ट 6050-6100, एवरेज 5900-6000, विशाल 5900-6000, महाराष्ट्र विशाल 5900-5950, काबूली चना डॉलर 7000-8300, काबूली चना रशियन 5600-5800, बिटकी 5200-5300, मसूर बेस्ट 5900-5950, एवरेज 5800-5850, मूंग गर्मी बेस्ट नया 7100-7250, मूंग पुराना बोल्ड 7500-7700, मीडि?यम 7400-7700, मोगर 5500-6500, तुअर निमाड़ी बेस्ट 7200-7400, एवरेज 6500-6600, हल्की 6400-6500, महाराष्ट्र सफेद 7400-7500, महाराष्ट्र लाल 7700-7900, उड़द बेस्ट 9100-9200, एवरेज 9000-9100, शंकर 8800-9000, हल्की 8600-8700,

दाल- चना दाल एवरेज 7400-7500, मीडियम 7600-7700, बोल्ड 7900-8100, तुअर दाल सवा नं. 8200-8400, तुअर दाल 7300-7600, तुअर दाल मीडियम 8500-8800, बेस्ट 9900-10200, मसूर दाल 6800-7100, मूंग दाल 8700-8900, मूंग मोगर 10100-10600, उड़द दाल 9900-10300, मोगर 10800-11000,

अनाज- गेहूं मिल क्वालिटी 2500-2550, लोकवन एवरेज 2550-2650, बेस्ट 2750-2800, मालवराज 2600-2650, गेहूँ पूर्णा एवरेज 2400-2550, बेस्ट 2650-2750, मक्का पीली 1975-2000,

चावल- चावल हंसा सफेद 2900-3100, सेला 3500-3700, परमल 3400-3500, दुबराज 4500-5500, राजभोग 7500, काली मुंछ डिनर किंग 9000, बासमती दुबार 9500-10000, मीनी दुबार 8000-8500, मोगरा 5000-7000, तिबार 10500-11500, बासमती (921) 12000-13000, बासमती सेला 7500-9500, पोहा 4500-5100,

मावा- इन्दौर 340, उज्जैन 280, रतलाम 280 रू. प्रति किलो।

इंदौर सर्राफा बाज़ार

इन्दौर। एजेंसी। शुक्रवार को स्थानीय सराफा बाजार में व्यापार की मात्रा कम ही रही। दोनों ही मूल्यवान धातुओं में बाजार नरमी के रहे। भाव इस प्रकार रहे-

चाँदी (9999) 225000, चाँदी (99) 224900, टंच 224300, सिक्का 2600, सोना 10 ग्राम 142400,

रुपया तेजी के साथ बंद

मुंबई। एजेंसी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले शुक्रवार को भारतीय 15 पैसे की तेजी के साथ ही 95.32 पर बंद हुआ। इससे पहले आज सुबह रुपया शुरुआती कारोबार में रुपया 15 पैसे मजबूत होकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.32 पर पहुंच गया। अमेरिकी डॉलर के कमजोर रुख और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बावजूद कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से घरेलू मुद्रा को बल मिला। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की बिकवाली और पश्चिम एशिया में तनाव से जुड़ी अनिश्चितताओं का स्थानीय मुद्रा पर दबाव रहा, जबकि घरेलू शेयर बाजारों में दिन की मजबूत शुरुआत से रुपये को समर्थन मिला। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, डॉलर के मुकाबले 95.27 पर खुला। बाद में 95.32 प्रति डॉलर पर आ गया जो पिछले बंद भाव से 15 पैसे की बढ़त दिखात है।

शेयर बाजार में मजबूत उछाल

सेंसेक्स 828 अंक चढ़ा, निफ्टी 24200 के पार पहुंचा

मुंबई। एजेंसी। भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को जोरदार वृद्धि दर्ज की गई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 1 फीसदी से अधिक का उछाल आया। सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी टीसीएस के बेहतर तिमाही नतीजों और सकारात्मक वैश्विक संकेतों ने निवेशकों के उत्साह को बढ़ाया। छोटे और मझोले बाजार ने भी बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन किया। निफ्टी स्मॉलकैप 100 और निफ्टी मिडकैप 100 सूचकांकों में 1.5 फीसदी तक की वृद्धि हुई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और रियल एस्टेट के शेयर सबसे आगे रहे। बाजार में चौतरफा खरीदारी देखने को मिली। सेंसेक्स 828 अंक (1.08 प्रतिशत) की तेजी के साथ 77,569 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 244 अंकों (1.02 प्रतिशत) की तेजी रही, ये 24,206 पर पहुंच गया। भारतीय शेयर बाजार में यह उछाल कई कारणों से आया। टीसीएस के तिमाही

नतीजे उम्मीद के मुताबिक रहे। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा। वैश्विक बाजारों से भी सकारात्मक संकेत मिले। इन सभी कारकों ने बाजार को ऊपर उठाने में मदद की। 2026-2027 की पहली तिमाही के नीतेजों के बाद टीसीएस के शेयर में आज 0.90 प्रतिशत की तेजी रही। ये 2,068 रुपए पर बंद हुआ। बीते 6 महीने में टीसीएस का शेयर करीब 30 परसेंट गिरा है। वहीं एक साल में ये 40 प्रतिशत टूटा है। टीसीएस का नेट प्रॉफिट एक साल पहले की समान तिमाही के 12,760 करोड़ रुपए के मुकाबले 5 प्रतिशत बढकर 13,349 करोड़ रुपए रहा है। इस अवधि के दौरान ऑपरेशंस से मिलने वाला रेवेन्यू भी सालाना आधार पर 14 प्रतिशत बढ ?र 72,275 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। कंपनी के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 12 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दी है और इसके लिए 15 जुलाई को रिकॉर्ड डेट तय किया है। वहीं वैश्विक बाजारों में मिला-जुला रुख रहा। एसएंडपी 500 वायदा 0.1 फीसदी गिरा।

ई-20 पेट्रोल से गाड़ियों में लगे रबर पार्टस को हो रहा नुकसान, माइलेज भी घटा

नई दिल्ली। एजेंसी। देशभर में इन दिनों ई-20 पेट्रोल को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। कई लोग ई-20 पेट्रोल के कारण गाड़ियों के इंजन खराब होने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार का कहना है कि ई-20 पेट्रोल पूरी तरह से सेफ है और इसका गाडियों पर कोई खास नुकसान नहीं है। इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ई-20 पेट्रोल को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की सिफारिश की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक ई10 के लिए बने वाहनों में ई20 पेट्रोल के इस्तेमाल से फ्यूल सिस्टम के रबर वाले हिस्सों जैसे होज, गैसकिट, सील और ओ-रिंग में खराबी देखी गई। रिसर्च में कहा गया है कि इन पुर्जों को बदलने की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि रिपोर्ट अभी सार्वजनिक रूप से बाहर नहीं आई है, लेकिन अहम रिपोर्ट सामने आई है। हालांकि यह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन सरकार और गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों के बीच यह अहम दस्तावेज रही है। ई10 गाडियों पर ई20 फ्यूल के असर को लेकर की गई स्टडी में यह भी बताया गया कि फोर-व्हीलर इंजन ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के दौरान, एक बीएस-4 इंजन का परफॉर्मेंस ई20 के साथ ठीक रहा, लेकिन बीएस-6 टर्बो-चार्ज्ड इंजन में 265 घंटे की ड्यूरेबिलिटी के बाद समस्या देखी गई। स्टडी के जिस हिस्से में इंजन ड्यूरेबिलिटी की बात की गई, उसमें बताया गया कि दो फोर व्हीलर गाड़ी बनाने वाली कंपनियों ने यह टेस्ट किया। एक निर्माता के इंजन ने 400 घंटे तक बिना किसी समस्या के ई20 पर अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि दूसरे निर्माता के इंजन में कुल 809 घंटे के परीक्षण के दौरान एग्जॉस्ट वाल्व में थर्मोमैकेनिकल फेल्योर देखा गया।

यूपीआई का नया अवतार, बायोमेट्रिक भुगतान ने तोड़े सारे रिकॉर्ड!

नई दिल्ली। एजेंसी। भारत में डिजिटल भुगतान के परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा जा रहा है, जहां यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। जून 2024 में फिंगरप्रिंट या चेहरे की पहचान जैसे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से रिकॉर्ड 61.1 करोड़ लेनदेन दर्ज किए गए, जिनकी कुल वैल्यू 25,416 करोड़ रुपये थी। यह आंकड़ा उसी महीने हुए कुल यूपीआई लेनदेन का 2.7 फीसदी है, जो पिछले साल शुरू की गई इस सुविधा की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता और स्वीकार्यता को दर्शाता है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) की एक व ?रिष्ठ अ ?धिकारी ने इस वृद्धि को यूपीआई उपयोगकर्ताओं द्वारा आसान और कुशल भुगतान अनुभव को तरजीह देने का प्रमाण बताया। उनका मानना है कि जैसे-जैसे अधिक उपयोगकर्ता इस सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके को अपनाएंगे, इसका इस्तेमाल और बढ़ेगा। कई प्रमुख बैंक और यूपीआई ऐप्स पहले से ही अपने ग्राहकों को यह सुविधा प्रदान कर रहे हैं, जिससे डिजिटल लेनदेन की प्रक्रिया और सुगम हो गई है। एनपीसीआई के अनुसार, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यूपीआई पिन पर निर्भरता को कम करता है, लेनदेन को गति देता है और सफलता दर में सुधार करता है। यह पीयर-टू-पीयर और पीयर-टू-मर्चेंट दोनों तरह के लेनदेन के लिए फायदेमंद है, जिससे उपयोगकर्ता अनुभव बेहतर होता है। फोनपे, एनबीपीएसएल के भीम ऐप, सीआरईडी और विभिन्न बैंकिंग ऐप्स सहित कई प्रमुख प्लेटफॉर्म पहले ही इस सुविधा को अपने उपयोगकर्ताओं के लिए शुरू कर चुके हैं, जिससे बायोमेट्रिक भुगतान का इकोसिस्टम मजबूत हो रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी डिजिटल भुगतानों के लिए कम से कम दो अलग-अलग ऑथेंटिकेशन फैक्टर की आवश्यकता होती है, जिसमें यूपीआई के लिए एक फैक्टर का गतिशील रूप से उत्पन्न या सिद्ध होना अनिवार्य है। बायोमेट्रिक तरीका इन आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भुगतान को और अधिक सुरक्षित बनाता है।

मेष- आज आपके लिए मेहनत का फल मिलने का दिन है। रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है और आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रगति कुछ लोगों को खटक सकती है, इसलिए अपनी योजनाएं फिलहाल अपने तक ही रखें। घर में सुख-सुविधाओं से जुड़ी खरीदारी हो सकती है और संतान से जुड़ी चिंताओं में भी राहत मिलने के संकेत हैं। कोई भी फैसला जल्दबाजी या गुस्से में लेने से बचें। इस समय उधार दिए हुए पैसे की वापसी मुश्किल है। बेकार की गतिविधियों से दूर रहें, क्योंकि बैठे-बिठाए कोई परेशानी आ सकती है। युवा लोग जल्दी कामयाबी पाने के चक्कर में गलत रास्ता न अपनाएं।

वृषभ- भाग्य आज आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। नौकरी में प्रमोशन या कोई अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापार में नए अवसर और नई साझेदारी लाभ दिला सकती है। जीवनसाथी के साथ मधुर पल बिताने का मौका मिलेगा, लेकिन दूसरों की बातों में आकर किसी विवाद का हिस्सा बनने से बचें।

मिथुन- आज आमदनी के नए रास्ते खुल सकते हैं, लेकिन खर्चों पर भी नजर रखना जरूरी होगा। जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें। परिवार में किसी शुभ कार्य की तैयारी शुरू हो सकती है और भविष्य के लिए कोई बड़ा निवेश करने का विचार भी बन सकता है। यात्रा के दौरान अपने सामान का विशेष ध्यान रखें।

कर्क- आज का दिन कई सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। धन और संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ मिलने के संकेत हैं। यदि कोई कानूनी मामला चल रहा है तो सतर्कता से आगे बढ़ें। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलने की संभावना है। कुछ नकारात्मक सोच वाले लोग आपकी आलोचना या बुराई कर सकते हैं, लेकिन चिंता न करें, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। फाइनेंस से जुड़े लेन-देन करते समय बहुत सावधानी रखें। कोई गलती आपको परेशानी में डाल सकती है।

सिंह- आज आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा दोनों चरम पर रहेंगे। धार्मिक और सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। प्रेम संबंधों में नया मोड़ आ सकता है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से राहत मिलेगी। व्यापार में भी कोई बड़ा और लाभदायक बदलाव संभव है। इस समय नई जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर आएंगी। ध्यान रखें, लापरवाही और देरी की वजह से जरूरी काम रुक सकते हैं। भाइयों के साथ संबंध मजबूत रखें। इनकम के साथ-साथ खर्चे भी ज्यादा रहेंगे।

कन्या- आज सोच-समझकर लिया गया हर फैसला आपके पक्ष में जाएगा। शिक्षा और करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। सामाजिक सम्मान बढ़ेगा और कार्यक्षेत्र में प्रशंसा या प्रमोशन मिलने की संभावना है। संपत्ति से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण फैसला भी आज आपके पक्ष में हो सकता है। कोई भी फैसला लेते समय या काम करते समय उससे जुड़ी पूरी जानकारी लेना जरूरी है। जल्दबाजी नुकसानदायक रहेगी। स्वभाव में गुस्सा और ईगो की वजह से घर का माहौल थोड़ा अस्त-व्यस्त हो सकता है।

तुला- लंबे समय से रुके हुए काम आज पूरे होने की संभावना है। परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। मन की कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है जिससे दिन यादगार बन जाएगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है।

वृश्चिक- आज आपका अनुभव आपको सफलता की ओर ले जाएगा। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के नए अवसर मिलेंगे। संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है। नया वाहन खरीदने या पुराने कर्ज को कम करने की दिशा में भी सकारात्मक कदम उठ सकते हैं। दूसरों के मामलों में दखल न दें। स्थितियां मजबूत करने के लिए किसी गलत काम का सहारा न लें। सहज तरीके से अपने काम निपटाते जाएं। महिलाओं को ज्यादा काम की वजह से व्यवस्था बनाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है।

धनु- आज व्यापार और निवेश दोनों में लाभ मिलने के अच्छे संकेत हैं। नई योजनाएं भविष्य में बड़ा फायदा दे सकती हैं। परिवार के साथ तालमेल बनाए रखें और जीवनसाथी की भावनाओं को समझें। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। इसका कारण गुस्से पर नियंत्रण न रख पाना हो सकता है। इन बातों का असर आपकी नींद पर भी पड़ सकता है।

मकर- आज व्यस्तता ज्यादा रहेगी, लेकिन मेहनत रंग भी लाएगी। व्यापार के रुके हुए काम पूरे होंगे। परिवार के साथ खुशियां बांटने का मौका मिलेगा और किसी जरूरतमंद की मदद करके मन को संतोष मिलेगा। यात्रा और बातचीत के दौरान सावधानी रखना बेहतर रहेगा।

कुंभ- आज सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी के योग हैं। कार्यक्षेत्र में मनचाहा काम मिलने से उत्साह बना रहेगा। ससुराल पक्ष से आर्थिक सहयोग मिल सकता है। हालांकि किसी छोटी बात को बड़ा विवाद बनने से रोकने के लिए धैर्य और समझदारी जरूरी होगी।

मीन- आज का दिन खुशियों और नए अवसरों से भरा रहेगा। आपकी मीठी वाणी लोगों को प्रभावित करेगी। परिवार में विवाह से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। व्यापार में नए विचार सफलता का रास्ता खोलेंगे और यात्रा के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपके काम आ सकती है।

शब्दजाल - 8316

र	क	ल	ड्री	म	ही	ला	धी	सी	ल	ज
र	जि	ल	दे	क्रां	ति	ड्ड	इं	म	ला	ई
त	स	म	ल	र्म	छ	रा	रा	औ	म	द
ब	ज	ज	हा	पु	र	म	प	र	हा	ब
म	गा	म	ग	दे	लं	हा	तू	गी	रा	र्नि
स	म	व	श	ह	व	रा	ना	म	णा	ग
त्ते	ज	स	त	हू	प	जा	श	स	ला	ट्रे
पे	बू	दा	ई	ह	र	सा	फ	ल	श	न
स	र	चे	न	म	हा	न	री	ना	प	रु
त्ता	पा	ला	ल	शो	ले	दु	म	ज	दू	र
ह	रा	जी	व	गां	धी	रा	क	या	म	त

शब्दजाल में 'म' से शुरु होने वाले दस शब्द ढूंढिए. दिये गए शब्द उपर से नीचे व तिरछे हो सकते हैं.

महान, मजबूर, मजदूर, महिला, महाराणा, महादेव, मसलना, मलाई, मशहूर, महाराजा

शब्दजाल - 8315 का हल

आ	घा	त	ह	दा	प	र	तू	ग	झ	आ
ज	अ	ल	म	आ	त	ता	यी	तें	शा	ई
अं	इ	नु	दि	ल	दा	ल	ढा	र	ला	ना
आ	कु	अ	ल	बे	ला	क	ई	रि	श	लौ
स	मा	श	आ	तं	क	स	अ	ग	वी	ट
री	रं	दा	चु	व	लि	आ	वा	ग	म	न
आ	गा	ल	के	गा	आ	म	र	कौ	या	ले
ग	बा	आ	रा	म	क	रो	प्रे	ग	श	थ
म	स	मि	न	व	न	ज	ग्य	शा	जू	द
न	र	ल	म	ह	र	औ	के	स	प	ना
थो	आ	स	मा	न	हो	ग	या	दु	र	क

Jagrutidaur.com, Bangalore

दैनिक पंचांग

11 जुलाई 2026 को सूर्योदय के समय की ग्रह स्थिति

ग्रह	स्थिति
सूर्य	मिथुन में
चंद्र	वृष में
मंगल	वृष में
बुध	मिथुन में
गुरु	कर्क में
शुक्र	सिंह में
शनि	मीन में
राहु	कुंभ में
केतु	सिंह में

राहुकाल 9.00 से 10.30 बजे तक

लग्नारंभ समय	
कर्क	05.50 बजे से
सिंह	08.07 बजे से
कन्या	10.18 बजे से
तुला	12.29 बजे से
वृश्चिक	14.44 ब.से
धनु	17.00 बजे से
मकर	19.05 बजे से
कुंभ	20.51 बजे से
मीन	22.24 बजे से
मेष	23.55 बजे से
वृष	01.35 बजे से
मिथुन	03.33 बजे से

शनिवार 2026 वर्ष का 192 वा दिन **दिशाशूल** पूर्व **ऋतु** वर्षा। **विक्रम संवत्** 2083 **शक संवत्** 1948 **मास** आषाढ़ (दक्षिण भारत में ज्येष्ठ) **पक्ष** कृष्ण **तिथि** एकादशी 05.23 बजे तदनन्तर द्वादशी 02.05 बजे रात्र को समाप्त। **नक्षत्र** कृत्तिका 11.04 बजे को समाप्त। **योग** गण्ड 00.06 बजे रात्र को समाप्त। **करण** बालव 05.23 बजे, कौलव 15.47 बजे तदनन्तर तैतिल 02.05 बजे रात्र को समाप्त। **चन्द्रायु** 24.9 घण्टे **रवि क्रान्ति** उत्तर 22° 08' **सूर्य** उत्तरायन **कलि अहर्गण** 1872767 **जूलियन दिन** 2461232.5 **कलियुग संवत्** 5128 **कल्पारंभ संवत्** 1972949128 **सृष्टि ग्रहारंभ संवत्** 1955885128 **वीरनिर्वाण संवत्** 2552 **हिजरी सन्** 1448 **महीना** मोहर्रम **तारीख** 25 **विशेष** कृष्ण रामलक्ष्मण द्वादशी, गौण योगिनी एकादशी, विश्व जनसंख्या दिवस।

दिन का चौघड़िया				
काल	05.55	से	07.23	बजे तक
शुभ	07.23	से	08.51	बजे तक
रोग	08.51	से	10.19	बजे तक
उद्वेग	10.19	से	11.46	बजे तक
चर	11.46	से	01.14	बजे तक
लाभ	01.14	से	02.42	बजे तक
अमृत	02.42	से	04.10	बजे तक
काल	04.10	से	05.37	बजे तक

रात का चौघड़िया				
लाभ	05.37	से	07.10	बजे तक
उद्वेग	07.10	से	08.42	बजे तक
शुभ	08.42	से	10.14	बजे तक
अमृत	10.14	से	11.47	बजे तक
चर	11.47	से	01.19	बजे तक
रोग	01.19	से	02.51	बजे तक
काल	02.51	से	04.23	बजे तक
लाभ	04.23	से	05.56	बजे तक

चौघड़िया शुभाशुभ- शुभत्व श्रेष्ठ शुभ, अमृत व लाभ, **मध्यम** चर, **अशुभ** उद्वेग, रोग व काल। सभी समय भारतीय मानक समय की मध्य रेखा बिन्दु के आधार पर है अतः आप अपने स्थानीय समयानुसार ही देखें। ■ Jagrutidaur.com, Bangalore

प्रसंगतः प्रसन्न रहने की कला

एक संत सदा प्रसन्न रहते थे। वह हर बात पर ठहाके लगाते रहते। कुछ चोरों को यह बात अजीब लगती थी। वे समझ नहीं पाते थे कि कोई व्यक्ति हर समय इतना खुश कैसे रह सकता है। चोरों ने यह सोच कर कि संत के पास अपार धन होगा, उनका अपहरण कर लिया। वे उन्हें दूर जंगल में ले गए और बोले, ' सुना है संत कि तुम्हारे पास काफी धन है, तभी इतने प्रसन्न रहते हो। सारा धन हमारे हवाले कर दो वरना तुम्हारी जान की खैर नहीं। ' संत ने एक-एक कर हर चोर को अलग-अलग बुलाया और कहा, 'मेरे पास सुखदा मणि है मगर मैंने उसे तुम चोरों के डर से जमीन में गाड़ दिया है। यहां से कुछ ही दूर पर वह स्थान है। अपनी खोपड़ी के नीचे चंद्रमा की छाया में खोदना, शायद मिल जाए। ' यह कहकर संत एक पेड़ के नीचे सो गए। सभी चोर अलग-अलग दिशा में जाकर खोदने लगे। जरा सा उठते चलते तो छाया भी हिल जाती और उन्हें जहां-तहां खुदाई करनी पड़ती। रात भर में सैकड़ों छोटे-बड़े गड्ढे बन गए पर कहीं भी मणि का पता नहीं चला। चोर हताश होकर लौट आए और संत को भला-बुरा कहने लगे। संत हंस कर बोले, 'मूर्खों, मेरे कहने का अर्थ समझो। खोपड़ी तले सुखदा मणि छिपी है अर्थात उस में श्रेष्ठ विचारों के कारण मनुष्य प्रसन्न रह सकता है। तुम भी अपना दृष्टिकोण बदलो और जीना सीखो।' चोरों को यथार्थ का बोध हुआ। वे भी अपनी आदतें सुधार कर प्रसन्न रहने की कला सीखने लगे।

फिल्म वर्ग पहेली- 7260

बायें से दायें:-

१. शाहरूख, अपूर्व अग्निहोत्री, महिमा की 'किसी रोज तुम से' गीत वाली फिल्म-४
४. 'हम बेवफा हरगिज न थे' गीत वाली धर्मेन्द्र, जीनत अमान की फिल्म-४
६. विनोद मेहरा, रीना राय की 'दिल का तोहफा लाई हूँ' गीत वाली फिल्म-४
९. 'मुझे दुनियावलों शरबी' गीत वाली दिलीपकुमार, वैजयंती की फिल्म-३
११. अजय, सैफ, विवेक, करीना, बिपाशा की 'बीड़ी जलई' गीतवाली फिल्म-४
१३. 'आ ये हसीना रात' गीत वाली जीतेंद्र, आदित्य, एकता की फिल्म-४
१६. अक्षयकुमार, रवीना की 'क्यूं आँचल हमारा गिरा जा' गीत वाली फिल्म-२
१७. 'आँखों से दिल में' गीत वाली फराज खान, सुमन रंगनाथन की फिल्म-३
१८. दिलीपकुमार, सायरा की 'सारे शहर में आपसा कोई' गीत वाली फिल्म-३
१९. 'रात दुल्हन बनी चॉद दूल्हा बना' गीत वाली जीतेंद्र, बिस्वजीत, माला सिन्हा, मुमताज की फिल्म-३
२३. धर्मेन्द्र, संजीव, शर्मिला की 'जिंदगी है क्या बोलो' गीत वाली फिल्म-४
२५. 'दिल गम से' गीत वाली विजय, सुरैया की फिल्म जो सुरैया की अंतिम फिल्म थी-२
२६. संजयदत्त, उर्मिला की 'ओ भंवरे देखो हम दीवानों को' गीत वाली फिल्म-२
२७. आमिर, ममता कुलकर्णी की 'बाजी' में मुख्यमंत्री विश्वासराव चौधरी की भूमिका किसने की थी-२,३
२८. सनी, सुनील शेट्टी, शिल्पा की 'कोई परी आती नहीं' गीत वाली फिल्म-२
२९. फिल्म 'सात रंग के सपने' में अरविंद स्वामी के साथ नायिका कौन थी-२

ऊपर से नीचे:-

१. अमिताभ, शाहरूख, सुनील, रानी, जूही की फिल्म-३
२. 'दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब' गीत वाली फिल्म-३
३. नसीरूद्दीनशाह, पूजा भट्ट की फिल्म-२
४. 'आते जाते हुए मैं सब पे नजर' गीत वाली फिल्म-२
५. इंद्रकुमार, आयशा जुल्का की फिल्म-३
७. आर्यन वैद, सोनाली कुलकर्णी की मकरंद देशपांडे निर्देशित फिल्म-३
८. सुनीलदत्त, आशा पारेख की फिल्म-२
१०. 'जादू तेरी नजर' गीत वाली फिल्म-२
११. अतीन भल्ला, संदली सिन्हा की फिल्म-२
१२. 'लम्हा लम्हा जिंदगी है' गीत वाली फिल्म-४
१३. मोहित अहलावत, निशा की फिल्म-२
१४. 'ये वादा करो चाँद' गीत वाली फिल्म-४
१५. मनोज बाजपेयी, रेखा, करिश्मा की फिल्म-३
१६. 'हम दर्द के मारों का इतना ही' गीत वाली फिल्म-२
२०. धर्मेन्द्र, संजीवकुमार, आशा की फिल्म-३
२१. 'जागे जागे नैनों में' गीत वाली फिल्म-३
२२. आफताब शिवदासानी, अमीषा पटेल, एशा देओल की फिल्म-४
२३. 'जब जब प्यार पे पहरा हुआ' गीत वाली फिल्म-३
२४. जीतेंद्र, श्रीदेवी की फिल्म-३
२५. 'इंतहा हो गई इंतजार की' गीत वाली अमिताभ, जया प्रदा की फिल्म-३

फिल्म वर्ग पहेली-7259

को	ह	रा	■	आँ	धी	■	आ	नं	द
ह	■	म	■	खें	■	जो	र	दा	र
रा	जा	जा	नी	■	ध	र	ती	■	मि
म	■	ने	■	क	र्मा	■	■	सा	या
■	रा	■	आ	■	त्मा	■	सा	ज	न
रा	स्ते	प्या	र	के	■	श	■	औ	■
■	का	■	जू	■	मे	रा	ध	र	म
स	प	ने	■	दु	ला	रा	■	आ	ह
■	थ	■	प्या	■	■	■	स	वा	ल
प्या	र	का	सा	या	■	सू	र	ज	■

■ Jagrutidaur.com, Bangalore

सूडोकु नवताल- 7569

★★★✯✩ मध्यम

2	9		3	1			8	
3	6		2		7		9	
		7			6		2	1
	7		1					
1	3			4			7	2
					5		4	
6	2		4			9		
	5		6		9		1	8
	1			5	3		6	4

Jagrutidaur.com, Bangalore

■ प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
■ प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
■ पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते .
■ पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -7568 का हल

3	9	7	5	1	4	6	8	2
1	2	8	6	9	3	4	5	7
6	4	5	2	8	7	1	3	9
5	7	3	4	6	9	2	1	8
2	1	9	7	5	8	3	4	6
4	8	6	3	2	1	7	9	5
9	3	2	8	4	6	5	7	1
7	6	1	9	3	5	8	2	4
8	5	4	1	7	2	9	6	3

शब्द पहेली - 8784

बाएँ से दाएँ

1. नियंत्रण, घोड़े की रास-3
3. ध्वज, झंडा-3
5. माहिर, होशियार-2
6. बेल, लतिका-2
8. अस्वीकृत करना-4
11. अदृश्य-3
13. फटकार, धिक्कार-3
14. अधर, होठ-2
15. सलाह, सुझाव-2
16. आश्रय-3
18. अनुमान, अंदाज-3
20. आलता, माहुर-4
23. नासिका-2
25. रहस्य-2
26. रेखा, लाइनू-3
27. परिमूल्य-3

ऊपर से नीचे

1. लाख, सौ हजार-2
2. बारीक, सूक्ष्म-3
3. तीन घंटे का समय-3
4. समय, वक्त-2
5. कोतवाल-3
7. बल, जोर, दम-3
9. श्रवणेंद्रिय-2
10. जो लायक न हो-4
12. कृष्ण के बड़े भाई-4
16. दर्पण, शीशा-3
17. नौका -2
19. आसान, सरल-3
21. उपस्थित-3
22. रस से भरा-3
24. बीता हुआ दिन-2
25. रजनी, निशा-2

शब्द पहेली -8783 का हल

■	आ	र	ति	■	अ	ना	मि	का
आ	ना	■	ल	जी	ज	■	■	र
ले	■	श	मि	■	र	न	■	तू
ख	ल	ब	ला	ना	■	र	ई	स
■	ग	■	ना	■	म	■	मा	■
ख	न	न	■	म	नो	न	न	य
लि	■	ल	क	■	रं	ग	■	ती
हा	■	■	हा	फि	ज	■	का	म
न	स	बा	र	■	न	ज	ला	■

■ Jagrutidaur.com, Bangalore

नगर परिषद कार्यालय के सामने अधूरा डिवाइडर बना मच्छरों का अड्डा!

बालाघाट रोड़ एवं अमगांव रोड़ पर नगर परिषद की लापरवाही से बारिश का पानी और कचरा जमा, सड़कर पैदा हो रहे मच्छर

पद्मेश न्यूज। लांजी। नगर परिषद द्वारा बालाघाट रोड एवं आमगांव रोड पर बनाए गए डिवाइडर का काम अधूरा छोड़ दिया गया है। परिणामस्वरूप यह डिवाइडर अब नालीनुमा टाका बन गया है, जिसमें बारिश का पानी जमा हो रहा है। लंबे समय से जमा पानी और कचरे के सड़ने से यहां मच्छरों का प्रजनन हो रहा है, जो पूरे इलाके के लिए गंभीर स्वास्थ्य खतरा बन गया है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह समस्या नगर परिषद कार्यालय के ठीक सामने मौजूद है। जहां से शहर की सफाई और स्वास्थ्य व्यवस्था की निगरानी होनी चाहिए, वहीं खुद नगर परिषद की लापरवाही साफ दिखाई दे रही है।

प्रशासन की दोहरी नीति

स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन समय-समय पर घर-घर जाकर जागरूकता अभियान चलाता है। लोगों को सख्ती से कहा जाता है कि घर के आसपास पानी जमा न होने दें, टायर, बर्तन, कूलर आदि में पानी न रखें, वरना डेंगू-मलेरिया जैसे रोग फैल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है — जब नगर परिषद के अपने कार्यालय के सामने ही पानी और कचरे का ऐसा भयानक अड्डा बना हुआ है, तो आम नागरिकों से जागरूकता की अपील किस मुँह से की जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस अधूरे डिवाइडर में लगातार पानी भरा रहता है। कचरा भी जमा होता जा रहा है। सड़क के किनारे से गुजरने वाले लोग बदबू और मच्छरों से परेशान हैं। कई लोगों ने चिंता जताई कि मानसून के इस मौसम में यह जगह डेंगू और अन्य वेक्टर जनित बीमारियों का केंद्र बन सकती है। नागरिकों की मांग है कि नगर परिषद तुरंत इस अधूरे डिवाइडर का निर्माण पूरा करे या कम से कम जमा पानी निकालने और कचरा हटाने की व्यवस्था करे। अन्यथा यह लापरवाही पूरे शहर की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रही है। क्या नगर परिषद अपने कार्यालय के सामने की इस समस्या को देख पाएगी या फिर जागरूकता अभियान सिर्फ कागजों और फोटो सेशन्स तक ही सीमित रहेंगे?

कारंजा सेक्टर में ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) प्रशिक्षण शिविर संपन्न

पद्मेश न्यूज। लांजी। क्षेत्रीय ग्रामीण एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केंद्र, सिवनी के आदेशानुसार 9 जुलाई से 15 जुलाई तक बोलेगांव, कारंजा, पालडोंगरी, घोटी एवं मनेरी सेक्टरों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायतों के फ्रंटलाइन कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं वार्ड सदस्य सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे हैं। यह प्रशिक्षण 16वां वित्त आयोग अंतर्गत वर्ष 2026-27 की जी.पी.डी.पी. योजनाओं को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर सही व पूर्ण रूप से अपलोड करने हेतु दिया जा रहा है। 10 जुलाई को कारंजा सेक्टर में आयोजित अभ्यास सत्र में कारंजा, कुल्पा, बापड़ी, घंसा, परसोडी, परसवाड़ा, सिंगोला, मिरिया, लाडसा, दिघोरी, सिरेगांव, कुम्हारीकला, कुम्हरीखुर्द, देवलगांव और बिंझलगांव ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर जी.पी.डी.पी. (ग्राम पंचायत विकास योजना) का डेटा 100न्न अपलोड कराने तथा उसी दिवस सभी उपस्थित लोगों को प्रमाण पत्र प्रदान करने का निर्देश दिया गया। प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनरों द्वारा संचालित किया गया। मुख्य प्रशिक्षक राजेन्द्र कुमार ताण्डेकर (पीसीओ) के साथ महेन्द्र सिरामे (पीसीओ), परमानंद बोरकर (बीसी) तथा दिलीप सत्कार (सचिव) ने तकनीकी और व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान कर योजनाओं के पोर्टल अपलोडिंग नियम, आवश्यक दस्तावेजों की जाँच तथा फील्ड-लेवल डेटा एंट्री की बारीकियाँ समझाईं।

प्रशिक्षण का उद्देश्य

ग्राम पंचायतों द्वारा वर्ष 2026-27 की जी.पी.डी.पी. योजनाओं को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर समयबद्ध व पूर्ण रूप से अपलोड कराना, क्षेत्रीय फ्रंटलाइन कर्मचारियों को पोर्टल के व्यवहारिक उपयोग का प्रशिक्षण देना, प्रत्येक ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव व रोजगार सहायक को

पोर्टल ऑपरेशन में सक्षम बनाना, प्रशिक्षण समाप्ति पर सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर उनकी उपस्थिति और योग्यता सुनिश्चित करना। प्रशिक्षण सत्र में उपस्थित सरपंचों व ग्राम कर्मचारियों ने पोर्टल पर वास्तविक समय में योजनाओं के अपलोड की प्रक्रिया का अभ्यास किया तथा तकनीकी समस्याओं पर प्रशिक्षकों से समाधान प्राप्त किया। आयोजन के समापन पर प्रशिक्षक गणों ने सभी पंचायतों से आग्रह किया कि वे निर्दिष्ट तिथि तक जी.पी.डी.पी. प्लान 100 प्रतिशत अपलोड सुनिश्चित करें ताकि 16वाँ वित्त आयोग अंतर्गत आवंटन प्रक्रियाओं में विलंब न हो।

रियल एस्टेट को सरकार का बड़ा झटका

बहुमंजिलाओं और व्यावसायिक भवनों पर भी आश्रय निधि लागू

भोपाल। राज्य सरकार द्वारा रियल एस्टेट क्षेत्र को बड़ा झटका दे दिया गया है। सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश के आधार पर अब बहुमंजिला इमारत और व्यावसायिक भवन में भी आश्रय निधि के प्रावधान लागू कर दिए गए हैं। इन प्रावधानों को लागू किए जाने से इन भवनों में भी गरीब और एलआईजी वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू हो गई है। निगम द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 एवं मध्यप्रदेश नगर पालिक (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के अंतर्गत नगर पालिक निगम इंदौर क्षेत्र अंतर्गत विकसित कालोनियों, योजनाओं के भूखंडों पर अपार्टमेंट्स, बहु-इकाई, ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं पर कॉलोनी विकास अनुमति के साथ ही आश्रय निधि अधिरोपित की जा रही है। इस आदेश में कहा गया है कि नगर निगम के विभिन्न भूस्वामियों, कॉलोनाइजरों द्वारा विकसित कॉलोनी के भूखंडों पर आवासीय या गैर-आवासीय या दोनों के प्रयोजन से अपार्टमेंट्स, बहु-इकाई, ग्रुप हाउसिंग निर्मित करके विक्रय करने या अन्यथा अंतरित करने के आशय से भवन निर्माण किया जा रहा है। अब तक तो सरकार द्वारा आश्रय निधि का प्रावधान कॉलोनी में ही लागू किया गया था, अब इस आदेश के माध्यम से यह प्रावधान बहुमंजिला इमारत, ग्रुप हाउसिंग और व्यावसायिक इमारत पर भी लागू हो गया है। वर्तमान में प्रचलित नियमों के अनुसार कॉलोनाइजर को कॉलोनी विकसित करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करना होती है और उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग हेतु आवास अथवा उसके स्थान पर आश्रय शुल्क देय होता है, लेकिन अब किसी भी प्लॉट या जमीन के टुकड़े पर यदि बहुमंजिला इमारत या ग्रुप हाउसिंग का निर्माण किया जाता है तो उसमें निर्माण करने वाले बिल्डर को निर्मित क्षेत्र का 9 अत्यंत गरीब वर्ग के लिए और 6 गरीब वर्ग के लिए आरक्षित करना होगा। यदि बिल्डर यह आरक्षण नहीं करना चाहता है तो उसे गाइड लाइन की कीमत की 6 राशि जमा करवाना होगी। मध्यप्रदेश नगर पालिक (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के अनुसार कॉलोनी को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि 'कॉलोनी से आशय है कि किसी भूमि का भाग, जिसे आवासीय या गैर-आवासीय या दोनों के प्रयोजन से भूखंडों में विभाजित करके या उस पर अपार्टमेंट निर्मित करके विक्रय करने या अन्यथा अंतरित करने के आशय से विकसित किया गया है या वह विकास के अधीन है।' इस परिभाषा से स्पष्ट है कि विकसित कॉलोनी के भूखंड पर कॉलोनाइजर द्वारा विक्रय या अन्यथा अंतरित करने के आशय से अपार्टमेंट्स, बहु-इकाई, ग्रुप हाउसिंग का निर्माण किया जाता है तो वह कॉलोनी की श्रेणी अंतर्गत माना गया है।

अतिथि विद्वानों के हित में उठेंगे आवश्यक कदम, सरकार ने बनाई उच्च स्तरीय समिति-मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में कार्यरत अतिथि विद्वानों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार आवश्यक सभी संभव कदम उठाएगी। उनकी मांगों पर विचार के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है, जिसकी अनुशंसाओं के आधार पर निर्णय लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शुक्रवार को रवीन्द्र भवन में आयोजित प्रदेश स्तरीय अतिथि विद्वान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिथि विद्वान युवा पीढ़ी के भविष्य निर्माता हैं और सरकार उनके सम्मान व कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में हर जिले में पीएमश्री एक्सीलेंस कॉलेज शुरू किए गए हैं तथा खरगोन, गुना और सागर में नए शासकीय विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि मध्यप्रदेश की उच्च शिक्षा में सकल पंजीयन दर (जीईआर) अब राष्टीय औसत से बेहतर हो गई है। डॉ. यादव ने कहा कि सरकार ने अतिथि विद्वानों के लिए आकस्मिक एवं ऐच्छिक अवकाश, महिला विद्वानों के लिए प्रसूति अवकाश, घर के निकट पदस्थापना, सहायक प्राध्यापक भर्ती में 25 प्रतिशत आरक्षण तथा आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट जैसी सुविधाएं प्रदान की हैं।

भोपाल सेंट्रल जेल में बनेगा नशामुक्ति केंद्र

मनोचिकित्सक, काउंसलर और विशेषज्ञों की टीम करेगी इलाज; प्रदेश की अन्य जेलों के बंदियों को भी मिलेगा लाभ

भोपाल। मध्यप्रदेश की जेलों में बंद नशे के आदी कैदियों के उपचार और पुनर्वास के लिए राज्य सरकार एक महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। पहली बार भोपाल सेंट्रल जेल में समर्पित नशामुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र (डी-एडिक्शन सेंटर) स्थापित किया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सहयोग से बनने वाला यह केंद्र केवल नशा छुड़ाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कैदियों को मानसिक, सामाजिक और व्यवहारिक रूप से सामान्य जीवन के लिए तैयार करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल जेल प्रशासन की सोच में आए बड़े बदलाव का संकेत है, जहां अब केवल सजा नहीं बल्कि सुधार और पुनर्वास को भी प्राथमिकता दी जा रही है। जेल मुख्यालय के अधिकारियों के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में अभी तक नशे के आदी कैदियों के लिए समय-समय पर काउंसलिंग और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं, लेकिन इनका अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाया। इसी वजह से अब एक पूर्णकालिक और विशेषज्ञों से संचालित नशामुक्ति केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

नशे की लत बनी जेल प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती

जेल अधिकारियों का कहना है कि बड़ी संख्या में ऐसे बंदी जेल पहुंचते हैं जो शराब, गांजा, अफीम, स्मैक, ब्राउन शुगर या अन्य नशीले पदार्थों के नियमित सेवन के आदी होते हैं। जेल में प्रवेश के बाद अचानक नशा बंद हो जाने से उन्हें गंभीर मानसिक और शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विशेषज्ञ इसे विथड्रॉल सिंड्रोम कहते हैं। इस दौरान कैदियों में बेचैनी, घबराहट, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, अवसाद, शरीर में दर्द, उल्टी, पसीना आना, भूख खत्म होना और कई बार हिंसक व्यवहार जैसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। कुछ बंदी तो खाना-पीना तक छोड़ देते हैं, जिससे उनकी स्वास्थ्य स्थिति गंभीर हो जाती है।

विशेषज्ञों की टीम करेगी इलाज

प्रस्तावित नशामुक्ति केंद्र में कैदियों के उपचार के लिए मनोचिकित्सक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। यह टीम प्रत्येक नशाग्रस्त बंदी की मानसिक और शारीरिक स्थिति का मूल्यांकन करेगी तथा उसके अनुसार उपचार योजना तैयार करेगी। इसमें आवश्यकता अनुसार दवाइयों के साथ व्यक्तिगत काउंसलिंग, समूह परामर्श, व्यवहार परिवर्तन चिकित्सा, मोटिवेशनल सेशन और पुनर्वास कार्यक्रम शामिल किए जाएंगे। विशेषज्ञ कैदियों को नशे की लत से बाहर निकलने के साथ-साथ तनाव प्रबंधन, आत्मनियंत्रण और समाज में पुन÷ सामान्य जीवन जीने के लिए भी तैयार करेंगे।

प्रदेश की अन्य जेलों के कैदियों को भी मिलेगा लाभ

भोपाल सेंट्रल जेल में बनने वाला यह केंद्र केवल राजधानी तक सीमित नहीं रहेगा। जेल मुख्यालय की योजना है कि प्रदेश की अन्य जेलों में बंद गंभीर रूप से नशे के आदी कैदियों को भी उपचार के लिए भोपाल लाया जाएगा। इससे पूरे प्रदेश के जेल तंत्र को एक विशेषीकृत उपचार सुविधा उपलब्ध होगी। भविष्य में आवश्यकता के अनुसार अन्य केंद्रीय जेलों में भी ऐसे केंद्र स्थापित किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा।

जेल से बाहर निकलने के बाद भी रहेगा फॉलोअप

जेल प्रशासन का उद्देश्य केवल जेल अवधि के दौरान नशा छुड़ाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि रिहाई के बाद बंदी दोबारा नशे की गिरफ्त में न जाएं। इसके लिए काउंसलिंग के दौरान कैदियों में आत्मविश्वास विकसित किया जाएगा। उन्हें रोजगार, परिवार और सामाजिक जीवन में सकारात्मक वापसी के लिए मानसिक रूप से तैयार किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि नशे की लत पर जेल में ही प्रभावी नियंत्रण हो जाए तो अपराध की पुनरावृत्ति (री-ऑफेंडिंग) में भी कमी लाई जा सकती है।

सामाजिक न्याय विभाग करेगा सहयोग

जेल मुख्यालय के अनुसार इस परियोजना को सामाजिक न्याय विभाग के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। केंद्र की स्थापना के लिए आवश्यक संसाधन, विशेषज्ञों की उपलब्धता और संचालन व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है। एडीजी जेल जी. अखेतो सेमा ने बताया कि नशामुक्ति केंद्र स्थापित करने के लिए सामाजिक न्याय विभाग की ओर से निविदा प्रक्रिया जारी है। प्रक्रिया पूरी होते ही केंद्र की स्थापना का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

कु.मनीषा राजेश शुक्ला का माध्यमिक शिक्षक वर्ग-2 (विषय- अंग्रेजी) के पद पर हुआ चयन

पद्मेश न्यूज। लांजी। क्षेत्र के लिए हर्ष का विषय है कि कु. मनीषा पिता राजेश शुक्ला का चयन माध्यमिक शिक्षक वर्ग-2 (विषय-अंग्रेजी) के पद पर हुआ है। चयन उपरांत उनकी पदस्थापना

शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय, लांजी में हुई, जहाँ उन्होंने विधिवत अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इस अवसर पर कु. मनीषा शुक्ला ने अपनी सफलता का श्रेय अपने सभी गुरुजनों, पिता राजेश शुक्ला, माता रीता शुक्ला, भाई सिद्धांत शुकुला एवं सभी शुभचिंतकों, परिवार जनों और इष्टमित्रों को देते हुए उनके मार्गदर्शन, आशीर्वाद एवं सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया। बतादे कि मनीषा शुक्ला के पिता श्री राजेश कुमार शुक्ला, जो स्वयं एक निजी विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, ने पुत्री की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह सफलता उनके निरंतर परिश्रम, लगन और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। उन्होंने मनीषा के उज्वल भविष्य की कामना करते हुए विश्वास जताया कि वे शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर विद्यार्थियों के जीवन को नई दिशा देंगी। कु. मनीषा शुक्ला की इस उपलब्धि पर क्षेत्रवासियों, परिजनों, मित्रों एवं शुभचिंतकों ने उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ प्रेषित की हैं।

गेहूं भंडारण में इस्तेमाल बोरे और पीपी बैग की गुणवत्ता की होगी जांच

नागरिक आपूर्ति निगम ने बनाई जांच टीम

भोपाल। सरकारी गोदामों में गेहूं की कमी का मामला सामने आने के बाद अब नागरिक आपूर्ति निगम ने खाद्यान्न भंडारण में इस्तेमाल किए गए जूट के बोरे और पीपी (पॉलीप्रोपाइलीन) बैग की गुणवत्ता की जांच कराने का फैसला किया है। निगम के अध्यक्ष केपी यादव के निर्देश पर प्रबंध संचालक भास्कर लाक्षाकर ने अधिकारियों को जांच के आदेश दिए हैं। निगम के अनुसार करीब 86 हजार क्विंटल गेहूं की कमी सामने आने के बाद यह शिकायतें मिली थीं कि खाद्यान्न की पैकिंग में इस्तेमाल किए गए बोरे और पीपी बैग की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं थी। इन्हीं शिकायतों की जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है।

हालांकि सरकार के अनुसार, तुलाई, परिवहन और भंडारण के दौरान गेहूं में कुछ कमी आना सामान्य प्रक्रिया है। पिछले वर्षों में यह कमी औसतन 176 ग्राम प्रति क्विंटल थी, जबकि इस वर्ष यह घटकर 70 ग्राम प्रति क्विंटल रह गई है। खास बात यह है कि इस बार गेहूं की खरीदी पिछले वर्ष की तुलना में करीब 30 प्रतिशत अधिक हुई, फिर भी कमी का स्तर कम रहा। सागर जिले में भी खरीदे गए गेहूं की जांच की जा रही है। वहां पिछले वर्षों में औसतन 510 ग्राम प्रति क्विंटल कमी रहती थी, जो इस वर्ष घटकर 318 ग्राम प्रति क्विंटल रह गई है। सरकार का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद वास्तविक नुकसान की भरपाई संबंधित जिम्मेदार पक्षों से कराई जाएगी।

तीन अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी

जांच की निगरानी महाप्रबंधक (उपार्जन) के नेतृत्व में की जाएगी। अलग-अलग जिलों के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। एजीएम एस.सी. हेडाऊ सीहोर, उज्जैन और रतलाम जिलों की जांच करेंगे। एजीएम ज्योति चोकसे विदिशा, नर्मदापुरम और देवास की जांच की जिम्मेदारी संभालेंगी। प्रबंधक हेमराज मोरे भोपाल, रायसेन और नरसिंहपुर जिलों में जांच करेंगे।

जांच में इन बिंदुओं पर रहेगा फोकस

जांच टीम यह पता लगाएगी कि खाद्यान्न की पैकिंग में इस्तेमाल किए गए बोरे और पीपी बैग निर्धारित गुणवत्ता के थे या नहीं। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि कहीं खराब गुणवत्ता के कारण गेहूं के भंडारण और परिवहन के दौरान नुकसान तो नहीं हुआ। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टरों की अध्यक्षता वाली कमेटी करती है उपार्जन

प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी का समस्त कार्य जिला कलेक्टर की अध्यक्षता के गठित जिला स्तरीय उपार्जन समिति के माध्यम से किया जाता है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है कि गेहूं की खरीद में पाई गई कमी की प्रतिपूर्ति जिला स्तरीय उपार्जन समिति द्वारा ही संबंधित समितियों/परिवहनकर्ताओं से वसूली कर की जाती है। जिला स्तरीय समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि जिले में उपार्जित गेहूं में शासन को किसी प्रकार की आर्थिक क्षति न होने पाये।

पुलिस सैलरी पैकेज योजना से दिवंगत पुलिसकर्मियों के परिवारों को मिले 1-1 करोड़

भोपाल। मप्र पुलिस द्वारा पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कल्याण तथा उनके परिवारों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित पुलिस सैलरी पैकेज योजना के अंतर्गत जिला दमोह में पदस्थ दिवंगत दो पुलिसकर्मियों के आश्रित परिवारों को 1-1 करोड़ रूपए की दुर्घटना बीमा दावा राशि प्रदान की गई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय दमोह में आयोजित विशेष कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगी ने दिवंगत प्रधान आरक्षक श्रीमती शमीम खान एवं दिवंगत आरक्षक भूपेंद्र ठाकुर के आश्रित परिजनों को 1-1 करोड़ रूपए की सहायता राशि के चेक प्रदान किए। दिवंगत प्रधान आरक्षक श्रीमती शमीम खान एवं आरक्षक भूपेंद्र ठाकुर का जून 2025 में दुर्घटना के उपरांत उपचार के दौरान दुखद निधन हो जाने पर उनके वेतन खाते भारतीय स्टेट बैंक में पुलिस सैलरी पैकेज योजना से संबद्ध होने के कारण उनके नामांकित उत्तराधिकारी को दुर्घटनावश मृत्यु बीमा के रूप में 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा सभी पुलिस कर्मियों को पुलिस वेतन पैकेज खाता के जरिए अनेक वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

भोपाल के सरकारी स्कूलों की होगी हाईटेक निगरानी

सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन मानिटरिंग सिस्टम के तहत कंट्रोल कमांड रूम होगा स्थापित

भोपाल। राजधानी के सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए जिला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब स्कूलों की हर गतिविधि पर जिला स्तर से सीधे नजर रखी जाएगी। इसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन मानिटरिंग सिस्टम के तहत कंट्रोल कमांड रूम स्थापित किया जा रहा है। इस हाईटेक सिस्टम के जरिए छात्रों की उपस्थिति, सुरक्षा और ड्रापआउट रेट की नियमित ट्रैकिंग होगी। हाल ही में कमला नेहरू सांदीपनि कन्या शासकीय विद्यालय, टीटी नगर में आयोजित समग्र शिक्षा अभियान की समीक्षा बैठक में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। इस दौरान उन्होंने छात्राओं से संवाद किया और उनके साथ बैठकर लंच भी किया। इस बैठक में तकनीक के इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया गया। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिले के सभी स्कूली विद्यार्थियों की अपार आईडी शत-प्रतिशत तैयार की जाए। इस डिजिटल पहचान के जरिए छात्रों के शैक्षणिक सफर की ट्रैकिंग आसान होगी। इसके साथ ही शिक्षा के अधिकार के तहत पात्र बच्चों का समय पर एडमिशन सुनिश्चित करने और सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल छोडने वाले बच्चों के आंकड़ों को लेकर कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि पोर्टल पर केवल सही और प्रामाणिक डेटा ही दर्ज किया जाए। यदि किसी भी स्तर पर आंकड़ों में हेराफेरी या लापरवाही पाई गई, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों की बुनियादी समस्याओं और शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए एक नई व्यवस्था बनाई गई है। कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी को विद्यालयों के लिए प्रथम संपर्क अधिकारी नियुक्त किया है। अब स्कूलों को अपनी किसी भी समस्या के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि ये अधिकारी सीधे तौर पर समस्याओं का समाधान करेंगे।

लांजी में ''पद्मेश''
इंटरनेट (ब्राडबेंड)
कनेक्शन के लिये संपर्क करें
Mo. 8319969927

13 से 15 जुलाई तक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे पटवारी

- 32 हजार पटवारियों ने सरकार के खिलाफ किया आंदोलन का ऐलान

- 1998 के बाद न वेतन पुनरीक्षण, न कैडर रिव्यू और न ही प्रमोशन मिलने का आरोप

भोपाल। मध्यप्रदेश के करीब 32 हजार पटवारियों ने विधानसभा के मानसून सत्र से ठीक पहले सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है। प्रदेशभर के पटवारी 13 जुलाई से 15 जुलाई तक तीन दिवसीय सामूहिक सांकेतिक अवकाश पर रहेंगे, जिससे राजस्व विभाग के कामकाज पर असर पड़ सकता है। इसके बाद भी मांगें पूरी नहीं होने पर चरणबद्ध और व्यापक आंदोलन की चेतावनी दी गई है।

मध्यप्रदेश पटवारी संघ ने आरोप लगाया है कि वर्षों से लंबित मांगों पर शासन कोई ठोस निर्णय नहीं ले रहा है। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि 1998 के बाद से अब तक न तो वेतन पुनरीक्षण किया गया, न कैडर रिव्यू हुआ और न ही नियमित पदोन्नति दी गई। इससे पूरे पटवारी संवर्ग में भारी नाराजगी है। संघ ने प्रदेशभर के कलेक्टरों के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपना शुरू कर दिया है। साथ ही 12 जुलाई को भोपाल में प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाकर आंदोलन की आगे की रणनीति तय की जाएगी।

चार दिन का अल्टीमेटम

पटवारी संघ ने सरकार को चार दिन का समय देते हुए कहा है कि यदि लंबित मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो 13 से 15 जुलाई तक सामूहिक अवकाश रहेगा। इसके बाद आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

वर्षों से सिर्फ आश्वासन मिलने का आरोप

संघ के प्रांतीय अध्यक्ष उपेंद्र बाघेल का कहना है कि संगठन कई वर्षों से अपनी मांगें शासन के सामने रखता आ रहा है, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला। उनका आरोप है कि अन्य विभागों के कर्मचारियों को लगातार पदोन्नति और सेवा लाभ मिल रहे हैं, जबकि पटवारियों की समस्याएं लगातार नजरअंदाज की जा रही हैं।

पटवारियों की प्रमुख मांगें

पटवारी संघ ने सरकार के सामने पांच प्रमुख मांगें रखी हैं। पहला कैडर रिव्यू लागू कर नियमित पदोन्नति और समयमान वेतनमान दिया जाए। जब तक कैडर रिव्यू नहीं होता, तब तक पदोन्नति से वंचित कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ मिले। दूसरा नायब तहसीलदार की विभागीय परीक्षा शीघ्र कराई जाए। संघ का कहना है कि पिछले 23 वर्षों में केवल एक बार, वर्ष 2019 में परीक्षा आयोजित हुई थी। तीसरा पटवारियों को जज प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में शामिल किया जाए। संघ का कहना है कि राजस्व मामलों में अंतिम निर्णय तहसीलदार या नायब तहसीलदार लेते हैं, लेकिन कई मामलों में सीधे पटवारियों पर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। चौथा लंबित मानदेय और भुगतान तत्काल किया जाए। संघ के अनुसार स्वामित्व योजना, कृषि गणना, लघु सिंचाई गणना, फार्मर आईडी शिविर सहित कई सरकारी योजनाओं में निजी संसाधनों से काम कराने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया है। पांचवां संघ पदाधिकारियों के स्थानांतरण निरस्त किए जाएं। संघ का आरोप है कि कर्मचारी हितों की आवाज उठाने वाले पदाधिकारियों का स्थानांतरण स्थानांतरण नीति के विपरीत किया गया है।

शासन पर भेदभाव का आरोप

मध्यप्रदेश पटवारी संघ के प्रदेश संवाद समिति अध्यक्ष राजीव जैन ने कहा कि प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर पटवारियों ने एकजुट होकर ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने समय रहते न्यायोचित मांगों पर निर्णय नहीं लिया तो प्रदेशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। इससे होने वाले किसी भी प्रशासनिक व्यवधान की जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

पंचायत विभाग का निलंबित इंजीनियर ने बताया कौन-कितना खाता है कमीशन

भोपाल। प्रदेश के सतना जिले में भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद निलंबित किए गए मझगवां जनपद पंचायत के संविदा उपयंत्री सतीश समेले ने वीडियो जारी कर विभाग में चल रही कमीशनखोरी को उजागर कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि जनपद पंचायत से लेकर भोपाल तक कमीशन का पूरा सिस्टम चलता है। समेले का कहना है कि उनसे भी अधिकारियों के लिए वसूली कराई गई और इसके ऑडियो, वीडियो समेत अन्य सबूत उनके पास हैं, जिन्हें वह हाईकोर्ट में पेश करेंगे।

पंचायत विभाग में कमीशन का चार्ट

सरपंच-10 फीसदी
सचिव - 5 फीसदी
ग्राम रोजगार सहायक- 3 फीसदी
सब इंजीनियर- 5 फीसदी
सहायक यंत्री- 2 फीसदी
जनपद सीईओ - 2 से 3 फीसदी

समेले ने आरोप लगाया कि सब इंजीनियर अब वसूली एजेंट बनकर रह गए हैं। उन्होंने कहा कि वह खुद भी इस व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं और उनसे भी वसूली कराई गई। कब-कब चंदा हुआ और किस तरह पैसा नीचे से ऊपर तक पहुंचा, इसके ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड उनके पास हैं। उनका दावा है कि ये सभी सबूत वह हाईकोर्ट में पेश करेंगे।

हनुमान जी सामने खाए बेटे की कसम

समेले ने कहा कौन माई का लाल है जो पैसा नहीं लेता। अगर कोई नहीं लेता तो हनुमान जी के सामने अपने बेटे की कसम खाए, तब मैं मान जाऊंगा। उनका दावा है कि निर्माण कार्यों में नीचे से ऊपर तक अलग-अलग स्तर पर कमीशन तय रहता है। उन्होंने अपने ऊपर लगे कमीशन लेने के आरोपों को भी निराधार बताया। उनका कहना है कि ईएमएफ, ग्रांट और अन्य मद के कार्यों में 10 से 15 प्रतिशत तक कमीशन लिया जाता है। उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) से लेकर भुगतान तक कई स्तरों पर पैसा देना पड़ता है। सरपंच, सचिव, जीआरएस, सब इंजीनियर, सहायक यंत्री और जनपद स्तर तक कमीशन का प्रतिशत पहले से तय रहता है।

महादेव सट्टा ऐप मामले में सीबीआई ने दाखिल की छह नई चार्जशीटें

-भोपाल के दो कारोबारी समेत कई को बनाया आरोपी, फर्जी खातों से विदेश भेजी गई रकम

-नेटवर्क को संरक्षण देने के लिए प्रोटेक्शन मनी देने का आरोप

भोपाल,। देश के चर्चित महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप घोटाले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने जांच को आगे बढ़ाते हुए विशेष अदालत में छह नए आरोप पत्र दाखिल किए हैं। इनमें एक चार्जशीट महादेव ऐप से जुड़े कथित भ्रष्टाचार प्रकरण से संबंधित है, जबकि पांच अन्य आरोप पत्र अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क के संचालन से जुड़े मामलों में दायर किए गए हैं। इन आरोप पत्रों में भोपाल के दो कारोबारी विशाल आहूजा और धीरज आहूजा सहित कई लोगों को आरोपी बनाया गया है।

मीडिया रिपोर्ट में सीबीआई के हवाले से बताया जा रहा, कि आरोपियों में असीम दास, रोहित गुलाटी, विकास छापरिया, अनिल धम्मानी, विशाल आहूजा और धीरज आहूजा शामिल हैं। जांच में सामने आया है कि भोपाल के लालघाटी निवासी आहूजा बंधु अपनी रैपिड ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से महादेव ऐप के प्रमोटरों, उनके परिवार और सहयोगियों की देश-विदेश की हवाई यात्रा की बुकिंग का काम देखते थे। इसके लिए विभिन्न टिकटिंग कंपनियों में पहले से वॉलेट बैलेंस जमा कराया जाता था, जिससे टिकटों की बुकिंग की जाती थी। सीबीआई का दावा है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी से अर्जित धन फर्जी बैंक खातों के जरिए विदेश भेजा जाता था। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया है कि नेटवर्क के संचालन और उसे संरक्षण दिलाने के लिए कुछ अधिकारियों को कथित तौर पर प्रोटेक्शन मनी दी जाती थी। मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ भी अतिरिक्त साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

जांच में यह भी सामने आया कि महादेव नेटवर्क ने सोशल मीडिया और डिजिटल विज्ञापनों के माध्यम से देशभर में अपने अवैध सट्टा कारोबार का तेजी से विस्तार किया। फिलहाल सीबीआई पश्चिम एशिया में छिपे आरोपियों को भारत लाने के प्रयास में जुटी है। चार आरोपियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जा चुका है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अब तक देशभर में 175 से अधिक स्थानों पर छापेमारी कर 4,336 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां, नकदी और आभूषण कुर्क कर चुका है। आयकर विभाग, ईडी, आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) और सीबीआई की कार्रवाई के बावजूद अलग-अलग नामों से ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क संचालित होने की बात जांच में सामने आई है।

चार्जशीट में कोई नेता या अधिकारी आरोपी नहीं

हालांकि, इस मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि ईडी और छत्तीसगढ़ ईओडब्ल्यू की जांच में कई नेताओं और पुलिस अधिकारियों के नाम सामने आने तथा उनके ठिकानों पर छापेमारी और पूछताछ होने के बावजूद सीबीआई की ताजा चार्जशीट में किसी भी राजनेता या अधिकारी को आरोपी नहीं बनाया गया है। इसे लेकर जांच के दायरे और निष्कर्षों पर सवाल भी उठ रहे हैं। वहीं, सीबीआई ने जांच जारी रहने और नए साक्ष्यों के आधार पर आगे भी कार्रवाई की संभावना जताई है।

भाजपा विधायक प्रीतम लोधी का बेटा विशेष अदालत से फरार घोषित

भोपाल। ग्वालियर की विशेष एससी-एसटी अदालत ने भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी के बेटे दिनेश लोधी को फरार घोषित करते हुए उसके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। अदालत ने निर्देश दिए हैं कि प्रकरण के रिकॉर्ड के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से अभियुक्त फरार है अंकित किया जाए और प्रकरण को नियमानुसार सुरक्षित रखा जाए। दिनेश लोधी (40), निवासी ग्राम जलालपुर, के विरुद्ध पुरानी छावनी थाने में एससी-एसटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज है। न्यायालय के रिकॉर्ड के मुताबिक उसके खिलाफ 28 दिसंबर 2023 को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, लेकिन उसके बाद भी वह पुलिस की पकड़ में नहीं आया। सुनवाई के दौरान पुरानी छावनी थाने के प्रधान आरक्षक संजय द्विवेदी ने अदालत में वारंट की अदम तामील रिपोर्ट और तस्दीक पंचनामा पेश किया। रिकॉर्ड का परीक्षण करने के बाद विशेष न्यायाधीश नवीन कुमार शर्मा ने अभियुक्त को फरार घोषित करते हुए उसके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश पारित किए।

20 हजार पुलिसकर्मी होंगे प्रमोट

- पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर होंगे प्रमोशन

भोपाल। मध्य प्रदेश के पुलिसकर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही बड़े स्तर पर प्रमोशन होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि 48 घंटे के अंदर करीब 20 हजार पुलिसकर्मियों को पदोन्नत कर दिया जाएगा। इसके लिए जल्द ही आदेश जारी किए जाएंगे। इस ऐतिहासिक फैसले से लंबे वक्त से प्रमोशन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों और अधिकारियों को लाभ मिलेगा।

दरअसल, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पदोन्नति को लेकर मंत्रियों और अधिकारियों से कहा था कि जो पात्र कर्मचारी और अधिकारी हैं, उन्हें समय पर पदोन्नति मिले। साथ ही उन्होंने सख्त रुख अपनाया था। इसके बाद डीजीपी कैलाश मकवाना ने विभाग में प्रमोशन के लिए निर्देश दिए हैं। इस प्रक्रिया के लिए गृह विभाग ने पत्र भी लिखा है। इंस्पेक्टर से लेकर डीएसपी तक के प्रमोशन के लिए पत्र लिखा गया है। वहीं, कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की पदोन्नति के लिए कमेटी बनाई गई है। जल्द ही प्रमोशन ऑर्डर जारी किए जाएंगे।

स्वस्थ पुलिस – सुरक्षित प्रदेश

मुख्यमंत्री ने अपनाया सख्त रुख

सीएम ने कैबिनेट मीटिंग में प्रमोशन के बारे में चर्चा की। लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के तहत पिछले 9 दिनों में किए गए प्रमोशन का ब्यौरा मांगा है। अलग-अलग विभागों को प्रमोट किए गए कर्मचारी और अधिकारियों की जानकारी अपलोड करने के लिए कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विभिन्न विभागों में अधिकारियों के द्वारा प्रमोशन नहीं दिए जाने की शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंची थी। इसके बाद उन्होंने इसे गंभीरता से लेने के लिए कहा था। सीएम ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो भी पात्र अधिकारी और कर्मचारी हैं उन्हें प्रमोट किया जाए। वहीं, कुछ स्त्रोतों से प्रमोशन के बदले पैसे मांगने की बात भी सामने आई है। इसके सीएम ऑफिस एक्टिव हो गया है।

तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को मिले उप-पंजीयक के अधिकार

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने स्वामित्व योजना को गति देने के लिए बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को उप-पंजीयक (सब-रजिस्ट्रार) के अधिकार प्रदान कर दिए हैं। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के बाद अब ये अधिकारी विशेष शिविरों के माध्यम से आबादी भूमि पर दर्ज संपत्तियों की रजिस्ट्री भी कर सकेंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति पंजीयन की प्रक्रिया तेज होगी और लोगों को जिला पंजीयक कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश में 68.11 लाख संपत्तियों का पंजीयन किया जाना है। इनमें करीब 48.32 लाख निजी तथा 19.79 लाख सरकारी एवं अन्य संस्थाओं की संपत्तियां शामिल हैं। सरकार का अनुमान है कि यदि केवल पंजीयन विभाग के माध्यम से यह कार्य कराया जाए तो इसमें पांच वर्ष से अधिक समय लग सकता है। इसी कारण तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को उप-पंजीयक के अधिकार देकर इस अभियान को गति देने का फैसला लिया गया है। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से रजिस्ट्री प्रक्रिया सरल, तेज और पारदर्शी बनेगी। साथ ही ग्रामीण नागरिकों को समय और धन दोनों की बचत होगी तथा स्वामित्व योजना के लक्ष्यों को तय समय में पूरा करने में भी मदद मिलेगी।

भ्रष्टाचार और कर्ज के मुद्दे पर 15 जुलाई को सीएम आवास घेरेगी कांग्रेस

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार और सरकार की असफलता से आमजन का ध्यान भटकाने के लिए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मुद्दा उछाला गया है। इसका प्रदेश के लगभग पौने दो करोड़ आदिवासियों की संस्कृति, परंपरा और संवैधानिक अधिकारों पर संभावित प्रभाव पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए।

नर्मदा नदी पर बनीं सरदार सरोवर परियोजना को लेकर हुए समझौते से राज्य के हित प्रभावित होने की बात सामने आई है। इसे लेकर सरकार श्वेत पत्र जारी कर वस्तुस्थिति जनता के सामने लाए। भ्रष्टाचार सहित अन्य मामलों को लेकर 15 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। भोपाल में मीडिया से चर्चा में पटवारी ने कहा कि देशभर में बंद हुए लगभग 5,000 स्कूलों में से 2,500 स्कूल अकेले मध्य प्रदेश के हैं। यूसीसी केंद्र सरकार का विषय है। प्रदेश में इसे लागू करने की चर्चा केवल वास्तविक मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास है। प्रदेश महिलाओं पर अत्याचार, आदिवासियों पर अत्याचार, बलात्कार, ड्रग्स माफिया, शराब माफिया सहित अन्य प्रकार के अपराध व भ्रष्टाचार के मामलों में लगातार बदनाम हो रहा है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी अपना संघर्ष जारी रखेगी। 15 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर अयोध्या से महाकाल तक कथित भ्रष्टाचार के मुद्दों को जनता के सामने लाएगी। सरकार प्रदेश को कर्ज के दलदल में फंसती जा रही है। वर्तमान में 5,61,786 कर्ज हो गया है। सरदार सरोवर बांध को लेकर हुए समझौते पर पटवारी ने कहा कि परियोजना से सर्वाधिक प्रभावित मध्य प्रदेश हुआ। क्षति की भरपाई के लिए 76,69 करोड़ का दावा प्रस्तुत किया था लेकिन समझौते में 231 करोड़ रुपये देना तय किया गया। सरकार को श्वेत पत्र जारी कर वस्तुस्थिति स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर यह कैसे हुए।

ग्वालियर में बनेगी मप्र की पहली हाईटेक फ्लोरीकल्चर नर्सरी

भोपाल। प्रदेश के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और ग्वालियर में पर्यटन की नई संभावनाएं तलाशने के लिए सरकार एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत ग्वालियर जिले के ग्राम जहांगीरपुर खुरेरी में प्रदेश की पहली सर्वसुविधाजनक हाईटेक फ्लोरीकल्चर नर्सरी की स्थापना होने जा रही है। पूरा प्रोजेक्ट करीब 49 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जाएगा, जिसके पहले चरण के सिविल और तकनीकी कार्यों के लिए 13 करोड़ की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है।

इस हाईटेक नर्सरी की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि यहां आधुनिक तकनीकों से न केवल पौधों और फूलों की नई किस्में तैयार की जाएंगी, बल्कि अंचल भर के किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए हास्टल और आडिटोरियम भी बनाया जा रहा है। इसके साथ ही, इसकी भव्य लैंडस्केपिंग इसे एक खूबसूरत पर्यटन केंद्र का रूप देगी, जहां सैलानी भी घूमने आ सकेंगे।

नर्सरी परिसर रहेंगी कई सुविधाएं

परिसर में किसानों के लिए 200 की क्षमता वाला एक भव्य आडिटोरियम सह ट्रेनिंग हाल बनाया जाएगा। इसके साथ ही, दूर-दराज से आने वाले किसानों के रुकने के लिए 30 बिस्तरों की क्षमता वाला एक रेसिडेंस हास्टल भी तैयार होगा। पौधों की बीमारियों की जांच और बेहतर किस्मों के शोध के लिए एक अत्याधुनिक प्लांट पैथोलाजी लैब का निर्माण 120 वर्ग मीटर में किया जा रहा है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लाक, वर्कर शेड और स्टाफ के लिए तीन एफ-टाइप क्वाटर्स भी बनेंगे। सैलानियों को आकर्षित करने के लिए 500 की क्षमता वाला एक ओपन एयर थिएटर बनाया जाएगा, जहां सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हो सकेंगी। साथ ही फूलों और पौधों की खरीद के लिए एक सेल काउंटर और एग्जीबिशन एरिया भी होगा। नर्सरी में फूलों को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए आठ मीट्रिक टन क्षमता का एक कोल्ड चैंबर और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्मी-कंपोस्टिंग यूनिट बनाई जाएगी।

संरक्षित खेती और सिंचाई के लिए आधुनिक तकनीकें

प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के तहत 4000 वर्ग मीटर में फैन एंड पैड टाइप ग्रीन हाउस, इतनी ही क्षमता के नेचुरली वेंटिलेटेड पाली हाउस और शेड नेट हाउस विकसित किए जा रहे हैं ताकि मौसम के प्रभाव से बचाकर बेमौसम फूलों की खेती हो सके। व्यावसायिक फूलों की खेती के लिए दो हेक्टेयर का ओपन फील्ड, एक हेक्टेयर में मदर ब्लाक और नई किस्मों के प्रदर्शन के लिए दो हेक्टेयर का डेमोस्ट्रेशन प्लाट तैयार किया जाएगा। सिंचाई के लिए आटो सैंड फिल्टर, एडवांस आटो वाटर फर्टी-मिक्स तकनीक और माइक्रो व ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया जाएगा, जो पानी की एक-एक बूंद का सटीक उपयोग करेगा।

अतिथि विद्वानों के मुद्दों पर बनेगी कमेटी

सीएम बोले- फिक्स सैलरी, नियमितीकरण समेत मांगों पर होगा विचार, अटकाने-लटकाने का समय गया

भोपाल। भोपाल में भारतीय मजदूर संघ के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अतिथि विद्वानों को बड़ी राहत का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि अतिथि विद्वानों की फिक्स सैलरी, नियमितीकरण और अन्य लंबित मांगों पर विचार के लिए कमेटी बनाई जाएगी। देश के जिस भी राज्य का बेहतर मॉडल होगा, उसका अध्ययन कर मध्यप्रदेश में लागू करने की कोशिश की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटकाने-लटकाने का समय गया, अब सरकार सकारात्मक सोच के साथ फैसले ले रही है। मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से कहा कि वे उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समिति बनाकर अतिथि विद्वानों की मांगों पर काम करें। उन्होंने कहा कि सरकार हर संभव सहयोग करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पहले भी अतिथि विद्वानों के लिए कई फैसले ले चुकी है। अब उनकी बाकी समस्याओं के समाधान की दिशा में भी काम होगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा समेत जिस राज्य में बेहतर व्यवस्था है, उसका अध्ययन कर मध्यप्रदेश में लागू करने पर विचार किया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि सरकार ने अतिथि विद्वानों को 13 आकस्मिक अवकाश, तीन ऐच्छिक अवकाश, महिला अतिथि विद्वानों को प्रसूति अवकाश, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 25 प्रतिशत आरक्षण और साल में एक बार स्थानांतरण की सुविधा दी है।

उन्होंने बताया कि तकनीकी शिक्षा विभाग में वेतन 12 महीने के बजाय 11 महीने मिलने की समस्या को भी दूर किया जाएगा, ताकि दोनों विभागों के अतिथि विद्वानों के लिए एक जैसी व्यवस्था लागू हो सके।

मजदूर संघ ने उठाए सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे

भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री कुलदीप सिंह गुर्जर ने कहा कि अतिथि विद्वानों की सामाजिक सुरक्षा और अन्य लंबित मांगों का जल्द समाधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास से मध्यप्रदेश देश में अग्रणी राज्य बनेगा और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

शिक्षा से ही बनेगा मजबूत समाज

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में भारतीय शिक्षा परंपरा का उल्लेख करते हुए भगवान राम और भगवान कृष्ण के प्रसंगों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था हमेशा दुनिया के लिए प्रेरणा रही है और नई शिक्षा नीति के जरिए मध्यप्रदेश देश में मिसाल बना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो (त्रश्वक्र) राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर है और अब किताबी ज्ञान के साथ नवाचार पर भी जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों और अतिथि विद्वानों से नशा मुक्ति अभियान में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि जैसे प्रदेश में नक्सलवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हुई, उसी तरह अब नशे के खिलाफ भी व्यापक अभियान चलाया जाएगा। शैक्षणिक परिसरों में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है, ताकि युवा नशे से दूर रहें।

दो प्रतिशत महंगाई भत्ते की मांग तेज, कर्मचारी बोले

49 करोड़ की लागत से सैलानियों के लिए तैयार होगा नया टूरिस्ट स्पॉट

भोपाल। मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय सेवा (आईएएस, आईपीएस, आईएफएस) के अधिकारियों को जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) दिए जाने के बाद अब प्रदेश के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स भी इसी तिथि से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने राज्य सरकार से जल्द घोषणा करने की मांग की है। उनका कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और सरकार राहत दे नहीं रही।

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार अपने एक करोड़ से अधिक कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जनवरी 2026 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दे चुकी है। इसी आधार पर मध्य प्रदेश में कार्यरत करीब 850 अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को भी केंद्रीय दर से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत कर दिया गया है। ऐसे में प्रदेश के अन्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी समान लाभ मिलना चाहिए।

12 लाख से अधिक कर्मचारियों-पेंशनर्स को मिलेगा लाभ

कर्मचारी संघ का कहना है कि प्रदेश के करीब 7.50 लाख कार्यरत कर्मचारियों और 4.50 लाख पेंशनर्स को इसका लाभ मिलना चाहिए। वर्तमान में कर्मचारियों को 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता और पेंशनर्स को 58 प्रतिशत महंगाई राहत मिल रही है। संगठन ने इसे बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने की मांग की है।

बढ़ती महंगाई का दिया हवाला

उमाशंकर तिवारी ने कहा कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का उद्देश्य बढ़ती महंगाई से कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देना होता है। उन्होंने बताया कि मार्च से जून के बीच घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में करीब 89 रुपए की बढ़ोतरी हुई है।

इंग्लैंड ने भारतीय टीम को 9 विकेट से हराकर 3-0 से टी20 सीरीज जीती

ब्रिस्टल। भारतीय क्रिकेट टीम को मेजबान इंग्लैंड के हाथों चौथे टी20 क्रिकेट मैच में भी करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस मैच में जीत के साथ ही मेजबान टीम ने पांच मैचों की ये सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड ने इस मैच में 9 विकेट से जीत हासिल की। इस प्रकार मेजबान टीम ने भारतीय टीम के खिलाफ पहली बार कोई टी20 सीरीज जीती है। इससे पहले, भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गईं छह सीरीज में से पांच टीम भारतीय टीम ने जीती थीं, जबकि एक सीरीज 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुई थी। इसी के साथ ही भारतीय टीम को आयरलैंड के बाद अब इंग्लैंड के खिलाफ भी लगातार हार झेलनी पड़ी है, जो टीम के लिए चिंता का कारण है। भारतीय टीम को इससे पहले अंतिम बार साल 2019 में न्यूजीलैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया के हाथों लगातार दो द्विपक्षीय सीरीज में हार मिली थी।

इस चौथे टी20 मुकाबले में भी भारतीय बल्लेबाजा पुरानी गलतियों को दोहराते दिखे। कप्तान श्रेयस अय्यर के अलावा कोई भी बल्लेबाज विकेट पर टिककर नहीं खेल पाया। इसी कारण बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर केवल 158 रन ही बना पायी। भारतीय टीम की ओर से कप्तान श्रेयस अय्यर ने 49 गेंदों पर सबसे अधिक 80 रन बनाये पर अन्य बल्लेबाजों के विफल रहने से टीम एक बड़ा स्कोर नहीं बना पायी।

15 साल के उभरते हुए बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी केवल 15 रन ही बना पाये। अभिषेक शर्मा भी विफल रहे और 16 रन बनाकर पेवेलियन लौट गये। ईशान किशन भी केवल 4 रन ही बना पाये। शिवम दुबे ने 23 गेंदों में 22 रन बनाए और वह विल जैक्स का शिकार बने। तिलक वर्मा ने 11, वॉशिंगटन सुंदर ने 5 और अक्षर पटेल 1 रन बनाकर आउट हुए। इस बाद जीत के लिए मिले 159 रनों के लक्ष्य को मेजबान इंग्लैंड ने केवल 13.5 ओवरों में ही एक विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। इंग्लैंड टीम की ओर से सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट ने 42 गेंदों में 59 रनों की नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली, वहीं कप्तान हैरी ब्रूक ने केवल 35 गेंदों में 8 चौकों और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 79 रन बनाए और टीम को आसानी से जीत दिला दी। आउट होने वाले एकमात्र बल्लेबाज जोस बटलर रहे।वह केवल हाल 8 रन बना पाये।

इंग्लैंड दौरे में लगातार मिली हार के बाद गंभीर की कुर्सी खतरे में पड़ी

मुम्बई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) इंग्लैंड दौर पर टीम के खराब प्रदर्शन से बेहद नाराज है और ऐसे में टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर की कुर्सी खतरे में पड़ती नजर आ रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार टीम के कमजोर प्रदर्शन के लिए बीसीसीआई कोचिंग स्टाफ और खिलाड़ियों के प्रदर्शन की समीक्षा कर सकता है। इसमें मुख्य गौतम गंभीर पर भी गाज गिर सकती है। अनका अनुबंध साल 2027 तक है पर बोर्ड इससे पहले भी कोई कदम उठा सकता है। गंभीर ही नहीं उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर रहे खिलाड़ियों को भी हटाया जा सकता है।

इस सीरीज में कप्तान श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया को लगातार दो टी20 सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है। इससे टीम के प्रदर्शन पर गंभीर सवाल खड़े हो गये हैं। पहले आयरलैंड के खिलाफ भारतीय टीम 2-0 से हारी और अब इंग्लैंड के खिलाफ उसे तीन मैचों में लगातार हार मिली है।इस शर्मनाक प्रदर्शन ने टीम इंडिया की तैयारियों और रणनीति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बोर्ड की इस समीक्षा के पीछे टीम प्रबंधन के कई विवादास्पद फैसले भी हैं। इंग्लैंड दौरे पर लिए गए फैसलों, खासकर अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन को टीम से बाहर किए जाने को लेकर टीम प्रबंधन की काफी आलोचना हो रही है। सैमसन को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच के बाद टीम से बाहर कर दिया गया, जबकि उनकी जगह पारी की शुरुआत के लिए उतारे गए उभरते हुए बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी रन नहीं बना पाये। प्रभाव को सैमसन जैसे अनुभवी की जगह अवसर देने पर भी सवाल उठे है। उनका अनुभव सीमित है और उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपयोगिता साबित नहीं की है।

लगातार मिलती हार और प्रबंधन के फैसलों पर उठते सवालों ने टीम इंडिया के भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। बीसीसीआई इस शर्मनाक प्रदर्शन को हल्के में नहीं ले रही है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़े और कड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं, जिनका सीधा असर टीम की रणनीति, कोचिंग ढांचे और खिलाड़ियों के चयन पर पड़ेगा।

77 साल के हुए गावस्कर को मिली प्रशंसकों और क्रिकेट जगत से बधाईयां

मुम्बई । भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और लिटिल मास्टर के नाम से लोकप्रिय सुनील मनोहर गावस्कर आज 77 साल के हो गये। इस अवसर पर इस महान बल्लेबाज को साथी खिलाड़ियों के साथ ही प्रशंसकों ने भी बधाईयां दी हैं। गावस्कर सत्तर और अस्सी के दशक में भारतीय बल्लेबाजी के आधार थे। उन्होंने इस दौरान कई बड़े रिकार्ड बनाये जिसमें से कई आज भी कायम हैं। गावस्कर ने उस दौर में पारी की शुरुआत करते हुए खतरनाक गेंदबाजों के खिलाफ बिना हेलमेट से खेलते हुए नई नये रिकार्ड बनाकर सभी को हैरान कर दिया था।

गौरतलब है कि गावसकर दस हजार रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बने। इसके अलावा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज डोनाल्ड ब्रैडमैन का 29 शतकों का रिकार्ड तोड़कर एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की थी।गावस्कर ने भारत के लिए 125 टेस्ट मैच खेले। 1971 से 1987 के अंतरराष्ट्रीय करियर के दौरान एक दौर ऐसा भी रहा, जहां उन्होंने भारतीय टीम की ओर से लगातार 106 टेस्ट खेले। इस प्रकार वह भारतीय टीम की ओर से लगातार सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले पहले बल्लेबाज बने। इस सूची में दूसरे नंबर पर राहुल द्रविड़ हैं, जिन्होंने लगातार 93 टेस्ट खेले हैं।

गावस्कर के दौर में वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों के पास कई खतरनाक गेंदबाजों थे। उनका सामना गावस्कर ने अपने साहस, धैर्य, तकनीक और बेहतरीन स्ट्रोक प्ले से किया। जानलेवा बाउंसर्स के उस दौर में गावस्कर बिना हेलमेट के बल्लेबाजी किया करते थे। विकेटों के पतझड़ के बीच ही वह एक छोर पर टिके रहते। देश हो या विदेश हर पिच पर गावस्कर ने अपनी दमदार बल्लेबाजी विपक्षी टीमों के लिए मुश्किल खड़ी की और इसी वजह से वह भारतीय बल्लेबाजी के पहले पोस्टर बॉय माने जाते हैं। गावस्कर का टेस्ट करियर असाधारण और बाद में आने वाले युवाओं के लिए प्रेरणा था. गावस्कर ने अपने करियर में साल 1971 से 1987 तक के अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 125 टेस्ट और 108 वनडे खेले। टेस्ट क्रिकेट में गावस्कर ने 214 पारियों में 51.12 की औसत से 10,122 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने 34 शतक और 45 अर्धशतक बनाये। वहीं एकदिवसीय की 102 पारियों में 1 शतक और 27 अर्धशतक की मदद से उन्होंने 3,092 रन बनाए थे। उनका सबसे अधिक शतक और रनों का रिकार्ड कई साल तक कायम रहा जो बाद में सचिन तेंदुलकर ने तोड़ा। क्रिकेट से संन्यास के बाद गावस्कर कमेंटेटर के तौर पर भी छाये रहे हैं।

मैनचेस्टर सिटी ने क्लब के लिए रखा नया कोचिंग स्टाफ

मैनचेस्टर। इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर सिटी ने मैनेजर एन्जो मारेस्का के लिए नय कोचिंग स्टाफ रखा है। इसमें अर्जेंटीना दिग्गज गोलकीपर रहे विली कैबलेरो को भी शामिल किया गया है। अनुभवी कैबलेरो के आने से मारेस्का के लिए काम काफी आसान होगा। मारेस्का पिछले महीने ही मैनचेस्टर सिटी के नये मैनेजर बने थे। उनका करार क्लब के साथ तीन साल के लिए हैं। मारेस्का की कोचिंग टीम में शामिल होने वाले अन्य प्रमुख चेहरों में रॉबर्टो विटिएलो, डैनी वॉकर, मिशेल डी बर्नार्डिन, मार्कोस अल्वारेज, डेनिस सिल्वा और जेवियर मोलिना शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सेट-पीस कोच जेम्स फ्रेंच और गोलकीपिंग कोच रिचर्ड राइट अपने मौजूदा पदों पर बने रहेंगे, जो टीम में निरंतरता बनाए रखने में मदद करेगा।

अर्जेंटीना के पूर्व अंतरराष्ट्रीय गोलकीपर विली कैबलेरो की वापसी क्लब के प्रशंसकों के लिए खुशी का कारण है। कैबलेरो ने साल उन्होंने 2014 से 2017 तक मैनचेस्टर सिटी के लिए 48 मुकाबले खेले थे और क्लब के लिए लीग कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे थे।

सलीमा टेटे की कप्तानी में एशियाई खेलों में उतरेगी भारतीय महिला हॉकी टीम

नई दिल्ली। हॉकी इंडिया ने शुक्रवार को एशियाई खेलों के लिए 20 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम घोषित कर दी गयी है । टीम की कप्तान अनुभवी मिडफील्डर सलीमा टेटे को सौंपी गयी है। एशियाई खेल 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान के आइची और नागोया में खेले जायेंगे। यह टूर्नामेंट न केवल एशियाई गौरव के लिए बल्कि लांस एजिल्स ओलंपिक 2028 के लिए सीधी योग्यता हासिल करने के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिससे टीम पर अतिरिक्त दबाव और प्रेरणा दोनों है।

युवा लेकिन अनुभवी सलीमा टेटे, जिन्होंने हाल ही में न्यूजीलैंड में एफआईएच नेशंस कप में टीम को अपराजेय रहते हुए खिताब जिताया था और टीम को प्रतिष्ठित प्रो लीग में वापसी कराई थी, एक बार फिर टीम की बागडोर संभालेंगी। उनकी शांत नेतृत्व क्षमता, मैदान पर बेहतरीन समझ और खिलाड़ियों को एकजुट रखने की क्षमता टीम के लिए निर्णायक साबित हुई है। उनका प्रदर्शन न सिर्फ टीम को गति देता है बल्कि युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है।

टीम की घोषणा करते हुए मुख्य कोच जेनेके शोपमैन ने टीम की संरचना पर संतोष व्यक्त किया।

उन्होंने कहा, हमारे पास एक ऐसी टीम है जिसमें युवा प्रतिभा, अनुभवी खिलाड़ी और वरिष्ठ खिलाड़ियों का एक बेहतरीन मिश्रण है। यह संतुलन टीम के लिए लगातार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का मार्ग प्रशस्त करेगा और हम विभिन्न खेल स्थितियों में खुद को ढालने में सक्षम होंगे। शोपमैन ने उम्मीद जताई कि यह मिश्रण टीम को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।

टीम में दो मजबूत और विश्वसनीय गोलकीपर शामिल हैं ङ्क पद्मश्री से सम्मानित अनुभवी सविता पुनिया, जो अपने शानदार बचाव और नेतृत्व के लिए जानी जाती हैं, और युवा बिछू देवी खारीबम। रक्षा पंक्ति में, सुशीला चाणु, इशिका चौधरी और ज्योति को शामिल किया गया है, जिनके साथ एफआईएच नेशंस कप के माध्यम से सीनियर टीम में पदार्पण करने वाली लालह्रुइज़ेली और शिल्पी डबास भी अपनी जगह बनाने में सफल रही हैं, जो मजबूत रक्षात्मक दीवार प्रदान करेंगी।

मध्यपंक्ति का जिम्मा कप्तान सलीमा टेटे के साथ निक्की प्रधान, साक्षी राणा, सुनेलिटा टोप्पो, नेहा और दीपिका सोरेंग संभालेंगी। ये खिलाड़ी गेंद पर नियंत्रण, पासिंग सटीकता और मिडफील्ड से फॉरवर्ड तक संक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। फॉरवर्ड पंक्ति में, लालरेम्सियामी, रुतुजा पिसाल, नवनीत कौर, बलजीत कौर और नेशंस कप में सर्वाधिक छह गोल करने वाली दीपिका शामिल हैं, जो विरोधी टीम के डिफेंस को भेदने और गोल करने की क्षमता रखती हैं।

एशियाई खेलों के लिये भारतीय टीम

गोलकीपर - सविता, बिछू देवी खारीबम

डिफेंडर - इशिका चौधरी, सुशीला चानू, लालथांटलुआंगी, ज्योति , शिल्पी डबास

मिडफील्डर - सलीमा, निक्की प्रधान, साक्षी राणा, सुनेलिटा टोप्पो, नेहा और दीपिका सोरेंग

फॉरवर्ड - लालरेम्सियामी, रूतुजा पिसाल, नवनीत कौर, बलजीत कौर, दीपिका, इशिका, ब्यूटी डुंगडुंग।

फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर लगातार तीसरी बार सेमीफाइनल में प्रवेश किया

लास एंजिल्स । फ्रांस ने फीफा विश्वकप फुटबॉल 2026 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अफ्रीकी देश मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। इस प्रकार फ्रांस ने लगातार तीसरी बार अंतिम चार में जगह बनायी है। यहां अब उसका मुकाबला मंगलवार को डलास में स्पेन या बेल्जियम के बीच मैच की विजेत टीम से होगा। मोरक्को के खिलाफ मैच में दोनों टीमों के बीच कड़ मुकाबला हुआ। फ्रांस ने शुरुआत से ही हमले शुरु कर दिये। वहीं मोरक्को ने भी काफी अच्छी तरह से उन्हें रोका और बीच-बीच में आक्रमकण भी किये। पहले हाफ में दोनों ही टीमें गोल नहीं कर पायीं और 0-0 से मुकाबला बराबरी पर रहा। ।

इसके बाद दूसरे हाफ में फ्रांस ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए तेजी से हमले शुरु कर दिये। इसी कारण मैच के 60वें मिनट में किलियन एम्बापे ने एक गोल दागा। इससे फ्रांस को 1-0 की बढ़त मिल गयी। ये टूर्नामेंट में एम्बापे का यह आठवां गोल था, इससे वह सबसे अधिक गोल के लिए मिलने वाले गोल्डन बूट के दावेदार बने हुए हैं।

गांगुली के नाम दर्ज इस अनूठे कीर्तिमान को शायद ही कोई तोड़ पाये

कोलकाता। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के नाम कई रिकार्ड हैं पर एक ऐसा रिकार्ड उनके नाम है जो शायद ही कभी टूटे। यह रिकॉर्ड है उनके टेस्ट डेब्यू में शतक लगने के बाद अंतिम टेस्ट मैच की आखिरी पारी में गोल्डन डक (पारी की पहली ही गेंद पर आउट होने का)। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में गांगुली एकमात्र ऐसे खिलाड़ी बन गये हैं जिनके नाम यह अनूठा और शायद कभी न टूटने वाला कीर्तिमान दर्ज है।

गांगुली के इस रिकॉर्ड को 'असंभव' इसलिए कहा जाता है, क्योंकि हर क्रिकेटर अपने करियर की शुरुआत धमाकेदार तरीके से करना चाहता है। पहले ही मैच में शतक जड़ना या पांच विकेट लेना, किसी भी खिलाड़ी का सपना होता है। ठीक वैसे ही जैसे गांगुली ने लॉर्ड्स में अपने टेस्ट डेब्यू में शतक लगाकर अपने आगमन का बिगुल बजाया था पर इसके विपरीत, कोई भी खिलाड़ी अपने करियर के अंतिम मैच, खासकर अंतिम पारी में गोल्डन डक नहीं होना चाहेगा। यह स्थिति आकस्मिक और अनचाही होती है। इन दोनों ध्रुवीय विपरीत घटनाओं का एक ही खिलाड़ी के करियर में घटित होना, और वह भी करियर की शुरुआत और अंत में, इसे लगभग असंभव बना देता है। यह संयोग किसी खिलाड़ी द्वारा जानबूझकर दोहराया जाना तो दूर, आकस्मिक रूप से भी घटित हो पाना लगभग संभव नजर नहीं आता है। गांगुली का करियर उपलब्धियों और अनूठे पलों से भरा पड़ा है पर उनका यह डेब्यू शतक और अंतिम पारी गोल्डन डक का रिकॉर्ड एक ऐसा कीर्तिमान है, जो उनके करियर की विशिष्टता को रेखांकित करता

हालांकि, सौरव गांगुली का करियर सिर्फ इस अनोखे रिकॉर्ड तक ही सीमित नहीं है। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में उन्हें सबसे प्रभावशाली कप्तानों में से एक माना जाता है, जिन्होंने टीम को 2000 के दशक के मुश्किल दौर से निकाला और उसे एक आक्रामक व जीतने वाली टीम में बदला। दादा के नाम से मशहूर गांगुली ने अपने नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और कई ऐतिहासिक जीत दर्ज कीं।

बल्लेबाज के तौर पर भी गांगुली ने अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने भारत के लिए 113 टेस्ट मैच खेले, जिनमें 7212 रन बनाए। उनके टेस्ट करियर में 16 शानदार शतक और 35 अर्धशतक शामिल हैं, जो उनकी बल्लेबाजी क्षमता को दिखाते हैं। वनडे क्रिकेट में तो उनका प्रदर्शन और भी बेहतरीन रहा। 311 एकदिवसीय मैचों में गांगुली ने 11363 रन बनाए, जिसमें 22 शतक और 72 अर्धशतक शामिल हैं। बल्लेबाजी के साथ-साथ उन्होंने अपनी धीमी गति की मध्यम तेज गेंदबाजी से भी टीम के लिए अहम योगदान दिया और अपने करियर में 100 वनडे विकेट भी लिए।

प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीव वॉ को भेंट की 20 साल पुरानी तस्वीर

मेलबर्न । भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान शुक्रवार को मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम (एमसीजी) में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और खेल के महानतम दिग्गजों में से एक स्टीव वॉ से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने वॉ को एक बेहद खास उपहार के तौर पर 20 साल पुरानी एक यादगार तस्वीर भेंट की। यह तस्वीर उस समय की है जब स्टीव वॉ गुजरात के दौरे पर थे और मोदी उस समय राज्य के मुख्यमंत्री थे। यह भेंट न सिर्फ पुरानी यादों को ताजा करने वाली थी बल्कि दोनों देशों के बीच साझा क्रिकेट प्रेम और मजबूत होते सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक भी बनी। इस भावुक पल ने क्रिकेट जगत के एक नायक और भारत के एक प्रमुख नेता के बीच के जुड़ाव को फिर से दर्शाया।

एमसीजी में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी उपस्थित थे। इस दौरान अपने संबोधन में मोदी ने वॉ की अद्वितीय नेतृत्व क्षमता और क्रिकेट के मैदान पर उनकी अदम्य भावना की जमकर प्रशंसा की।

गौरतलब है कि 61 वर्षीय स्टीव वॉ का नाम ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफलतम कप्तानों में शामिल है, जिनके दौर में ऑस्ट्रेलियाई टीम को अजेय माना जाता था। उनकी कप्तानी में टीम ने जो रिकॉर्ड बनाये, वे आज भी क्रिकेट इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज हैं। पीएम मोदी द्वारा उन्हें सम्मानित करना उनकी खेल भावना और उपलब्धियों को एक अंतरराष्ट्रीय मान्यता देता है। यह भेंट केवल एक तस्वीर का आदान-प्रदान नहीं था, बल्कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साझा हितों और गहरे होते रिश्तों का एक प्रमाण भी था।

कार्यालय, कृषि उपज मण्डी समिति, गोंगलई,जिला बालाघाट(म.प्र.)

क्रमांक/मंडी/तौलकाटा/2026-27 **बालाघाट, तारीख 10.07.2026**

तृतीय निविदा आमंत्रण सूचना

कृषि उपज मण्डी समिति बालाघाट ई-टेण्डरिंग के माध्यम से स्वंय के व्यय पर बिल्ट ऑपरेट एण्ड ट्रासफर (ग) श्रेणी मडी द्वारा (बी0ओ0टी0) के तहत संरचना की स्थापना एवं संचालन हेतु वार्षिक प्रीमियम के आधार पर निविदा सिस्टम कमांक 2026_MPSAM_520624_1 के अन्तर्गत ऑन लाईन निविदाये दिनांक 22.07.2026 को शाम 3.30 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी निविदाकारों को म0 प्र0 शासन के ई-निविदा के पोर्टल https://mptenders.gov.in पर प्राप्त होगी एवं उक्त निविदा से संबंधित समस्त जानकारी मंडी बोर्ड के पोर्टल www.mpmandiboard.co.in पर भी अवलोकनीय होगी ।

नोट:- आवश्यक होने पर उपरोक्त निविदा सूचना से संबंधित किसी भी प्रकार की संशोधन सूचना अथवा अन्य जानकारी केवल उपरोक्तानुसार पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी ।

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति,
बालाघाट(म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज विभाग) जिला बालाघाट (म.प्र.)

Office e-mail – modgmbal@mp.gov.in

क्रमांक/ 606 /खनिज/2026 बालाघाट दिनांक 06/07/2026

म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 18(1-क) के अंतर्गत उत्खनिपट्टा प्राप्त करनें के लिए,

द्वितीय सूचना

यह सूचित किया जाता है कि, आवेदक निश्चल के. त्रिवेदी पिता किरन कुमार त्रिवेदी निवासी धनसुआ तहसील बलाघाट जिला बालाघाट (म.प्र.) द्वारा उत्खनिपट्टा प्राप्त करने हेतु निम्न क्षेत्र पर ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 04.06.2026 को प्रस्तुत किया गया है। इस क्षेत्र पर आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्रथम सूचना क्रमांक 542 दिनांक 16.06.2026 को प्रकाशित की गई थी। विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तारीख से 15 दिवस तक इस क्षेत्र पर यथास्थिति उत्खनिपट्टा आवेदन ऑनलाईन आमंत्रित किये जाते है। आवेदन ई-खनिज पोर्टल https://ekhanij.mp.gov.in पर प्रस्तुत किये जायेंगे।

आवेदन का संक्षिप्त विवरण

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नंबर	रकबा हे. में	भूमि का प्रकार शासकीय/निजी	खनिज का नाम	रिमार्क
बालाघाट	बालाघाट	धनसुआ	43, 45/1/1	1.000 हे.	निजी	मिट्टी (कवेलू निर्माण)	आवेदक के पक्ष में पूर्व से उत्खनिपट्टा स्वीकृत है। आवेदक द्वारा नवकरण आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

1. उपरोक्त प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदित क्षेत्र के संबंध में अन्य इच्छुक आवेदकों से विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तारीख से आवेदन प्रस्तुत करनें की अंतिम तिथि तक (कार्यालय समय सायं 05:30 बजे तक) ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।
2. यदि प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरांत आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक प्रथम सूचना से प्राप्त आवेदन को शामिल करते हुये 03 अथवा उससे अधिक अन्य आवेदकों के आवेदन पत्र प्राप्त होते है, तो प्रथम आवेदन पत्र एवं प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 21 के तहत् अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जाएगा।
3. यदि प्रकाशित विज्ञप्ति में उल्लेखित आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक 03 से कम आवेदन प्राप्त होते है तो उपरोक्त अवधि में प्राप्त आवेदन पत्र तथा पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति की अवधि के दौरान प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 21 तहत् अधिमान्यता तय करने की आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समक्षा जाएगा।
4. यदि प्रथम एवं द्वितीय प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरांत भी निर्धारित समयावधि में अन्य कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होता है तो प्रथम आवेदक के पक्ष में नियमानुसार खनि रियायत स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा।
5. निर्धारित समयावधि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों को विचार में नही लिया जाएगा।

जी-15451/26

उप संचालक
(खनि प्रशासन)
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

5 महीनों में महाराष्ट्र के 313 किसानों ने की आत्महत्या

सबसे अधिक 105 मामले यवतमाल जिले में दर्ज हुए

मुंबई। महाराष्ट्र के पश्चिम विदर्भ में जनवरी से मई 2026 के बीच पांच जिलों में 313 किसानों ने आत्महत्या की। सबसे अधिक आंकड़े यवतमाल के रहे, जहां 105 किसानों ने आत्महत्या की। इन आंकड़ों ने महाराष्ट्र में खेती-किसानी की मौजूदा स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए किए हैं।

आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम विदर्भ के यवतमाल, अमरावती, अकोला, वाशिम और बुलढाणा जिलों में जनवरी से मई 2026 के दौरान कुल 313 किसान आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए। इनमें यवतमाल सबसे ऊपर रहा, जबकि अमरावती और अकोला में 61-61 किसानों ने आत्महत्या की। इसके अलावा वाशिम में 46 और बुलढाणा में 40 किसानों की आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए। इन मामलों के बीच सबसे चिंताजनक पहलू आत्महत्या प्रभावित परिवारों को मिलने वाली सरकारी सहायता की धीमी प्रक्रिया है। किसानों के पुनर्वास और उनके परिवारों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित वसंतराव नाईक कृषि स्वावलंबन मिशन की ओर से कई प्रभावित परिवारों का अब तक दौरा भी नहीं किया गया है। ऐसे में यह सवाल उठ रहे हैं कि संकट की घड़ी में सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद परिवारों तक समय पर क्यों नहीं पहुंच पा रहा है।

76 परिवारों को सहायता के लिए पात्र माना गया

आंकड़ों के मुताबिक, कुल

313 मामलों में से अब तक केवल 76 परिवारों को सहायता के लिए पात्र माना गया है। वहीं, 56 मामलों को विभिन्न कारणों से अपात्र घोषित कर दिया गया है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि 181 मामलों में अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका है और वे जांच या प्रशासनिक प्रक्रिया में लंबित हैं। इससे प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता मिलने में देरी हो रही है। कृषि क्षेत्र से जुड़े जानकारों का मानना है कि किसानों की आत्महत्या केवल आर्थिक संकट का मामला नहीं है, बल्कि इसमें फसल नुकसान, बढ़ती लागत, कर्ज का बोझ, बाजार में उचित मूल्य न मिलना और प्राकृतिक आपदाओं जैसे कई कारण शामिल होते हैं। ऐसे में प्रभावित परिवारों को समय पर सहायता और योजनाओं का लाभ मिलना बेहद जरूरी है। जनवरी से मई 2026 के सरकारी आंकड़ों ने एक बार फिर यह संकेत दिया है कि पश्चिम विदर्भ में किसानों की स्थिति अब भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। साथ ही, राहत और पुनर्वास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर प्रशासन की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है।

महिला कांग्रेस नेत्री ने अभिनेता अनुपम खेर को समझाया त्रेता और द्वापर का फर्क

नई दिल्ली। अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर जारी बहस के बीच, कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने अभिनेता अनुपम खेर को सनातन धर्म की काल-गणना पर उनकी कथित गलत जानकारी पर आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने अनुपम के वायरल वीडियो का हवाला देकर उन्हें हिंदू धर्म के चार युगों का सटीक कालखंड बताया।

दरअसल, सोशल मीडिया पर अनुपम का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे राम मंदिर के लिए एकत्रित धन में कथित चोरी के संबंध में अपनी बात रख रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, घर में चोरी होती है, तब घर ही लांक्षन नहीं लगाते हैं। जो हुआ वहां गलत हुआ, वहां नहीं होना चाहिए था। मगर सनातन जो है, और राम जी द्वापर युग से हैं, युगों-युगों से हैं। खेर के बयान ने विवाद खड़ा कर दिया क्योंकि हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार भगवान राम का अवतरण त्रेता युग में हुआ था, न कि द्वापर युग में हुआ था।

इस गलत जानकारी पर प्रतिक्रिया देकर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीनेत ने अनुपम खेर को सनातन काल-गणना का विस्तृत पाठ पढ़ाया। उन्होंने लिखा, खेर साहब, सुना आप श्री रामभूमि पर कोई पिक्चर बना रहे हैं। लेकिन उससे पहले त्रेता और द्वापर युग का फर्क समझ लीजिए....फिर सनातन पर प्रवचन दीजिएगा। श्रीनेत ने हिंदू धर्म और शास्त्रों के अनुसार चारों युगों का काल-क्रम और उनकी अवधि बता दी। उन्होंने बताया कि सतयुग पहला और सबसे उत्तम युग है जिसकी अवधि 17,28,000 वर्ष है। इसके बाद त्रेतायुग आता है, जिसकी अवधि 12,96,000 वर्ष है, और इसी युग में भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के रूप में अवतार लिया था। उन्होंने बताया कि तीसरा द्वापरयुग है, जिसकी अवधि 8,64,000 वर्ष है, और इसमें भगवान विष्णु ने श्रीकृष्ण के रूप में अवतार लेकर जीवन के कर्म और धर्म का ज्ञान दिया।

बांकीपुर उपचुनाव बना प्रतिष्ठा की जंग, प्रशांत किशोर के सामने भाजपा ने बदला उम्मीदवार

बांकीपुर । बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव अब बेहद दिलचस्प हो गया है। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने के बाद इस सीट पर मुकाबला और अधिक चर्चित हो गया है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने पहले घोषित उम्मीदवार को बदलते हुए नया प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है। भाजपा ने पहले अभिषेक कुमार को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्होंने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद पार्टी ने त्वरित निर्णय लेते हुए नीरज कुमार सिन्हा को बांकीपुर उपचुनाव का नया उम्मीदवार घोषित किया। पार्टी का कहना है कि चुनाव पूरी मजबूती और संगठनात्मक एकजुटता के साथ लड़ा जाएगा। दूसरी ओर, यह चुनाव प्रशांत किशोर के राजनीतिक जीवन का पहला प्रत्यक्ष चुनाव भी माना जा रहा है। अब तक चुनावी रणनीतिकार के रूप में पहचान बनाने वाले प्रशांत किशोर पहली बार स्वयं जनता के बीच वोट मांग रहे हैं।

यूरेनियम आपूर्ति को लेकर कांग्रेस-भाजपा में जुबानी जंग हुई तेज

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम आपूर्ति के मुद्दे पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद भाजपा सांसद एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने वर्ष 2010 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारत को यूरेनियम बेचने से इनकार किए जाने का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस पर इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया।

दरअसल जयराम रमेश ने अपने एक बयान में कहा था, कि ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारत को यूरेनियम आपूर्ति संभव होना वर्ष 2008 में लागू हुए भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु सहयोग समझौते का परिणाम है। उन्होंने कहा कि इस समझौते की नींव जुलाई 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश के बीच हुई वार्ता से पड़ी थी। उन्होंने यह भी कहा, कि भाजपा ने उस समय संसद और संसद के बाहर इस समझौते का विरोध किया था और अब उसी उपलब्धि का खुद श्रेय लेने का प्रयास कर रही है।

जयराम रमेश के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए संबित पात्रा ने कहा, कि यदि 2008 का समझौता भारत के लिए यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित कर चुका था, तो वर्ष 2010 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यूरेनियम बेचने से इनकार क्यों किया था। उन्होंने कांग्रेस पर चुनिंदा इतिहास प्रस्तुत करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐतिहासिक असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसके बाद दोनों देशों के बीच यूरेनियम आपूर्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। उनके अनुसार, इसी समझौते ने भारत-ऑस्ट्रेलिया परमाणु सहयोग को नई दिशा दी।

इस मुद्दे को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के बीच यह विवाद भारत के असैन्य परमाणु कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के श्रेय को लेकर सामने आया है। कांग्रेस जहां 2008 के भारत-अमेरिका परमाणु समझौते को इसकी आधारशिला बता रही है, वहीं भाजपा का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ 2014 में हुए द्विपक्षीय समझौते के बाद ही यूरेनियम आपूर्ति का रास्ता वास्तविक रूप से खुला। फिलहाल यह मुद्दा राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का विषय बना हुआ है और दोनों दल अपने-अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को प्रमुखता से सामने रख रहे हैं।

सीईओ पद के लिए योग्यता सिर्फ प्रशासन नहीं, रामभक्ति और सेवाभाव भी जरूरी

शिरडी साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के पूर्व प्रमुख का बयान

अयोध्या। राम मंदिर में हाल ही में सामने आए दान चोरी के मामले के बाद अब पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसी क्रम में मंदिर के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति के लिए एक विशेष तीन-सदस्यीय सर्च कमेटी का गठन हुआ है। इस पैनल में शामिल शिरडी साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के पूर्व प्रमुख और रिटायर्ड न्यूक्लियर साइंटिस्ट सुरेश हवारे ने प्रक्रिया और नए सीईओ की योग्यताओं पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उनका मानना है कि दान चोरी के बाद मंदिर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है और राम भक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं, लिहाजा इस पद के चुनाव में बहुत सावधानी बरती जानी है।

हवारे का मानना है कि अयोध्या राम मंदिर का प्रबंधन संभालना देश के किसी भी बड़े कॉर्पोरेट घराने या तिरुपति व शिरडी जैसे विशाल मंदिरों से भी कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है। उन्होंने बताया कि जहां तिरुपति में रोजाना करीब 1 से डेढ़ लाख और शिरडी में 70 से 80 हजार श्रद्धालु आते हैं, वहीं अयोध्या में आम दिनों में ही 2 लाख से ज्यादा भक्त पहुंच रहे हैं, और विशेष उत्सवों पर यह संख्या कई गुना बढ़ती है। इसके अलावा, यह मंदिर 500 साल के लंबे संघर्ष और करोड़ों लोगों की गहरी आस्था का प्रतीक है, जिससे इसकी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। दान चोरी की घटना ने मंदिर की प्रतिष्ठा को ठेस लगी है, इसलिए लोगों का भरोसा वापस जीतना सर्वोपरि है।

पैनल सदस्य हवारे ने स्पष्ट किया कि सर्वोच्च प्रशासनिक पद के लिए केवल एक पेशेवर डिग्री या प्रबंधन पृष्ठभूमि ही काफी नहीं होगी। सबसे पहले, उम्मीदवार में प्रभु राम के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्तों के प्रति सेवा व सम्मान का भाव होना अनिवार्य है। इसके उपरांत, वित्त, मानव संसाधन, आपदा एवं भीड़ नियंत्रण तथा सामग्री प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में व्यावसायिक अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी।

चोरी विवाद के बाद भक्तों का भरोसा बहाल करना इस कमेटी की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हवारे के साथ इस सर्च पैनल में रिटायर्ड जस्टिस प्रदीप कोहली और लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) विष्णुकांत चतुर्वेदी शामिल हैं।

बाढ़ के बीच इंसानियत की मिसाल : एंबुलेंस नहीं पहुंची तो दरवाजे को बनाया स्ट्रेचर, गर्भवती को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया

पालघर। महाराष्ट्र के पालघर जिले में मूसलाधार बारिश और बाढ़ के बीच मानवता की एक प्रेरणादायक मिसाल देखने को मिली। जलभराव के कारण जब एक गर्भवती महिला तक एंबुलेंस नहीं पहुंच सकी, तब गांव के लोगों ने घर का लकड़ी का दरवाजा निकालकर उसे अस्थायी स्ट्रेचर बनाया और सीने तक भरे पानी के बीच महिला को कंधों पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया। समय पर इलाज मिलने से महिला ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया और मां-बेटा दोनों सुरक्षित हैं। जानकारी के अनुसार, हनुमानपाड़ा क्षेत्र की रहने वाली प्रियंका रवि यादव को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। लगातार बारिश से गांव का संपर्क कट चुका था और सभी रास्ते पानी में डूब गए थे। ऐसे में एंबुलेंस का पहुंचना संभव नहीं था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आशा कार्यकर्ता दिव्या घरात, समाजसेवी चेतन गावड़ और स्थानीय ग्रामीण तुरंत मदद के लिए आगे आए। उन्होंने एक घर का दरवाजा निकालकर उसे स्ट्रेचर बनाया और महिला को उस पर लिटाकर सीने तक भरे पानी से गुजरते हुए सफाले ग्रामीण अस्पताल पहुंचाया।

अस्पताल के चिकित्सकों ने समय रहते सुरक्षित प्रसव कराया, जिसके बाद महिला ने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि मां और नवजात दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं। इस साहसिक बचाव अभियान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग ग्रामीणों की सूझबूझ, साहस तथा मानवीय संवेदनशीलता की जमकर सराहना कर रहे हैं। गौरतलब है कि पालघर सहित महाराष्ट्र के कई हिस्से लगातार हो रही भारी बारिश से प्रभावित हैं। कई गांवों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

एक और पार्टी का भाजपा के साथ विलय

भगवा रंग में रंगी दिल्ली में 16 पार्षदों वाली आईवीपी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सियासत में भी आज शुक्रवार को शांत लेकिन बड़ी हलचल हुई। तकरीबन सवा साल पहले आम आदमी पार्टी से बागी होकर अलग दल इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी (आईवीपी) बनाने वाले पार्षदों ने सत्तारुढ़ भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना विलय कर लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा की अगुवाई में आईवीपी के संयोजक मुकेश गोयल, हेमचंद गोयल समेत 16 पार्षदों ने आज बीजेपी में विलय कर लिया। इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के पार्षदों के बीजेपी में विलय करने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि केंद्र, दिल्ली और नगर निगम में बीजेपी सरकार से विकास को तेजद गति मिलेगी। राजधानी दिल्ली को क्लीन, ग्रीन और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए हम सभी मिलकर काम करेंगे। इस अवसर पर दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और विकास कार्यों से प्रभावित होकर ही आईवीपी ने कमल का दामन थामने का फैसला लिया और पार्टी का विलय कर लिया।

अयोध्या विवाद के बाद कर्नाटक मंदिरों में दान पर 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी

अयोध्या। अयोध्या के राम मंदिर में चंदे और दान के कथित गबन के आरोपों के बाद, कर्नाटक की डीके शिवकुमार सरकार ने राज्य के मुजराई विभाग (हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग) के तहत आने वाले सभी मंदिरों में दान और चढ़ावे की गिनती पर चौबीसों घंटे सीसीटीवी निगरानी का आदेश दिया है। सीएम शिवकुमार ने यह महत्वपूर्ण घोषणा कर बताया कि मंदिर के गर्भगृह के पास रखी दान पेटियों को खोलने, पैसे निकालने और उनकी गिनती करने की हर एक प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी।

इस फैसले के तहत, मंदिरों में चढ़ावे से जुड़ी सभी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए इन सीसीटीवी कैमरों के कंट्रोल रूम सीधे जिला एसपी, डिप्टी कमिश्नर या तालुका-स्तर के अधिकारियों के कार्यालयों से जुड़ा होगा। सीएम शिवकुमार ने कहा कि यह कदम अयोध्या में दान के गबन के आरोपों के बाद एहतियाती उपाय के तौर पर उठाया गया है। उन्होंने अयोध्या में हुई बड़ी चोरी को शर्मनाक और अपमानजनकबताकर कहा कि धर्म के नाम पर ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सीसीटीवी कैमरे चौबीसों घंटे चालू रहने चाहिए और मंदिरों के उन सभी हिस्सों को कवर करना चाहिए जहां पैसे इकट्ठा किए और गिने जाते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के कर्नाटक कनेक्शन का दावा करने के बाद यह कदम और भी महत्वपूर्ण हो गया है। शिवकुमार ने कहा कि सरकार अपने राज्य में ऐसी घटनाओं से सतर्क रहने के लिए यह कदम उठा रही है और अयोध्या के आरोपों पर विस्तृत रिपोर्ट मिलने के बाद ही वे टिप्पणी करेंगा।

जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग तेज

फारूक अब्दुल्ला ने 52 नेताओं को पत्र लिख जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का दिया न्योता

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने संसद के आगामी मानसून सत्र के पहले दिन नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का फैसला किया है। पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए देश के 52 प्रमुख राजनीतिक नेताओं, जम्मू-कश्मीर के विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों तथा नागरिक समाज के सदस्यों को पत्र लिखकर आमंत्रित किया है।

आमंत्रित नेताओं में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती, राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के प्रमुख शरद पवार, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के प्रमुख उद्धव ठाकरे, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी, बीआरएस प्रमुख के. चंद्रशेखर राव, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल तथा तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के अध्यक्ष एवं अभिनेता सी. जोसेफ विजय सहित कई अन्य नेता शामिल हैं।

इसके अलावा जम्मू-कश्मीर की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं, धार्मिक प्रतिनिधियों और नागरिक समाज के प्रमुख लोगों को भी प्रदर्शन में शामिल होने का निमंत्रण भेजा गया है। फारूक अब्दुल्ला ने अपने पत्र में कहा कि वे यह अपील केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के रूप में नहीं, बल्कि जम्मू-कश्मीर के लोगों के अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के उद्देश्य से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान हटाने, राज्य के पुनर्गठन और उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के समय केंद्र सरकार ने संसद में उचित समय पर राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन दिया था।

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भरोसा बनाए रखा और वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में भाग लेकर नई सरकार का गठन किया। इसके बावजूद अब तक राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष ने अपने पत्र में कहा कि संघीय ढांचे की मजबूती केवल जम्मू-कश्मीर का नहीं, बल्कि पूरे देश के लोकतांत्रिक ढांचे का विषय है।

एआईएमआईएम को बड़ा झटका : रोशन शेख की बीएमसी सदस्यता रद्द

ओबीसी प्रमाण पत्र अमान्य

मुंबई । ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) में एक और बड़ा झटका लगा है। गोवंडी के वार्ड नंबर 138 से निर्वाचित कॉर्पोरेटर रोशन शेख की सदस्यता को बीएमसी ने तत्काल प्रभाव से रद्द किया है। यह कड़ी कार्रवाई परभणी की जिला जाति प्रमाण पत्र जांच समिति द्वारा उनके अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जाति प्रमाण पत्र को अमान्य और अवैध घोषित करने के बाद हुई है। चूंकि रोशन शेख ने यह चुनाव ओबीसी के लिए आरक्षित सीट से जीता था, इसलिए प्रमाण पत्र अमान्य होते ही उनका निर्वाचन रद्द हुआ। बीएमसी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, परभणी की जिला जाति प्रमाण पत्र जांच समिति ने 27 अप्रैल, 2026 को शेख के ओबीसी जाति प्रमाण पत्र को अमान्य घोषित किया था, जिसके बाद बीएमसी ने उनकी कॉर्पोरेटर सदस्यता खत्म करने की प्रक्रिया शुरू की। मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 की धारा 16(1सी)(ए) के तहत उनकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो गई। बीएमसी ने स्पष्ट किया कि उनकी अयोग्यता 27 अप्रैल, 2026 से प्रभावी मानी जाएगी, जिस तारीख को जाति जांच समिति ने अपना फैसला सुनाया था। यह पहला ऐसा मामला नहीं है। इससे पहले, जून में, एआईएमआईएम के ही एक अन्य कॉर्पोरेटर शमीर रमजान पटेल ने इसी आधार पर अपनी सीट गंवा दी थी। उन्होंने भी गोवंडी के वार्ड 137 से ओबीसी आरक्षित सीट से चुनाव जीता था और उनकी जाति प्रमाण पत्र को भी जांच समिति ने अमान्य घोषित किया था।

संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा

2029 तक तैयार होगी वन नेशन, वन इलेक्शन की रूपरेखा

नई दिल्ली। देश में वन नेशन, वन इलेक्शन लागू करने की दिशा में तैयारियां तेज हो गई हैं। इस मामले पर गठित संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि समिति ऐसी व्यवस्था तैयार करने पर काम कर रही है, जिससे 2029 के लोकसभा चुनाव तक एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था लागू की जा सके। गोवा में समिति की दो दिवसीय बैठक के दौरान पीपी चौधरी ने बताया कि समिति ने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और उनके मंत्रिमंडल के साथ चर्चा की। बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने में क्या चुनौतियां आ सकती हैं और उनका समाधान कैसे निकाला जा सकता है। पीपी चौधरी ने बताया कि समिति अब तक गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गोवा समेत कई राज्यों का दौरा कर चुकी है। इस दौरान संवैधानिक विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, सामाजिक संगठनों और अन्य हितधारकों से राय ली गई।

पीपी चौधरी ने दावा किया कि करीब 99 फीसदी नागरिक संगठनों और अन्य हितधारकों ने वन नेशन, वन इलेक्शन के प्रस्ताव का समर्थन किया है। समिति अब ऐसा मॉडल तैयार करने में जुटी है, जिस पर सभी राजनीतिक दलों की सहमति बन सके। जेपीसी अध्यक्ष ने यह भी कहा कि अगर कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री और राजनीतिक दल स्वेच्छा से तैयार हों तो 2029 से पहले भी कुछ राज्यों के चुनावी चक्र को लोकसभा चुनाव के साथ जोड़ा जा सकता है।

हर साल चुनाव में 7 लाख करोड़ का नुकसान

पीपी चौधरी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति के समक्ष पेश आर्थिक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि बार-बार अलग-अलग चुनाव होने से देश को करीब 7 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान होता है। उनका कहना है कि एक साथ चुनाव होने से न केवल यह नुकसान रुकेगा, बल्कि अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा भी होगा। चौधरी ने कहा कि लगातार चुनाव होने से प्रशासनिक कामकाज भी प्रभावित होता है। चुनाव ड्यूटी में बड़ी संख्या में सरकारी शिक्षकों की तैनाती होने से सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बाधित होती है, जिसका सबसे ज्यादा असर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों पर पड़ता है। पीपी चौधरी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना वाला वन नेशन, वन इलेक्शन देश का एक बड़ा चुनावी सुधार है। इससे शासन व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी, चुनावी खर्च कम होगा और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद मिलेगी।

श्रीनगर हिंसा : एनआईए ने 6 हुर्रियत नेताओं पर दाखिल की चार्जशीट

श्रीनगर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने वर्ष 1996 के श्रीनगर हिंसा मामले में अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के छह वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ जम्मू स्थित विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। एनआईए एजेंसी ने आरोप लगाया है कि इन नेताओं ने एक आतंकी के जनाजे के दौरान भीड़ को उकसाकर पुलिस पर हमला कराया और बड़े पैमाने पर हिंसा भड़काई थी।

एनआईए द्वारा दाखिल चार्जशीट में शब्बीर अहमद शाह, सैयद अली शाह गिलानी, अब्दुल गनी लोन, मोहम्मद याकूब वकील (उर्फ मोहम्मद याकूब वकील), जावेद अहमद मीर और शकील अहमद बख्शी को आरोपी बनाया गया है। इन सभी पर दंड संहिता (आरपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत आपराधिक साजिश, हत्या के प्रयास, दंगा और सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने के आरोप लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, उन पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 13 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। हालांकि, गिलानी, लोन और वकील का निधन हो चुका है, जिसके कारण उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही समाप्त हुई है। फिर भी, एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि जांच के दौरान उनके खिलाफ आपराधिक साजिश और गैरकानूनी जमावड़े में शामिल होने के पर्याप्त सबूत मिले हैं। एनआईए के अनुसार, यह मामला 17 जुलाई 1996 का है, जब श्रीनगर के नाज़ क्रॉसिंग पर मारे गए आतंकी हिलाल अहमद बेग के जनाजे के दौरान इन छह नेताओं ने एक गैरकानूनी भीड़ का नेतृत्व किया था। जांच में सामने आया कि जनाजे के जुलूस में हथियारबंद आतंकी भी भीड़ में शामिल थे, जिन्होंने पुलिसकर्मियों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे।

पद्मेश न्यूज़
शहर | समाज | गांव

/padmeshmedia /padmeshmedia epaper.balaghatexpress.in E-mail: balaghatexpress@gmail.com

न्यूज गैलरी

जहरीली गैस से भरे कुएं में उतरे दो ग्रामीणों की मौत

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। बालाघाट जिले के किरनापुर थाना क्षेत्र के ग्राम पीपरटोला में गुरुवार 09 जुलाई की शाम एक हृदयविदारक हादसे में जहरीली गैस से भरे कुएं में उतरने से दो ग्रामीणों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही जिला होमगार्ड की एसडीईआरएफ एवं क्यूआरटी टीम मौके पर पहुंची और अत्यंत विषम परिस्थितियों में साहसिक रेस्क्यू अभियान चलाकर दोनों शवों को सुरक्षित बाहर निकाला। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पीपरटोला निवासी महेश चौधरी (50 वर्ष) मोटर से पानी नहीं आने पर उसकी जांच करने के लिए कुएं में उतरे थे। कुएं में मौजूद जहरीली गैस और ऑक्सीजन की कमी के कारण वे बेहोश हो गए। उन्हें बचाने के उद्देश्य से युवराज बिसेन (55 वर्ष) भी कुएं में उतर गए, लेकिन वे भी जहरीली गैस की चपेट में आ गए। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। शाम करीब 6:30 बजे घटना की सूचना जिला कंट्रोल रूम को मिली। इसके बाद जिला होमगार्ड कार्यालय से एसडीईआरएफ एवं क्यूआरटी टीम आवश्यक जीवन रक्षक उपकरणों और ब्रीदिंग अपरेटस (बी.ए.) सेट के साथ तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। कुएं में जहरीली गैस होने के कारण बचाव अभियान बेहद जोखिमपूर्ण था। टीम ने सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए बी.ए. सेट पहनकर कुएं में प्रवेश किया और कठिन परिस्थितियों के बीच दोनों शवों को सुरक्षित बाहर निकालकर पुलिस के सुपुर्द किया। रेस्क्यू अभियान का नेतृत्व सहायक उपनिरीक्षक महेश कुमार ने किया। अभियान में हवलदार सुनील कुमार नागपुरे, सैनिक संजय चौधरी, सतीश तोमर, एसडीईआरएफ सैनिक करण सिंह वल्के, विशाल रजक, आशीष खारोल, राजेश धुर्वे तथा वाहन चालक चेतेश्वर राहंगडाले ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टीम की त्वरित कार्रवाई, साहस और कर्तव्यनिष्ठा की स्थानीय लोगों ने सराहना की। जिला होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग ने आमजन से अपील की है कि किसी भी कुएं, सेप्टिक टैंक, बोरवेल या अन्य बंद स्थान में बिना गैस परीक्षण, सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षित बचाव दल की सहायता के प्रवेश न करें। ऐसे स्थानों पर जहरीली गैस एवं ऑक्सीजन की कमी जानलेवा साबित हो सकती है। किसी भी आपात स्थिति में तत्काल पुलिस, होमगार्ड अथवा जिला कंट्रोल रूम को सूचना दें।

बस स्टैंड की अव्यवस्थाओं पर फूटा बस चालकों का गुस्सा, सड़क पर बस खड़ी करने को लेकर यातायात पुलिस से हुआ विवाद

चालकों का सवाल- बस स्टैंड में जगह ही नहीं, तो बस कहां खड़ी करें? मॉडल बस स्टैंड के दावे भी सवालों के घेरे में

सिटी रिपोर्टर।
पद्मेश न्यूज। बालाघाट।

शहर के स्थानीय बस स्टैंड की लगातार बिगड़ती व्यवस्थाओं का असर अब यातायात व्यवस्था पर भी साफ दिखाई देने लगा है। बस स्टैंड परिसर में बसों के खड़े होने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होने और अव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था के कारण बस चालकों को मजबूरन अपनी बसें मुख्य सड़क पर खड़ी करनी पड़ रही हैं। यही स्थिति शुक्रवार 10 जुलाई की शाम करीब 6:30 बजे उस समय देखने को मिली, जब सड़क पर खड़ी बसों को हटाने पहुंचे यातायात पुलिसकर्मियों और बस चालकों के बीच तीखी बहस हो गई। कुछ समय के लिए विवाद और जाम जैसे हालात भी बन गए, हालांकि बाद में समझाइश के बाद बस चालकों ने सड़क से बसें हटा लीं। बस चालकों का कहना था कि वे जानबूझकर सड़क पर बसें खड़ी नहीं करते, बल्कि बस स्टैंड के भीतर इतनी अव्यवस्था है कि वहां बसों को खड़ा करने तक की जगह उपलब्ध नहीं रहती। ऐसे में यदि उन्हें सड़क पर बस खड़ी करनी पड़ती है तो इसके लिए केवल चालक जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि बस स्टैंड की बदहाल व्यवस्था भी जिम्मेदार है।

विवाद के दौरान यातायात पुलिस सड़क पर खड़ी बसों के चालान काटने और नियमों के तहत कार्रवाई करने की बात कह रही थी, जबकि बस चालक इसका विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि जब बस स्टैंड के भीतर ही बसों के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है तो आखिर वे अपनी बसें कहां खड़ी करें। ऐसी परिस्थितियों में यदि पुलिस चालान काटती है तो यह उनके साथ अन्याय होगा। बस चालकों ने बताया कि स्थानीय बस स्टैंड में लंबे समय से अव्यवस्था बनी हुई है। निर्धारित पार्किंग व्यवस्था नहीं होने, समय से पहले बसों के प्रवेश और अव्यवस्थित संचालन के कारण बसों को अंदर खड़ा करने में भारी परेशानी होती है। कई बार तो स्थिति ऐसी बन जाती है कि एक बस के निकलने के लिए दूसरी बसों को हटाना पड़ता है। इसी कारण मुख्य सड़क तक जाम की स्थिति बन जाती है। लंबी दूरी की बसों का संचालन देखने वाले प्रतीक श्रीवास्तव ने भी इस पूरे मामले पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यदि यातायात पुलिस वास्तव में व्यवस्था सुधारना चाहती है तो सबसे पहले बस स्टैंड के अंदर पार्किंग और बस संचालन की व्यवस्था दुरुस्त करनी होगी। उन्होंने कहा कि जब बस स्टैंड के भीतर बसों के खड़े होने की जगह ही नहीं होगी तो चालक मजबूरी में सड़क का सहारा लेंगे। ऐसी स्थिति में केवल चालकों पर कार्रवाई करना समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि बस स्टैंड के अंदर समयबद्ध तरीके से बसों का प्रवेश और निकासी सुनिश्चित की जाए तथा अवैध रूप से खड़ी बसों और अन्य वाहनों पर नियंत्रण रखा जाए तो काफी हद तक व्यवस्था सुधर सकती है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मूल समस्या का समाधान किए बिना केवल चालानी कार्रवाई की गई तो बस संचालक इसका विरोध करेंगे। गौरतलब है कि स्थानीय बस स्टैंड में अव्यवस्था का यह मुद्दा नया नहीं है। पिछले कई महीनों से यातायात पुलिस और नगर पालिका प्रशासन यहां व्यवस्था सुधारने के लिए लगातार निरीक्षण और बैठकें कर रहे हैं। पार्किंग व्यवस्था लागू करने और बस स्टैंड को व्यवस्थित बनाने के कई दावे भी किए गए, लेकिन धरातल पर स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। बस स्टैंड परिसर में बसों के अलावा चौपहिया वाहनों की अव्यवस्थित पार्किंग, अतिक्रमण और पर्याप्त स्थान की कमी के कारण आए दिन जाम की स्थिति बनती है। न्यायालय के समीप स्थित इस बस स्टैंड में शाम के समय यातायात का दबाव बढ़ने पर हालात और भी गंभीर हो जाते हैं। ऐसे में यात्रियों, बस चालकों और आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ समय पहले स्थानीय प्रशासन द्वारा इस बस स्टैंड को मॉडल बस स्टैंड के रूप में विकसित करने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक उस दिशा में कोई ठोस प्रगति दिखाई नहीं दी है। वर्तमान स्थिति में बस स्टैंड मूलभूत सुविधाओं और सुव्यवस्थित संचालन के अभाव से जूझ रहा है। फिलहाल शुक्रवार शाम हुए विवाद के बाद मामला शांत तो हो गया, लेकिन बस चालकों का कहना है कि जब तक बस स्टैंड की व्यवस्थाओं में स्थायी सुधार नहीं किया जाएगा, तब तक इस तरह की स्थिति बार-बार बनती रहेगी। अब देखना होगा कि नगर पालिका प्रशासन और यातायात पुलिस बस स्टैंड की अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए क्या ठोस कदम उठाते हैं।

डीजल से भरा टैंकर पलटा, ग्रामीणों में डीजल लूटने की मची होड़

चालक परिचालक घायल, कटंगी अस्पताल में किया गया भर्ती
कटंगी के खिड़कीघाट का मामला, मामले की जांच में जुटी पुलिस

पद्मेश न्यूज ।कटंगी। कटंगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खिड़की घाट मार्ग पर शुक्रवार की सुबह उस वक्त डीजल लूटने की होड़ मच गई,जब जबलपुर से वारासिवनी के लिए आ रहा एक डीजल का टैंकर, खिड़की घाट के समीप अनियंत्रित होकर पलट गया। इस घटना में डीजल टैंकर के चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।घायलों की पहचान टैंकर चालक अशोक यादव और परिचालक बबलू यादव के रूप में हुई है। दुर्घटना के बाद कुछ जागरूक राहगीरों ने एंबुलेंस को सूचना दी। दोनों घायलों को कटंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

अचानक ब्रेक फेल होना बताई जा रही वजह

हालांकि जबलपुर से वारासिवनी के लिए आ रहा यह डीजल टैंकर कटंगी के खिड़कीघाट मार्ग पर कैसे पलट गया, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है।लेकिन हादसे की वजह ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार टैंकर क्रमांक एमएच 17 एचए 3564 जबलपुर से ईंधन लेकर वारासिवनी की ओर आ रहा था।जो कटंगी के खिड़कीघाट मार्ग से होता हुआ वारासिवनी की तरफ ब? रहा था।बताया जा रहा है कि खिड़कीघाट के खतरनाक मोड़ पर अचानक टैंकर के ब्रेक फेल हो गए।ड्राइवर ने सुझबूझ से वाहन को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन ढलान और मोड़ के कारण टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया।

डीजल लूटने की मची होड़, पुलिस ने संभाला मोर्चा

उधर टैंकर पलटने से लगभग 15000 लीटर डीजल सड़क पर बह गया।यह जानकारी जैसे ही स्थानीय ग्रामीणों को लगी वैसे ही वे अपनी जान जोखिम में डालकर कुप्पी डब्बे और बाल्टिया लेकर मौके पर पहुंच गए और वहां डीजल लूटने की होड़ मच गई।उधर टैंकर के पलटने से उसका मुख्य चैंबर क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे डीजल सड़क और आसपास के गड्ढों में फैल गया। जिसे स्थानीय ग्रामीणों में अपनी-अपनी डपकियो, डब्बो व बर्तनों में भरकर ले जा लिया।जहां ज्वलनशील पदार्थ होने के बावजूद ग्रामीण बड़े हादसे के डर को नजरअंदाज करते हुए डीजल लूटते रहे। पुलिस और प्रशासन के पहुंचने से पहले ने मौके पर पहुंचकर डीजल लूट रहे ग्रामीणों को

तक लोग जान की परवाह किए बिना ईंधन को लूटते रहे।उक्त जानकारी मिलने पर पुलिस खदेड़ा और सुरक्षा के लिए इलाके की घेराबंदी की है।

आवश्यकता है
डाटा एण्ट्री ऑपरेटर
की आवश्यकता है
संपर्क करें-पद्मेश सिटी केबल
काली पुतली चौक, बालाघाट

AICTE भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं RGPV & DTE भोपाल से सम्बध्द
सतपुड़ा कॉलेज ऑफ
इंजीनियरिंग एण्ड पॉलिटेक्निक
बी.टेक. पॉलिटेक्निक JOB SAHI
• कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग
• माईनिंग इंजीनियरिंग
• सिविल इंजीनियरिंग
• मैकेनिकल इंजीनियरिंग
• इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
ADMISSION OPEN
नई शिक्षा नीति के तहत किसी भी ब्रांच से डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों का Lateral Entry द्वारा बी.टेक. के द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश
सतपुड़ा कैम्पस, लालबर्रा रोड, गर्रा-बालाघाट
6262604111, 9425836824 www.satpudaengineeringcollege.com

भारत वर्ष में नं. 1, मध्यप्रदेश में भी नं. 1
भारत वर्ष की पहली 9 इंच में डीबीटी में उपलब्ध
(भारत सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त)
रॉइडान व वॉकबिहाइड दोनो
LC09W
Kaira
तकनीक जापानी सोच हिन्दुस्तानी
बुकिंग पर सीडर ट्रे फर्मा फ्री या 20000 हजार की छूट
बगैर अनुदान के 2.40/-
अनुदान होने पर 1.50/-
Kaira RTP 4 Row
साई ट्रेक्टर्स/ के.के. इंटरप्राईजेस
• मोती तालाब रोड, नर्मदा नगर बालाघाट
• पटेल ठोला, बरपाट (सिवनी)
8770334649
8120467192

PADMESH X FIBERNET Connecting the Unconnected.
Taking people ahead with.
FIBER CONNECTION.
Follow us on @padmeshxfibernet 08045777666 www.padmeshdigital.in

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक उमेश बागरेचा द्वारा पद्मेश पब्लिकेशन, वार्ड नं.9, गुजरी चौक, बालाघाट (म.प्र.) से मुद्रित कराकर दैनिक बालाघाट एक्सप्रेस कार्यालय, काली पुतली चौक, बालाघाट(म.प्र.) से प्रकाशित,
प्रधान संपादक : उमेश बागरेचा, मो.नं. :9425138710, , ई-मेल- balaghatexpress@gmail.com पंजीयन क्रं. MPHIN/2009/32311, न्यायालयीन क्षेत्राधिकार बालाघाट